Follow us on: @TheDailyPioneer facebook.com/dailypioneer instagram.com/dailypioneer/

पायनियर

Established 1865

रायपुर, लखनऊ और नई दिल्ली से प्रकाशित

www.dailypioneer.com

RNI NO. CHHHIN/2016/70655
वर्ष-10, अंक-109
रायपुर, मंगलवार 09 दिसम्बर 2025
पृष्ठ-12, मूल्य ₹ 3.00

क्विक न्यूज

उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री की 2023 में वरुणा सीट पर चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की 2023 में वरुणा विधानसभा क्षेत्र पर चुनावी जीत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के. शंकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सिद्धारमैया से जवाब मांगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसी साल अप्रैल में इस याचिका को खारिज कर दिया था।

जहाज का संकट मोदी सरकार की एकाधिकार वाली नीति का परिणाम : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक कंपनी की हठधर्मिता के कारण आज पूरे देश में

जहाजों की उड़ान का संकट पैदा हो गया है। यह मोदी सरकार के एक ही कंपनी को एकाधिकार देने की नीति परिणाम है। देश में जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी सरकार देश के हर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निजी उद्योगपतियो के एकाधिकार में सौंप दिया है। प्रतिस्पर्धा में मौजूद तत्कालीन अन्य विमानन कंपनियो की उपेक्षा की गयी है। मोदी सरकार में सरकारी विमान कंपनी इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया। 2014 के पहले देश में 5 विमानन कंपनियां काम करती थी, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद 97 प्रतिशत भारतीय उड़ानो पर केवल दो कंपनियों का कब्जा है, उसमे भी लगभग 70 प्रतिशत अकेले इंडिगो का है।

बस दुर्घटना में अध्यापिका सहित तीन की मौत, दस से अधिक घायल

हनुमागनढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक अध्यापिका सहित तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हादसा मेगा हाइवे पर मानकसर गांव के पास जुनेजा होटल के सामने सुबह करीब नौ हुआ जब हनुमानगढ़ जंक्शन से हरियाणा के डबवाली जा रही निजी बस के चालक ने अचानक सामने आए एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की।

एमएमसी जोन नक्सलमुक्तः सीसी मेंबर समेत 3 करोड़ के 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर

पायनियर संवाददाता < राजनांदगांव
www.dailypioneer.com

महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन के नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरूण देव गौतम के समक्ष सरेंडर किया। सबसे बड़ी बात सरेंडर करने वाले नक्सलियों में बड़ा कैडर रामधेर मझी भी शामिल है, जो सेंट्रल एरिया कमेटी का मेंबर था। उस पर 1 करोड़ 5 लाख का ईनाम घोषित था। वहीं सभी 12 नक्सलियों पर 2 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इस सरेंडर को लेकर सीएम विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अरूण गौतम ने संयुक्त रूप से पत्रकारवार्ता की। बताया गया कि इन नक्सलियों के सरेंडर के बाद से एमएमसी जोन तकरीबन समाप्त हो गया है, कुछ छोटे कैडर वहां हो सकते हैं। उनसे भी अपील की गई कि वे बंदूक छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े।

नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष राज्य के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य–31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन की दिशा में छत्तीसगढ़ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और यह अब अंतिम सांसें गिन रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 500 से अधिक माओवादी मुठभेड़ों में न्यूट्रलाइज हुए, जबकि 4,000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी दी, जो नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के पराक्रम से बस्तर में दशकों से जमी हिंसा के विरुद्ध निर्णायक बढ़त मिली है।

इसके बाद यह भी स्पष्ट कहा गया कि यदि वे पुनर्वास की ओर नहीं लौटते हैं तो फोर्स का उन्हें सामना करना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार सभी नक्सली रविवार देर रात जंगल के रास्ते से खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना पहुंचे। इसके बाद उन्हें सुबह राजनांदगांव लाया गया। माओवादियों ने तीन एके 47, तीन इंसास सहित 10 हथियार सहित विस्फोटक सामग्री, वाकी टाकी पुलिस को सौंपे हैं। दो सदस्यों के पास कोई हथियार नहीं थे। रामधेर लम्बे समय से एमएमसी जोन के उत्तरी क्षेत्र में छिपा हुआ था। 26 नवंबर को गोंदिया में आत्मसमर्पण करने वाले जोन के प्रवक्ता और एसजेडएमसी विकास नागपुरे उर्फ अनंत ने रामधेर से सम्पर्क में न होने की बात कही थी। हालांकि, उसने यह भी कहा था कि शायद उन्हें समर्पण के लिए वक्त चाहिए। इनके सरेंडर के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब एमएमसी जोन को पूरी तरह से नक्सलमुक्त माना जा सकता है। इस दौरान सीएम साय, गृहमंत्री शर्मा, डीजीपी गौतम, एडीजी विवेकानंद, आईजी अभिषेक शांडिल्य, एसपी अंकिता शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

ये नक्सली लौटे मुख्यधारा में, हथियार भी लेकर आए

समर्पण करने वालों में रामधेर मझी सीसीएम- एके47, चंदू उसेंडी डीवीसीएम 30 कार्बाइन, ललिता डीवीसीएम, जानकी डीवीसीएम - इंसास, प्रेम डीवीसीएम -एके47, रामसिंह दादा एसीएम 303, सुखेश पोटूम एसीएम -एके47, लक्ष्मी पीएम इंसास, शीला पीएम इंसास, सागर पीएम एसएलआर, कविता पीएम- 303 और योगिता पीएम शामिल है।

इंडिगो ने डीजीसीए से कहा- इस समय सटीक कारण बताना संभव नहीं

पायनियर संवाददाता < नयी दिल्ली
www.dailypioneer.com

पांच दिन में हजारों उड़ानें रद्द करने और यात्रियों को हुई परेशानी पर निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने कहा है कि इस संकट का सटीक कारण बताना इस समय संभव नहीं है। पूरे मामले पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के कारण बताओ नोटिस के जवाब में इंडिगो ने और समय मांगते हुए कहा कि परिचालन की जटिलता और व्यापकता को देखते हुए व्यावहारिक तौर पर सटीक कारण बताना इस समय संभव नहीं है। उसने कहा है कि डीजीसीए के मैनुअल में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है और 'मूल कारण के विश्लेषण' के लिए उसे और समय दिया जाना चाहिये। नियामक ने एक प्रेस नोट में बताया कि एयरलाइंस ने कहा है कि विश्लेषण पूरा होने के बाद नियामक के साथ साझा किया जायेगा। डीजीसीए ने 06 दिसंबर को इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 07 दिसंबर तक जवाब मांगा था। बाद में एयरलाइंस के अनुरोध पर उसे एक दिन का और समय दिया गया था। भेजे गये जवाब पर इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एलबर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

आजादी का प्रेरणास्रोत रहा वंदे मातरम् आजाद भारत का भी है विजन : पीएम मोदी

पायनियर संवाददाता < नयी दिल्ली
www.dailypioneer.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आजादी के दीवानों का मंत्र बने 'वंदे मातरम' गीत की गूंज ने न सिर्फ अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी और पूरे भारत में उत्साह का ऐसा माहौल तैयार किया था जो न सिर्फ स्वतंत्रता का मंत्र बना बल्कि आजाद भारत के लिए भी विजन बनकर सामने आया। मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् गीत के 150वें वर्ष पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह गीत आजादी का उद्घार बन गया था और हर देशवासी इस गीत से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इस गीत से देश में बने नये माहौल को देखकर अंग्रेज बौखला गये थे इसलिए उन्होंने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे गाने को अपराध मानकर लोगों पर जुल्म ढहाने शुरु कर दिए थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् का एक ऐसा कालखंड रहा है जिसमें इतिहास के कई प्रेरक उदाहरण देश के सामने मौजूद है। वंदे मातरम् के जब सौ साल पूरे हो गये थे तो उस समय इसकी शताब्दी का उत्तम पर्व मनाया जाना था लेकिन तब देश को आपातकाल में धकेल दिया गया था और देश के नागरिकों का गला घोंटा जा रहा था। देश की आजादी के आंदोलन को ऊजा देने वाले वंदे मातरम् के सौ साल पूरे होने के समय देश को आपाताकाल के काले कालखंड में धकेल दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा वंदे मातरम् पर चर्चा में कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है क्योंकि इसी गीत से मिली प्रेरणा के कारण हम सब यहां बैठे हैं और यह हम सबके लिए पावन पर्व है। वंदे मातरम् की भावना के साथ देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गयी और इस गीत के भाव में आजादी के दीवाने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् गीत ऐसे समय लिखा गया था जब अंग्रेज सल्तनत 1857 की क्रांति से बौखलाई थी और देश की महान विभूतियों को मजबूर किया जा रहा था। जब चारों तरफ वंदे मातरम् की आवाज गूंज रही थी, देश को गुलाम बनाए रखने के लिए बड़ा षडयंत्र चल रहा था तो उस स्थिति को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चुनौती दे रहे थे। उन्होंने 1882 में 'आनंदमठ' उपन्यास की रचना की तो देश में आजादी की अलख जगा रहा वंदे मातरम् गीत इसमें रखा गया। देश के लोगों में जो भाव था, जो संस्कृति थी उसे वंदे मातरम् गीत के जरिए देश को बहुत बड़ी सौगात दी गई। वंदे मातरम् केवल आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, मात्र अंग्रेजों को भगाने का मंत्र नहीं था बल्कि यह इस भूमि को बेड़ियों से मुक्ति दिलाने की एक पवित्र जंग भी थी। प्रधानमंत्री ने कहा वंदे मातरम् देश की प्राचीन पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक अवतार है। बंकिमदा ने जब वंदे मातरम् की रचना की थी तो यह गीत स्वाभाविक रूप से आजादी की लड़ाई का स्वर बना और पूरे देश के आजादी के योद्धाओं को मुग्ध करने का मंत्र बन गया। वंदे मातरम् हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा थी, इसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत की दृष्टि भी थी। इस गीत के हर शब्द देशवासियों को हौसला देने वाले थे।

उच्च न्यायालय भवन में बम की अफ़वाह से अफरा-तफरी

जयपुर/वार्ता। जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय भवन में बम होने की सूचना से न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुँचकर पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि प्रारंभिक जाँच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, और पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि गलत सूचना किसने दी और इसके पीछे क्या मकसद था। इससे उच्च न्यायालय परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और मुवक्किलों में अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके चलते अदालतों में कामकाज काफी समय के लिये स्थगित रहा। इससे पहले पांच दिसम्बर को भी जयपुर में इसी तरह की बम अफ़्वाह ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था, जिसके चलते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को पूरे परिसर की तलाशी लेनी पड़ी थी। लगातार दूसरी बार ऐसी घटना होने से सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्क हो गई हैं। उधर पुलिस ने कहा है कि इस तरह की फर्ज़ी सूचनाएँ न केवल सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती हैं बल्कि आम नागरिकों में भय का माहौल पैदा करती हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय के वकीलों ने बताया कि पिछले शुक्रवार को भी ऐसी ही घटना हुई थी। आज पूर्वाह्न 11 बजे फिर बम की धमकी की सूचना मिली। उच्च न्यायालय में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई होनी थी। वकीलों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। इस तरह की अफवाहें प्रशासन और पुलिस के लिए एक चुनौती है। अगर ऐसा रोज होता रहा तो न्यायालय का काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बार काउंसिल चुनावों में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया

पायनियर संवाददाता < नई दिल्ली
www.dailypioneer.com

उच्चतम न्यायालय ने कानूनी पेशे में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़े कदम के तहत कहा कि जिन राज्यों की बार काउंसिलों में चुनाव अभी अधिसूचित नहीं हुये हैं, उनमें 30 प्रतिशत सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि मौजूदा चुनाव प्रक्रिया के लिए 20 प्रतिशत सीटें चुनी हुई महिला सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी और 10 प्रतिशत सह विकल्प के माध्यम से भरी जायेंगी। न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में महिला उम्मीदवारों की संख्या कम है, वहां सह विकल्प का प्रस्ताव उसके सामने रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि उन छह राज्य बार काउंसिल में कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, जहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और छत्तीसगढ़ हैं। इसके बावजूद, पीठ ने इन राज्यों के अधिवक्ता मतदाताओं से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं को उनके वोटों के माध्यम से पर्याप्त और सार्थक प्रतिनिधित्व मिले।

पूर्व तटीय रेलवे फंसे हुए यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा

पायनियर संवाददाता < भुवनेश्वर
www.dailypioneer.com

इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) मुंबई, नयी दिल्ली, बेंगलुरु और हावड़ा क्षेत्रों की ओर कुछ विशेष ट्रेनें चलाने के साथ ही मौजूदा संचालित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगायेगा। ईसीओआर के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष ट्रेन 08401 भुवनेश्वर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल 07 दिसंबर को भुवनेश्वर से, 08402 लोकमान्य तिलक टर्मिनस - संबलपुर स्पेशल 09 दिसंबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से , 08403 पुरी - आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 08 दिसंबर को पुरी से , 08404 आनंद विहार टर्मिनल - भुवनेश्वर स्पेशल 09 दिसंबर को आनंद विहार टर्मिनल से , 08501 विशाखापत्तनम - एसएमवीबी बेंगलुरु स्पेशल 08 दिसंबर को विशाखापत्तनम से तथा 08502 एसएमवीबी बेंगलुरु - विशाखापत्तनम स्पेशल 09 दिसंबर को एसएमवीबी बेंगलुरु से रवाना होगी। इसके अलावा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त एसी कोच जोड़े गए हैं।

उपबंधों के पुनरीक्षण पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय

जमीनों के गाइडलाइन दर को लेकर सरकार अपना फैसला ले सकती है वापस

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमीनों की गाईडलाइन दर में रिकार्ड बढ़ोत्तरी की है। जिसको लेकर चारों तरफ विरोध हो रहा है। चौतरफा विरोध के चलते प्रदेश में गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर व्यापक परीक्षण करने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। अब पुनः पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान एवं कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान भी हटा दिया गया है। अब मूल्यांकन बिल्ट-अप एरिया के आधार पर किया जाएगा। यह प्रावधान मध्यप्रदेश शासन के समय से लागू था, जिसे बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी और शहरी भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान भी लागू किए हैं। अब बेसमेंट और प्रथम तल पर 10 प्रतिशत तथा द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस निर्णय से मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर फ्लैट और व्यावसायिक स्थान मिलने में मदद मिलेगी। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए 25 प्रतिशत कमी के साथ भूखंड की दरों का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर की दूरी का आकलन मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित हिस्से से किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति के आधार पर अधिक न्यायसंगत मूल्यांकन संभव होगा। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को यह भी निर्देशित किया है कि हाल ही मंय दरों में वृद्धि के बाद प्राप्त आपत्तियों, ज्ञापनों और सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों का विश्लेषण कर बोर्ड आगामी गाइडलाइन दरों पर अंतिम निर्णय लेगा। इन सभी निर्णयों को तत्काल प्रभाव से लागू घोषित किया गया है, जिससे राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, पारदर्शिता और किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। हालांकि वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि जनता के सुझावों के अनुरूप उचित निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल वर्तमान में निर्मित हालातों को देखते हुए सरकार अपना फैसला वापस ले सकती है।

जबरदस्ती थोपे गए नियम को वापस लिया गयाः भूपेश

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा है कि गाइडलाइन दरों में अभी सुधार कहां हुआ? जब तक अनाप-शनाप बढ़ाई

गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा। भूपेश बघेल ने कहा है कि यह सुधार सतही है और जनता को बहुत कम राहत देने वाला है। दरअसल अभी गाइडलाइन की दरों में सुधार नहीं हुआ है। बस एक जबरदस्ती थोपे गए नियम को वापस लिया गया है। थोड़े बहुत और परिवर्तन हुए हैं वे बहुत असरकारी नहीं है। जब तक अनापशनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा। जनता पर प्रॉपर्टी टैक्स का जो बोझ आने वाला है वह तो अभी बरकरार दिखता है।

भारत ने खालिस्तान समर्थक संगठन पर प्रतिबंध के ब्रिटेन के निर्णय का स्वागत किया

नयी दिल्ली। भारत ने खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा के साथ कथित संबंधों के लिए एक ब्रिटिश सिख व्यवसायी और उससे जुड़े एक गुट पर ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में कहा कि ब्रिटेन सरकार द्वारा उठाए गए कदम आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, हम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं, जो आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करते हैं, और गैर-कानूनी वित्तीय प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को रोकने में मदद करते हैं।

डीजीसीए में खाली पड़े हैं 49 प्रतिशत पद, मंत्री बोले कामकाज पर असर नहीं

पायनियर संवाददाता < नयी दिल्ली
www.dailypioneer.com

देश के विमानन क्षेत्र में नियमन के लिए जिम्मेदार नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में 49 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि डीजीसीए में कुल 1,630 पद स्वीकृत हैं जिनमें 794 (49 प्रतिशत) खाली पड़े हैं। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) में 598 स्वीकृत पदों में से 203 रिक्त हैं। सरकार के जवाब में कहा गया है कि देश भर में सरकारी हवाई अड्डों के प्रबंधन और भारतीय हवाई सीमा में एयर नेविगेशन की सेवा प्रदान करने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में 25,730 स्वीकृत पदों में से 9,771 खाली हैं। सभी हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एटीसीओ (एटीसी अधिकारियों) के कुल 5,537 पद स्वीकृत हैं। इनमें भी 1,260 पद खाली पड़े हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा, (कर्मचारियों/अधिकारियों) की कमी की वजह से डीजीसीए का कामकाज प्रभावित नहीं हो रहा है। एटीसीओ के रिक्त पदों के कारण विमानन सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने सदन को बताया कि डीजीसीए ने पिछले तीन साल में 441 पद सृजित किये हैं। रिक्तियों को भरने के लिए उठाये गये कदमों के तहत पिछले चार महीने में 22 अधिकारी डीजीसीए में शामिल हुए हैं।

सैनिक स्कूल में ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी

पायनियर संवाददाता ◄ गोरखपुर
www.dailypioneer.com

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस स्कूल प्रोजेक्ट का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराया गया है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर जीबीआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाले आयोजित कार्यम में मुख्यमंत्री इस महान सैन्य अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ जनरल रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर फंड से बने राजकीय आईटीआई का भी लोकार्पण करेंगे। सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धाजंलि अर्पण और उनकी याद में बनाए गए ऑडिटोरियम के उद्घाटन का कार्यम मंगलवार सुबह 10 बजे से होगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेड़ा, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव मंजीत नेगी और जनरल बिपिन रावत की सुपुत्री कृतिका और तारिणी रावत की भी उपस्थिति रहेगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर के सैनिक स्कूल में निर्मित जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम की क्षमता 1000 से अधिक लोगों के बैठने की है। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलक कि पिपरौली क्षेत्र के ग्राम नरकटहा में बने राजकीय आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण करेंगे। इस आईटीआई का निर्माण पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर ;कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड्ड से 16 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। पिपरौली क्षेत्र का आईटीआई गोरखपुर का 11वां और पीपीपी मोड में संचालित होने वाला तीसरा राजकीय आईटीआई होगा।

झारखंड में रांची के तीनों बस टर्मिनल 48.72 करोड़ की लागत से आकर्षक बनेंगे

एजेंसी ◄ रांची
www.dailypioneer.com

राजधानी रांची के तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों आइटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगढ़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के क्रम में इन सभी टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इस कार्य को आरंभ करने के लिए विभागीय मंत्री दिव्य कुमार के निर्देश पर निविदा निकाल दी गयी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कुल 48.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति पहले ही दे चुके है। इसमें आइटीआई बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ और बिरसा मुंडा बस स्टैंड के लिए 3.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है है। मंत्री ने विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार को जुडको के माध्यम से निविदा के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है। आइटीआई बस स्टैंड बनेगा। अत्याधुनिक एवं आकर्षक वर्तमान में यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाओं वाले इस बस स्टैंड को आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। यह तीन एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा, जिसमें 2330 वर्गमीटर ग्राउंड फ्लोर और 880 वर्गमीटर प्रथम तल पर टर्मिनल भवन होगा।बसों के परिचालन के लिए 13 बस वे बनाया जाएगा। 35 बसों के लिए स्टैंड बाई पार्किंग की सुविधा रहेगी। भूतल पर ड्राइवर कैंटीन, मेंटेनेंस शेड, गार्ड रूम, स्लाइडिंग प्रवेश द्वार, वातानिकुलित प्रतीक्षालय, कार, फूड कियोस्क, परिवहन कार्यालय, कैफेटेरिया, महिला एवं पुरुष शौचालय, ऑटो और ई-रिक्शा पार्किंग की सुविधा होगी।

यूपी में मखाना विकास योजना की शुरुआत 158 लाख रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत

पायनियर संवाददाता ◄ लखनऊ
www.dailypioneer.com

उत्तर प्रदेश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन के बाद प्रथम चरण में देश के 10 राज्यों में यह योजना लागू की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। प्रदेश में इस योजना का यिान्वयन उद्यान विभाग द्वारा किया जाएगा। लखनऊ स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होने कहा कि यह योजना किसानों को उच्च मूल्य वाली फसल से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी और उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तैयार कार्ययोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और 158 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। इस बजट से मखाना खेती हेतु तालाबों का चयन व निर्माण, किसानों का विशेष प्रशिक्षण, बायर-सेलर मीट, मखाना पवेलियन के माध्यम से प्रचार-प्रसार, व्यापारियों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, जनपद व राज्य स्तरीय सेमिनार जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मखाना स्थापित करने की दिशा में भी कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे अनुसंधान और तकनीक आधारित उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उद्यान मंत्री ने कहा कि मखाना औषधीय गुणों और उच्च बाजार मूल्य के कारण सुपरफूड के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब तक इसकी खेती मुख्यतः बिहार में होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु और जलभराव वाली भूमि इस फसल के अनुकूल है। उन्होंने कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, वाराणसी और बस्ती को मखाना उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त जनपद बताया गया। जहां सिंघाड़े की खेती होती है, वहाँ मखाना उत्पादन भी सफल रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में मखाना क्षेत्र विस्तार, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन कार्यों को और व्यापक स्तर पर शुरू किया जाएगा। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मंत्री ने आलू निकासी को लेकर विपक्ष की आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी।

रुपये में जारी गिरावट से लुढ़के शेयर बाजार

एजेंसी ◄ मुंबई
www.dailypioneer.com

डॉलर के मुकाबले रुपये में जारी गिरावट से घरेलू शेयर बाजारों में निवेश धारणा प्रभावित हुई और दोनों प्रमुख सूचकांक करीब दो सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 609.68 अंक (0.71 प्रतिशत) गिरकर 85,102.69 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 225.90 अंक यानी 0.86 प्रतिशत नीचे 25,960.55 अंक पर आ गया। यह दोनों का इस साल 25 नवंबर के बाद का निचला स्तर है। रुपये में भी गिरावट जारी रहने से शेयर बाजारों में निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। इस कारण इस महीने अब तक बाजारों में बिकवाली हावी रही है, विशेषकर मझौली और छोटी कंपनियों में। शेयर बाजारों में चौतरफा बिकवाली देखी गयी। मझौली और छोटी कंपनियों में ज्यादा गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.71 प्रतिशत और स्मॉलकैप 100 सूचकांक 2.61 प्रतिशत टूट गया। एनएसई में रियलिटी सेक्टर का सूचकांक करीब 3.53 प्रतिशत गिर गया। सार्वजनिक बैंकों के सूचकांक में भी लगभग 2.81 फीसदी की गिरावट रही। रसायन, धातु, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, स्वास्थ्य, फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी समूहों के सूचकांक भी एक से दो प्रतिशत के बीच गिरे। एनएसई में कुल 3,246 कंपनियों के शेयरों में आज कारोबार हुआ जिनमें 2,579 के शेयर लाल निशान में और 579 के हरे निशान में बंद हुए। अन्य 88 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित रहे। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 26 के शेयर गिर गये। बीईएल में 4.97 प्रतिशत की गिरावट रही। इटरनल का शेयर 2.45 प्रतिशत, ट्रेंट का 2.35, टाटा स्टील का 2.18 और बजाज फाइनेंस का 2.12 प्रतिशत टूट गया। अडानी पोट्‌र्स में 1.94 फीसदी, बजाज फिनसर्व में 1.77, पावर ग्रिड में 1.69, भारतीय स्टेट बैंक में 1.58 और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में 1.53 प्रतिशत की गिरावट रही। एशियन पेंट्स का शेयर 1.39 फीसदी, टाइटन का 1.29, एनटीपीसी का 1.22, कोटक महिंद्रा बैंक का 1.07, हिंदुस्तान यूनीलिवर तथा एलएंडटी दोनों का 1.05 और भारती एयरटेल का 1.03 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, आईटीसी, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और सनफार्मा के शेयरों में भी गिरावट रही। टेक महिंद्रा का शेयर सबसे अधिक 1.40 प्रतिशत, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 0.31 और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 0.11 प्रतिशत की बढ़त में बंद हुआ।

जालंधर में पत्नी का हत्यारा गिरफ्तार

जालंधर। पंजाब में जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एक प्रवासी को गिरफ्तार किया, जिसने शाहकोट के कोटली गजरा गाँव में पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था। शाहकोट के उप पुलिस अधीक्षक सुखपाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने हत्यारोपी मुन्ना कांति (30) को घटना के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि छह दिसंबर को जरनैल सिंह पुत्र बलदेव सिंह, निवासी कोटली गजरा ने सूचना दी कि चार दिसंबर को करीब छह बजे शाम को वह अपने खेतों पर गए थे जहां पर एक मजदूर पत्नी और दो बच्चों के साथ सड़क पर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ठंड के मौसम के कारण, जरनैल सिंह ने जमीन में बने एक कमरे में रहने के लिए कहा। छह दिसंबर को सुबह वह अपने कुएं पर गए और देखा कि महिला की मृत्यु हो गई थी। उसका शव कमरे के अंदर फर्श पर पड़ा था और वह व्यक्ति अपने बच्चों के साथ उस समय मौजूद नहीं था। जो पत्नी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूछताछ में आरोपी मुन्ना कांति ने बताया कि उसकी शादी करीब 15 साल पहले रानी कुमारी से हुई थी।

गुजरात में महिला चिकित्सक की हत्या करने से पहले पकड़े गये शूटर

एजेंसी ◄ झुंझुनू
www.dailypioneer.com

राजस्थान में झुंझुनू पुलिस ने गुजरात में एक महिला चिकित्सक की सुपारी लेकर हत्या करने की साजिश रचने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय ने बताया कि 21 नवम्बर को बदमाशों द्वारा रंगदारी के लिये लिखवा ठेके पर गोलीबारी की गयी थी। इस मामले में पुलिस ने हिमांशु जाट को पकड़ा। पूछताछ में हिमांशु ने खुलासा किया कि वे इस गोलीबारी के अलावा गुजरात में एक महिला चिकित्सक की हत्या की सुपारी लेकर आये थे। इसके बाद पुलिस ने मनोज मेघवाल (30), आकाश उर्फ बिट्टू (21), सचिन उर्फ कालु (24), भूपेन्द्र कुमार (20) और अनुज शर्मा (22) को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि हिमांशु की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर हत्या की सुपारी के लिए खरीदे गए हथियार बरामद किए गए। जिसमें एक पिस्तौल, सात कारतूस, चार खाली कारतूस के खोल बरामद किए गए। आकाश और मनोज को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। अनुज शर्मा को वडोदरा, गुजरात से दस्तयाब किया गया। भूपेन्द्र को पिलानी से दस्तयाब किया गया। इस प्रकार गुजरात, उत्तर प्रदेश और जयपुर जाकर कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस ने इस बड़ी हत्या की योजना का पर्दाफाश कर दिया।

स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने नए अभियान 'क्रांति खेल से' का किया शुभारंभ

नयी दिल्ली। स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने आधिकारिक तौर पर अपना नया सोशल मीडिया अभियान 'क्रांति खेल से' का शुभारंभ किया। इस अभियान का मकसद बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता (आईडीडी) वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी खेल और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने वाले एक समर्पित संगठन के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करना है। इस अवसर पर स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नडडा ने कहा, क्रांति खेल से एक समावेशी भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक ऐसा भारत जहां बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को उनकी ताकत के लिए सराहा जाता है। इस अभियान के माध्यम से, हम सार्वजनिक समझ का विस्तार करने और एक ऐसा समाज बनाने में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करते हैं जहां बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को चमकने का अवसर मिले। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के मीडिया और संचार निदेशक अंतरिक्ष जायसवाल ने कहा, यह अभियान लचीलेपन और प्रभाव की कहानियों को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। हमारा लक्ष्य अपनी डिजिटल उपस्थिति को मज़बूत करना, युवा समर्थकों को जोड़ना और अधिक भागीदारों और समुदायों को खेलों के माध्यम से समावेशन को आगे बढ़ाने में हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।

टिहरी गढ़वाल में जनता दरबार में डीएम ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण का दिया निर्देश

टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों को सुना। इस दौरान 56 से अधिक आवेदन पत्र दर्ज किए गए, जिनमें पुनर्वास, लोक निर्माण, सिंचाई, राजस्व, विद्युत सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं। बैठक में सीएम हेल्पलाइन एवं जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें तथा क्लोज हो चुकी शिकायतों को पोर्टल पर समय से अपडेट करें। जनता दरबार में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे,जिसमे, धनीराम सेमवाल, ग्राम गेंवली (देवल), जाखणीधार ने घर के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन हटाने व पोल शिफ्टिंग की मांग की, जिस पर अधिशासी अभियंता को कार्यवाही हेतु निर्देश मिले।

नेपाल के शुक्लाफाँटा राष्ट्रीय उद्यान का 15 सदस्यीय दल पहुँचा कॉर्बेट

रामनगर। नेपाल के प्रसिद्ध शुक्लाफाँटा राष्ट्रीय उद्यान से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के दौरे पर पहुँचा। दल का नेतृत्व नेपाल के वन्यजीव वार्डन चंद्रशेखर चौधरी ने किया,प्रतिनिधिमंडल में नेपाल सरकार के अधिकारी, स्थानीय गांवों से जुड़े पर्यटन क्षेत्र के लोग, प्राइवेट टूरिज्म सेक्टर के प्रतिनिधि, कंजरवेशन पार्टनर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स शामिल रहे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व और नेपाल के शुक्लाफाँटा राष्ट्रीय उद्यान के बीच इको-टूरिज्म को जोड़ना और दोनों पार्कों के पर्यटन मॉडल को साझा करना रहा, इस कड़ी में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। नेपाल के वन्यजीव वार्डन चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि उनका मुख्य उददेश्य यह समझना है कि शुक्लाफाँटा और कॉर्बेट के बीच टूरिज्म को किस तरह से लिंक किया जाए।

ऋषिकेश में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर चला गृह संपर्क अभियान

एजेंसी ◄ ऋषिकेश
www.dailypioneer.com

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित शताब्दी वर्ष कार्यमों के अंतर्गत खांड गांव लालपानी कक्ष संख्या-2 में गृह संपर्क अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में सह विभाग प्रचारक ललित शंकर (हरिद्वार विभाग), सह विभाग कार्यवाह मनोज सैनी, नगर प्रचारक ऋषिकेश, धर्म जागरण मंच के प्रदेश सहसंयोजक राहुल तथा सेवा भारती के जिलाध्यक्ष डॉ. हेतराम ममगाई मौजूद रहे। अभियान के दौरान सह विभाग प्रचारक ललित शंकर ने 'पांच परिवर्तन' सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, आधारित जीवन और नागरिक कर्तव्य बोध विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में संघ से प्रेरित विभिन्न संस्थाओं द्वारा व्यापक जनसेवा कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें बनवासी कल्याण आश्रम की 333 ग्रामों में संस्कार शालाएं, विवेकानंद हेल्थ मिशन के 11 चिकित्सालय, उत्तरांचल उत्थान परिषद समिति के छात्रावास व स्वावलंबन केंद्र तथा ऋषिकेश एम्स के निकट भाऊराव देवरस न्यास द्वारा 430 बेड का तीमारदार विश्राम गृह शामिल हैं। जनकल्याण न्यास द्वारा ई-पुस्तकालय भी संचालित किया जा रहा है।

एसटीएफ ने 195 किलो अवैध गांजा के साथ तस्कर को दबोचा

एजेंसी ◄ लखनऊ/मथुरा
www.dailypioneer.com

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मथुरा जिले से 195 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को थाना कोसीकलां क्षेत्र में हिरासत में लिया गया है। एसटीएफकी ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान कन्हैया लाल सिंह, निवासी जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 195 किलो से अधिक गांजा (अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग दो करोड़ रुपये), एक कंटेनर वाहन, मोबाइल फोन, 2840 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। एसटीएफ फील्ड इकाई आगरा को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि उड़ीसा से अवैध गांजा लाकर मथुरा के रास्ते अन्य राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम सयि निगरानी कर रही थी। बीती रात करीब 12:30 बजे एक कंटेनर वाहन पर शक होने पर उसे रोका गया। चालक ने अपने साथी द्वारा भेजे गए स्थान से गाड़ी लेकर आगे बढ़ने की बात कही, लेकिन वाहन की तलाशी के दौरान छुपाकर रखा गया भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वाहन विनोद कुमार नामक व्यक्ति की है और उक्त गाड़ी में पहले भी अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई की गई थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी और उसके साथी अलग-अलग राज्यों में नशे का सामान पहुंचाते हैं और वसूली के रूप में प्रत्येक खेप पर 25 से 30 हजार रुपये कमाते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत शर्तों में ढील दी

पायनियर संवाददाता ◄ नयी दिल्ली
www.dailypioneer.com

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर लगायी गयी सख्त शर्तों में ढील दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सितंबर 2024 के आदेश में संशोधन किया, जिसमें बालाजी को चेन्नई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के सामने हर सोमवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेश होना पड़ता था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अब बालाजी को ईडी अधिकारी के सामने केवल जरूरत पड़ने पर पेश होना होगा, और वह भी पूर्व सूचना मिलने के बाद। बालाजी की ओर से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और शिकायत विशेष अदालत में दाखिल हो चुकी है इसलिए साप्ताहिक पेशी की कोई जरूरत नहीं है। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह शर्त आरोपों की गंभीरता के कारण लगाई गयी थी। पीठ ने इस शर्त की तर्क संगतता पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, एक आदमी हर सोमवार-शुक्रवार आपके सामने पेश हो रहा है। वह आपके अधिकारी के साथ चाय पीता है। क्या यह जरूरी है? न्यायमूर्ति बागची ने कहा, डेढ़ साल से व्यक्ति हर हफ्ते दो बार पेश हो रहा है... क्या उसने कभी कोई चूक की है? कम से कम अपने अधिकारी को इस परेशानी से बचाएं। उसे हर सोमवार और शुक्रवार उसका इंतजार करना पड़ता है। न्यायालय ने एक और जमानत शर्त में ढील दी, जिसमें बालाजी को निचली अदालत की हर तारीख पर विशेष पीएमएलए अदालत में पेश होना पड़ता था। अब स्पष्ट किया गया है कि बालाजी किसी विशेष कठिनाई के मामले में छूट मांग सकते हैं, और निचली अदालत ऐसी याचिकाओं पर उनके गुण दोष के आधार पर फैसला करेगा। इन संशोधनों के साथ, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मंत्री पर लगाई गई रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियों को काफी हद तक कम कर दिया है, जबकि जमानत की समग्र शर्तें बरकरार रखी गई हैं।

एमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह की अध्यक्षता करें

एजेंसी ◄ गोरखपुर
www.dailypioneer.com

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का मुख्य महोत्सव समापन कार्यम बुधवार 10 दिसंबर को महायोगी गोरखनाथ में होगा। विश्वविद्यालय गोरखपुर एमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोहएमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोहएमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोहएमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोहएमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोहएमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह (एमजीयूजी) आरोग्यधाम के परिसर में होगा जिसकी अध्यक्षता गोरक्षपीठाधीश्वर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगें और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल होंगे। समारोह में उत्कृष्टता के आधार पर एमपी शिक्षा परिषद की संस्थाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और संस्थापक सप्ताह समारोह के तहत आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी, पदक व नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर एमपी शिक्षा परिषद के स्मृतिशेष अध्यक्ष प्रो. यूपी सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी होगा। मुख्य महोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार प्रातः 900 बजे से प्रारम्भ होगा। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह का शुभारंभ 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यम के साथ हुआ था। शुभारंभ कार्यम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी उपस्थित थे। 10 दिसंबर को इसका समापन सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के मेधावियों को पुरस्कृत करने के साथ होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों पुरस्कृत होंगी। इस दौरान परिषद की सर्वश्रेष्ठ संस्था, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, इंटरमीडिएट, स्नातक व परास्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाएगा। संस्थापक समारोह के मुख्य कार्यम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति स्व. प्रो. यूपी सिंह पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा।

तेलंगाना में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे एरिक स्वीडर

एजेंसी ◄ हैदराबाद
www.dailypioneer.com

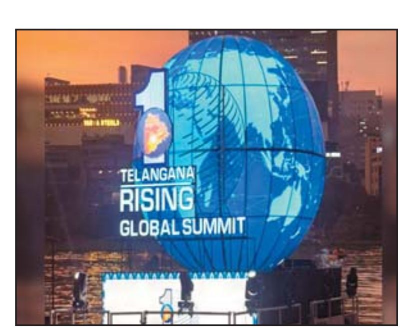

ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (टीएमटीजी) के निदेशक एरिक स्वीडर ने तेलंगाना के तेज विकास और निवेश अनुकूल माहौल को देखते हुए घोषणा की कि वह अगले दस वर्षों में फ्यूचर सिटी और इससे जुड़ी विकास परियोजनाओं में एक लाख करोड़ रुपये तक का निवेश करेंगे। स्वीडर ने भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में कहा कि तेलंगाना आकर वे सम्मानित और आभारी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और राज्य सरकार द्वारा दी गई मेहमान नवाजी के लिए गहरी प्रशंसा की। स्वीडर पहले ट्रुथ सोशल के कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें जो गर्मजोशी और प्रोफेशनलिज्म का अनुभव हुआ, उसने उन पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में तेलंगाना के विकास ने उन्हें 'हैरान कर दिया है।' उन्होंने राज्य की सराहना करते हुए कहा कि उसने ऐसा माहौल बनाया है जहां वैश्विक पूंजी का स्वागत महसूस होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेश के फैसले सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं होते बल्कि सार्थक, लंबे समय तक चलने वाले वैश्विक बदलाव में योगदान देने के बारे में भी होते हैं और तेलंगाना ऐसा मौका देता है। उन्होंने ट्रुथ सोशल के बारे में अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व और टेक्नोलॉजी कंपनियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। इससे पहले तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने ग्लोबल सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री रेवंत रेडडी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, केंद्रीय मंत्री किशन रेडडी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी, पुलिस महानिदेशक शिवधर रेडडी और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र : एक डॉक्टर के भरोसे 'रेफर सेंटर' बना अस्पताल, मरीज परेशान

पायनियर संवाददाता ◄ भानुप्रतापपुर
www.dailypioneer.com

अंचल के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी अव्यवस्था के कारण मरीजों की परेशानी चरम पर है। स्थिति यह है कि पूरा अस्पताल केवल एक डॉक्टर के भरोसे छोड़ दिया गया, जबकि बाकी डॉक्टर 'ट्रेनिंग और मीटिंग' का बहाना बनाकर नदारद रहे। इस गंभीर लापरवाही के चलते सुबह से ही अस्पताल पहुंचे ग्रामीण मरीज और उनके परिजन घंटों तक परेशान होते रहे। ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए अस्पताल पहुँच रहे मरीजों को न केवल डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें अस्पताल स्टाफ के निराशाजनक व्यवहार से भी गुजरना पड़ रहा है। शिवसेना नेता चंद्रमौली मिश्रा ने अस्पताल की अव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, ग्रामीण अंचल से मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन डॉक्टर अक्सर अस्पताल से नदारत रहते हैं। यह अस्पताल अब सिर्फ 'रेफर सेंटर' बनकर रह गया है, जहाँ से मरीजों को इलाज के लिए सीधे बड़े शहरों में रेफर कर दिया जाता है।

डॉक्टरों की भारी कमी और ड्यूटी से नदारद रहना

दो साल से सोनोग्राफी सुविधा का बंद होना। अस्पताल स्टाफ का मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार। जीवन दीप समिति' की राशि के दुरुपयोग का आरोप। अस्पताल परिसर और पीने के पानी के आस-पास घोर गंदगी। जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने जिला प्रशासन से तत्काल इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था पर संज्ञान लेते हुए दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र की जनता को समुचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

दो साल से सोनोग्राफी बंद: गरीबों पर आर्थिक बोझ

अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या सोनोग्राफी सुविधा का दो साल से बंद होना है। यह सुविधा बंद होने के कारण गर्भवती महिलाओं और अन्य जरूरतमंद मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों में मोटी रकम देकर सोनोग्राफी करानी पड़ रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

जीवन दीप समिति' की राशि पर सवाल, जानकारी देने में टालमटोल

अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर 'जीवन दीप समिति' की राशि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। शिवसेना नेता मिश्रा ने आरोप लगाया कि समिति की राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, जबकि इस राशि का उपयोग अस्पताल की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने और सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। जब 'जीवन दीप समिति' के फंड के संबंध में जानकारी मांगी जाती है, तो प्रबंधन द्वारा गोलमोल जवाब देकर टालमटोल किया जाता है।

गंदगी का आलम : पीने के पानी तक पर ग्रहण

अस्पताल में साफ-सफाई की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। मरीजों के लिए लगाए गए वाटर कूलर के पास भी चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों की खुली अनदेखी है। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई थी कि नए बीएमओ के आने से अस्पताल की स्थिति सुधरेगी, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्या निराकरण करने दिलाया भरोसा

पायनियर संवाददाता ◄ नारायणपुर
www.dailypioneer.com

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवो से पहुंचे लोगों से मुलाकात किया। उन्होंने मुलाकात कर उनकी मांगो एवं समस्याओं और शिकायत संबंधी आवेदनों का निराकरण कराने भरोसा दिलाया एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आज जनदर्शन में फुलेश्वरी बघेल ग्राम गौरवण्ड द्वारा रोजगार हेतु, समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत हिकुल द्वारा प्राथमिक शाला केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने तथा सोलर डयूल पम्प स्वीकृति करने, पुष्पादानी एड़का रोड बखरूपारा द्वारा पेंशन जी.पी.एफ ग्रेजुएटी एवं एरियस का समाधान करने, दुष्यंत कुमार बंजारे शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय द्वारा शासकीय आवास में मरम्मत कार्य करवाने, हेमन्त साहू निवासी ग्राम तेलसी द्वारा मेरे शासकीय भूमि पर लगभग 40 वर्षो से मकान बनाकर काबिज भूमि है उस भूमि का फर्जी पट्टा बना लिया गया है जिसकी जांच कर फर्जी तरीके से बने पटटे को निरस्त करने, समस्त ग्रामवासी ग्राम कोटेनार द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराने, सरपंच ग्राम पंचायत नेडनार द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराने, सोमनाथ धनेलिया ग्राम बोरण्ड द्वारा ग्राम बोरण्ड में हेण्डपंप खनन करने, सरपंच ग्राम पंचायत हान्दावाडा द्वारा सड़क निर्माण करवाने, आंगनबाड़ी केन्द्र खोलवाने, समस्त ग्रामवासी ग्राम गोहड़ा द्वारा स्वास्थ केन्द्र और स्कुल खेल मैदान मिडिल स्कुल भवन एवं पशु चिकित्सा भूमि आरक्षित के संबंध, सरपंच ग्राम पंचायत बाकुलवाही द्वारा सी.सी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति प्रदाय करने, समस्त ग्रामवासी ग्राम कुंदाडी द्वारा आंगनबाड़ी के संबंध में, मंगलराम गावड़े ग्राम ओरछा द्वारा माह जून 2025 जुलाई अगस्त सितम्बर 2025 का अप्राप्त मासिक वेतन आहरण करने, सरपंच ग्राम पंचायत रायनार द्वारा धान पंजीयन नही होने, सरपंच ग्राम पंचायत ताडोपाल द्वारा ग्राम खड़कागांव गोमटेपारा हेतु द्वितीय श्रेणी सड़क स्वीकृति करने, जुगुल कोर्राम ग्राम आतरगांव द्वारा लंबित राशि का भुगतान कराने, राजेश कुमार पटेल ग्राम महिमा गवाड़ी द्वारा लंबित राशि का भुगतान कराने एवं प्रवीण जैन पार्षद माड़ीन देवी वार्ड द्वारा जिले में रेत खदाने आबंटित न होने के कारण शासकीय विद्यालय कार्यो में अवरोध 181-25 प्रति घन मीटर की दर विसंगति और अनुचित पेनाल्टी पर रोक लगाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जनदर्शन में 20 प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने गंभीरतापूर्वक सभी आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए ग्रामीणों को भरोसा दिलाया।

कलेक्टर ने किया ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी वेयर हाउस का आंतरिक निरीक्षण

कांकेर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी वेयर हाउस का आंतरिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से राजेन्द्र सिंह गौर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुरुषोत्तम पाटिल तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र कुर्रे एवं जिला कोषालय अधिकारी अनिभा रेणु सोनबेर भी मौजूद थे।

नियद नेल्लानार क्षेत्र के ग्रामों में 11 से 24 दिसंबर तक समाधान शिविर आयोजित

नारायणपुर। जनपद पंचायत ओरछा के नियद नेल्लानार क्षेत्र के चयनित ग्रामों में शासन की विभिन्न योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को लाभान्वित करने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 11 से 24 दिसंबर 2025 तक निर्धारित तिथियों पर आयोजित होंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ओरछा द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन शिविरों में स्वास्थ्य, पशुपालन, मत्स्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, कृषि, श्रम, खाद्य, विपणन सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। शिविरों में योग्य ग्रामीणों को नवीन राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, पीएम-किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तथा अन्य योजनाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण स्थल पर ही किया जाएगा।

कड़मपाल में नवभारत साक्षरता अभियान के तहत महापरीक्षा का किया आयोजन

पायनियर संवाददाता ◄ किरंदुल
www.dailypioneer.com

नवभारत साक्षरता अभियान के अन्तर्गत संकुल केन्द्र कड़मपाल विकासखंड कुआकोंडा के छः केन्द्रों में राष्ट्रीय महापरीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित हैं। इसी तारतम्य में असाक्षरों को पुष्पगुच्छ भेंट कर परीक्षा में शामिल किया गया। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी को साक्षर करना हैं।कलेक्टर कुणाल दुदावत के आदेशानुसार एवं ब्लाक कार्यालय कुआकोंडा के शिक्षा अधिकारी प्रमोद भदौरिया के मार्गदर्शन में कुआकोंडा के सभी संकुलों में महापरीक्षा का नियमित रुप से आयोजन किया गया।इस परीक्षा में

मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित एवं सरकार की मुख्य धारा में आये अभ्यार्थियों का भी शामिल होना सराहनीय रहा। जिन्होंने पूर्व में स्कूल छोड़ चुके थे। इस कार्यक्रम में रविन्द्र प्रताप सिंह गौतम, संकुल समन्वयक एम माधव राव, शांति स्वामी, शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

बच्चों की जरूरत को देखते हुए पार्षद ने बढ़ाया हाथ, बांटे स्टडी टेबल

पायनियर संवाददाता ◄ किरंदुल
www.dailypioneer.com

वार्ड क्रमांक 09 की पार्षद लीना सोनी ने अम्बेडकर कॉलोनी स्थित भारत माता स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 14 स्टडी टेबल दिए। यह कार्यक्रम सोमवार स्कूल परिसर में हुआ।स्कूल में बच्चों को ठीक से पढ़ने और लिखने की सुविधा बढ़ानी थी। इस समस्या को देखते हुए पार्षद ने अपनी निधि से स्टडी टेबल खरीदकर स्कूल को दिए, जिससे बच्चों को आराम से और ध्यान लगाकर पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। प्राचार्या अंजलि नाग ने कहा कि इस सहयोग से बच्चों की पढ़ाई का माहौल और बेहतर होगा। पार्षद लीना सोनी ने कहा बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट चले, इसी सोच के साथ यह प्रयास किया गया है। आगे भी बच्चों के लिए जरूरी

सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह, प्राचार्या अंजली नाग, स्कूल संचालन समिति के अध्यक्ष एस.आर. नाग, किरंदुल चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष संजय सोनी और नपा के पार्षदगण व शिक्षक मौजूद थे।

स्कूल कैईन्ता अभियान : अप्रवेशी एवं शाला-त्यागी बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण सम्पन्न

पायनियर संवाददाता ◄ नारायणपुर
www.dailypioneer.com

स्कूल कैईन्ता अभियान संचालन किया जा रहा है। उक्त अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायत अन्तर्गत आश्रित गावों का शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यरर्ताओं एवं बिहान के सदस्यों द्वारा डोर-डोर 22364 घरों का सर्वे किया गया है। सर्वे पश्चात उक्त गावों में शाला त्यागी 1135 एवं अप्रवेशी 1280 बच्चों का चिंन्हान किया गया है। चिन्हान पश्चात कुछ बच्चों को पालके के सहमति उपरांत गांव के आस-पास स्कूलों, छात्रावास, आश्रम में अप्रवेशी 705 एवं शाला त्यागी 88 कुल 793 बच्चों को प्रवेश कराया है। कुछ पालकों द्वारा गांव से स्कूल की दूरी अधिक एवं अन्य समस्या होने के कारण गांव में ही कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार 10 गावों में अतिरिक्त शाला संचालन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला खनिज न्यास निधि मद से अतिथि शिक्षक एवं रसोईया मानदेय राशि स्वीकृत कर संचालन किया जा रहा है। स्कूल कैईन्ता अभियान अन्तर्गत ब्रिज कोर्स संचालन किया जा रहा है जिसके तहत बिहान के सदस्यों द्वारा अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को गांव में ही पढ़ाया जायेगा। गांव में 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को उल्लास साक्षरता मिशन के तहत असाक्षरों को साक्षर बिहान (शिक्षा सखी) अन्तर्गत गठित स्वसहायता समूह के सदस्यों को किया जावेगा। 15 से 18 वर्ष के शाला त्यागी बच्चों को ओपन स्कूल परीक्षा हेतु आवेदन फर्म भरवाया जा रहा है।

जिले में 05 दिसम्बर तक हुई 14 हजार 162 क्विंटल धान की खरीदी

नारायणपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश सहित जिले में गत 05 दिसम्बर तक जिले के पंजीकृत किसानों से विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों के जरिये अनवरत रूप से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के मार्गदर्शन में इन केन्द्रों में किसानों के धान का उपार्जन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के धान खरीदी केन्द्रों में 05 दिसम्बर तक 14 हजार 162 क्विंटल धान की खरीदी की गयी है, जिसमें धान खरीदी केन्द्र एड़का में 2443.6 क्विंटल, गढ़बेंगाल में 3099.2 क्विंटल, ओरछा में 1804.9 क्विंटल, कोहकामेटा में 0.00 क्विंटल, बासिंग में 0.00, छोटेडोंगर में 1137.6 क्विंटल, झारा में 26.8 क्विंटल, कन्हारगांव में 00.8 क्विंटल, सोनपुर में 28.4 क्विंटल, चांदागांव में 32.0, दण्डवन में 0.00 क्विंटल, नारायणपुर में 2894.0 क्विंटल, धौड़ाई में 627.6 क्विंटल, बेनूर में 514.4 क्विंटल और बाकुलवाही में 2051.6 क्विंटल, बिंजली में 4.00 क्विंटल, कुकड़ाझोर में 350.4 क्विंटल धान की खरीदी हुई है।

कुआकोंडा में उल्लास महा परीक्षा का हुआ सफल आयोजन

पायनियर संवाददाता ◄ किरंदुल
www.dailypioneer.com

उल्लास नव साक्षरता महापरीक्षा अभियान विकासखंड कुआकोंडा मे जिला मिशन समन्वयक हरीश प्रताप सिंह गौतम, विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद भदौरिया एवं सहायक खंडशिक्षा अधिकारी मनोज राठौर के के द्वारा नवसाक्षरो को पुष्पगुच्छ एवं तिलक लगाकर कर परीक्षा केंद्र मे स्वागत किया एवं डीएमसी सर एवं बीईओ सर के द्वारा सभी को उल्लास साक्षरता का पेपर वितरण कर सभी को परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया गया उल्लास साक्षरता विकासखंड कुआकोंडा मे कुल 12060 परीक्षार्थी राष्ट्रव्यापी नवसाक्षर महापरीक्षा में शामिल हुए इस महापरीक्षा को सफल बनाने के लिए समस्त केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक एवं वीटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

महापरीक्षा अभियान अंतर्गत कांकेर जिला में 9765 नवसाक्षरों ने दी परीक्षा

पायनियर संवाददाता ◄ कांकेर
www.dailypioneer.com

कलेक्टर एवं अध्यक्ष निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत महापरीक्षा अभियान जिला में आयोजित किया गया, जिसके लिए 426 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे जहां महिला नवसाक्षर 6216 और पुरुष नवसाक्षर 3549 कुल 9765 नवसाक्षर ने परीक्षा दी। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए 2027 तक शत-प्रतिशत साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले के सातों विकासखंडों की प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इस बर परीक्षा में अलग नजारा देखने को मिला जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों ने एक साथ परीक्षा दी। उम्रदराज महिला एवं पुरुष शिक्षार्थियों ने भी साक्षर होने के लिए बढ़-चढ़कर परीक्षा दी। इसी क्रम में विधानसभा कांकेर के विधायक आशाराम नेताम द्वारा अन्नपूर्णापारा के प्राथमिक शाला परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया। साथ ही प्राथमिक शाला बागोडार के परीक्षा केंद्र का जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद ने भी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। बताया गया कि जिले के 4 विकासखंडों में क्रमशः परीक्षा केंद्र शासकीय माध्यमिक शाला बेवरती, माध्यमिक शाला पटौद, प्राथमिक शाला करप, प्राथमिक शाला सरईटोला, माध्यमिक शाला करप, माध्यमिक शाला सरंगपाल, माध्यमिक शाला माटवाड़ा मोदी, प्राथमिक शाला तेलगरा, प्राथमिक शाला हिंगनझर का निरीक्षण परीक्षा के दौरान विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया। इसके अलावा विकासखंड भानुप्रतापपुर में नक्सली पुनर्वास केंद्र मुल्ला में भी विशेष तौर पर 34 असाक्षरों के द्वारा साक्षर बनने के लिए परीक्षा दी गई।

जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और उनके समृद्ध इतिहास पर विस्तार से चर्चा की गई

शासकीय महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय में 'जनजातीय गौरव' पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

पायनियर संवाददाता ◄ भानुप्रतापपुर
www.dailypioneer.com

शासकीय महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर में ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और उनके समृद्ध इतिहास पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष किरण नरेटी थीं, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष रत्नेश सिंह मंच पर मौजूद थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य रशिम सिंह ने की। अन्य गणमान्य अतिथियों में जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र टेकाम, भाजपा नेता राजीव श्रीवास, नरोत्तम सिंह चौहान, गिरधारी नरेटी और छत्रप्रतप दुग्गा भी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता विकास मरकाम ने 'जनजातीय गौरव दिवस' के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को जनजाति समाज के क्रांतिकारियों के देश की आजादी में दिए गए अमूल्य योगदान से अवगत कराया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि धरती, ज़मीन, और पेड़-पौधों का सम्मान करना जनजातीय परंपरा का मूल है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले झंडा उठाने वाले तिलका मांझी थे, और जनजाति समाज ने अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कांकेर जिले के शहीद गेंद सिंह और अन्य जन जाति महानायकों के बारे में बताया। शहीद गुडर धुर के नारे अगर अंग्रेज पेड़ कटाई करते हैं, तो अंग्रेजों के सर काटें का उल्लेख करते हुए संघर्ष की गाथा सुनाई। ऐतिहासिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब सीपी बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी और रतनपुर के राजा रायसिंह जगत ने रायपुर को बसाया है।

अतिथियों के विचार - मुख्य अतिथि एवं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जनजाति समाज द्वारा देश के लिए किया गया योगदान अस्मरणीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा जनजाति समाज के लिए चलाई जा रही विशेष योजनाओं का उल्लेख किया, जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बस्तर पांडुम की शुरुआत करने का श्रेय भी दिया, जिसके तहत बस्तर के व्यंजन और खेल-कूद का आयोजन किया गया था।।उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ समाज के लिए भी काम करें, क्योंकि उनका समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है और हम सबको मिलकर समाज के उत्थान के लिए प्रयास करना है।

पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम - कार्यशाला के दौरान महाविद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसे सभी ने सराहा। अतिथियों ने रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

ESAF
ESAF SMALL FINANCE BANK
REGD. OFFICE: ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur- 680 651, Kerala.

GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold ornaments pledged with ESAF Small Finance Bank and not redeemed by borrowers, despite repeated reminders and notices, of our branches, are listed below. This will be auctioned as per the details given below:

DATE OF AUCTION: 19-12-2025 TIME: 11 am to 6 pm
AUCTION VENUE: Through e-Auction
AUCTION ADDRESS: https://gold.matexnet.org/
Contact Number: 9944171360 / 9843312694

To register as bidder for the e-Auction with terms and conditions, and full details of e-Auction please visit the above site

BRANCHES & LOAN ACCOUNT NUMBERS

BHATAPARA: 63250001380305, BILASPUR: 63250001373588, CHAMPA: 75250001340814, DHAMDHA: 63250001349125, DHAMTARI: 63250001380785, 1387882, 75240003908881, DONAGARGARH: 75250001311089, JASHPUR: 63250001362309, 1386004, KATGHORA: 63250001386454, 75250001330143, KHARSIA: 63250001358567, 1359685, 75250001292103, KORBA: 63250001393360, SARANGARH: 63250001366882, 75240003801192, 3823480, SHIVRINARAYAN: 63250001373728, 75240003800574.

Customers who are interested to release the ornaments by paying the total due amount may do so, at the respective branches, on or two days before the date of the auction.

Bidders who wish to participate in the auction shall produce their KYC documents. GST No. is mandatory for registered firms/companies. Bidders shall deposit a sum of Rs.50,000 as EMD before participating in the auction.

Thrissur
Date: 09-12-2025
Sd/-
Authorized Signatory

कुरूद पालिका की मनमानी के विरोध में कांग्रेसी पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन

पायनियर संवाददाता ➤ धमतरी
www.dailypioneer.com

नगर पालिका अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मनमानी के विरोध में कुरूद की जनता के हित में कांग्रेस पार्षदों के द्वारा बजरंगबली की पूजा अर्चना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाया चित्र में माल्यार्पण करके राष्ट्रगान गाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया है। इनकी प्रमुख मांगों में परिषद की सामान्य सभा की बैठक में कुरूद नगर के हित में लिए गए निर्णय में छेड़छाड़ करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही, परिषद के निर्णय के बिना नगर पालिका कार्यालय को अस्थाई रूप से कैनाल रोड स्थित सामुदायिक भवन में स्थानांतरित करने के विरोध मे, परिषद के निर्णय के बिना नगर पालिका कार्यालय एवं सामने के दुकानों को तोड़कर व्यावसायिक कांप्लेक्स बनाने के विरोध में, प्रधानमंत्री आवास के ग़रीब हितग्राहियों की सालों से लंबित बचत किस्त की राशि को तत्काल भुगतान किये जाने जैसी मांगे शामिल हैं। कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि नगर हित में उपरोक्त सभी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता एवं दोषियों पर कार्यवाही जब तक नहीं की जाती, तब तक कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों एवं कुरूद के नागरिकों द्वारा नगर पालिका कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि कुरूद नगर को बचाने के लिए सभी नागरिकों, युवा साथियों एवं कांग्रेसजनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में उपस्थित हो कर कुरुद नगर को बचाने में अपना समर्थन दे अपनी सहभागिता प्रदान करें।

कुपोषण मुक्त नगरी अभियान का शुभारंभ-2000 बच्चों को एक साथ स्वर्ण प्राशन

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संचालनालय आयुष छत्तीसगढ़ तथा जिला आयुष कार्यालय धमतरी द्वारा कुपोषण मुक्त नगरी अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड नगरी के सांकरा ग्राम में 2000 बच्चों को एक साथ स्वर्ण प्राशन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान का उद्देश्य विकासखंड नगरी को पूर्णतः कुपोषण मुक्त बनाना है जिसके लिए आयुष विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग मिलकर अंतर.विभागीय समन्वय के माध्यम से संयुक्त कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। अभियान के तहत 1200 मध्यम कुपोषित और 200 गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रत्येक माह दो बार आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इन बच्चों को नियमित रूप से स्वर्ण प्राशन पिलाया जाएगा और उनके स्वास्थ्य की गहन देखभाल की जाएगी। आयुष विभाग ने अपने उच्च संस्थानों में बच्चों के लिए पंचकर्म उपचार की विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित सभी संस्थानों में कुपोषित एवं गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य बच्चों के लिए यह सेवा मात्र 20 रुपये शुल्क पर उपलब्ध होगी। आयुष विभाग सभी अभिभावकों से अपील करता है कि वे अपने नजदीकी आयुष संस्थानों में जाकर बच्चों का पंजीयन कराएं और उन्हें स्वर्ण प्राशन अवश्य दिलाएं जिससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण मिल सके।

मकर संक्रांति में गंगासागर जाएगा राज्य से यात्री दल भाटापारा में भी आस्था का उमंग नजर आ रहा प्रबल

पायनियर संवाददाता ➤ भाटापारा
www.dailypioneer.com

तीर्थों एवं दिव्य स्थलों की भूमि भारत जहां पग पग मे आस्था के स्थल विद्यमान है। देवभूमि कहे जाने वाले देश मे देवताओं के अवतरण एवं जीवन लीला के प्रसंग चंहुओर नजर आते है, जिन्हे तीर्थों के रुप मे आस्था का उच्च स्थान प्राप्त है, इन तीर्थों का दर्शन एवं यात्रा अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक सनातनी का लक्ष्य जीवन मे कम से कम एक बार इन तीर्थों का दर्शन एवं यात्रा होता है, इन्ही तीर्थों मे एक महत्वपूर्ण तीर्थ है गंगासागर जिसके बारे मे कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगासागर सागर एक बार।

गंगा मैया के समुद्र से समागम स्थली – सनातन संस्कृति मे अत्यंत पुण्यदायी एवं परम आस्था की प्रतीक गंगा नदी प्रत्येक भारतीय के लिए परम आस्था की प्रतीक है। साथ ही साथ मोक्ष की दायनी भी माना जाता है, गंगोत्री से निकलकर गंगा विभिन्न स्थलों से होती हुई सागर मे समाहित हो जाती है। समुद्र से समागम की यह स्थली गंगासागर के रुप मे आस्थामय तीर्थ का भव्य रुप प्रकट करती है।

मकर संक्रांति में लगता है भव्य मेला

वर्ष मे एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर सिर्फ एक दिन के लिए गंगासागर सागर मे दिव्य मेला आयोजित होता है जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। गंगासागर मे पुण्य स्नान के लिए इस वर्ष भी 14जनवरी मकर संक्रांति के मद्देनजर लोगों का आस्थामय उत्साह गंगासागर यात्रा के लिए नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ से भी यात्रियों के दल निकलने की रुपरेखा बनती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी मे राजेन्द्र तिवारी दुर्ग के नेतृत्व मे रायपुर बिलासपुर धमतरी राजनांदगांव आदि विभिन्न क्षेत्रों से यात्रियों का दल गंगासागर यात्रा के लिए उत्साह पूर्वक शामिल होता हुआ नजर आ रहा है तथा बड़ी संख्या में लोगों के बीच यात्रा को लेकर उत्साह एवं उमंग की झलक नजर आ रही है।

भाटापारा से भी बड़ी भागीदारी का दर्शन

धार्मिक आयामों के शहर जहां विभिन्न पर्व एवं उत्सव को लेकर उत्साह एवं उमंग की झलक दिखाई देती है, मकर संक्रांति के अवसर पर 10जनवरी से प्रारंभ हो रहे एवं 19 जनवरी को समापन गंगासागर एवं जगन्नाथ पुरी दर्शन यात्रा को लेकर भी क्षेत्र मे उत्साह की झलक स्पष्ट रुप से नजर आ रही है तथा यात्रा को लेकर बड़ी संख्या मे भागीदारी के भी दर्शन हो रहें हैं।

उल्लास महापरीक्षा में उमड़ा उत्साह-7518 में से 7393 शिक्षार्थियों ने दी परीक्षा

धमतरी। जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आयोजित उल्लास महापरीक्षा उत्साहपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। इस महापरीक्षा में सास-बहू, देवरानी-जेठानी, पिता-पुत्र, पति-प ी तथा दिव्यांगजन सहित समाज के सभी वर्गों के शिक्षार्थियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। जिले में बनाए गए कुल 408 परीक्षा केंद्रों में 7518 शिक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 7393 शिक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 125 शिक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 15 वर्ष से अधिक आयु के ये सभी शिक्षार्थी 200 घंटे अध्यापन पूर्ण कर परीक्षा में शामिल हुए। महापरीक्षा में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर अबीनाश मिश्रा, जनप्रतिनिधि मोनिका ऋषभ देवांगन, चेतन हिंदुजा, जय हिंदुजा, पार्षद कोमल सार्वा ने वीडियो संदेश के माध्यम से शिक्षार्थियों से परीक्षा में सम्मिलित होने की अपील की।

निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का सफल आयोजन

पायनियर संवाददाता ➤ भाटापारा
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ प्रान्तीय मारवाड़ी युवा मंच एवं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वावधान में मारवाड़ी युवा मंच ग्रेन सिटी भाटापारा, भाटापारा शाखा एवं जागृति शाखा द्वारा आयोजित निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का सफल व प्रेरणादायी समापन किया गया। सेवा और संवेदना से सजे इस शिविर में 85 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग, 5 को श्रवण यंत्र एवं 10 दिव्यांगजनों को बैशाखी प्रदान की गई। कुल 100 से अधिक जरूरतमंदों को नई राह, नया आत्मविश्वास और नया जीवन-संतुलन मिला। मारवाड़ी युवा मंच के प्रान्तीय अध्यक्ष प्रशान्त गाँधी ने शिविर को जीवन सुधार का मिशन बताते हुए कहा कि मंच द्वारा किया यह प्रयास सिर्फ सहयोग नहीं, बल्कि स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का संबल है। नगरपालिका अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने मंच की इस पहल को दिव्यांगजनों के जीवन में उम्मीद का प्रकाश बताते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता सुनील माहेश्वरी ने आयोजन को सच्ची जनसेवा कहा, वहीं पूर्व मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा ने मंच को निरंतर समाजहित में अग्रणी रहने की शुभकामनाएँ दीं। चिकित्सक डॉ. विकास अडिल ने शिविर को कई परिवारों के जीवन में नया साहस और फिर से जीने की शक्ति देने वाला अभियान बताया। कार्यक्रम में रामरतन मूंधड़ा, नरेश चौबे, सत्यनारायण जोशी, डॉ. बसन्त भृगु, गुलाब चंद गोलछा, प्रशांत गुप्ता, नरेश अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, श्यामरत्न मूंधड़ा, शिवकुमार दम्माणी, आशीष जायसवाल, हरिकिशन शर्मा, नरेश आर्य, गोपाल अग्रवाल, राजकुमार चोपड़ा, वाय. पी. सोनी, निक्की शर्मा एवं भरत अग्रवाल, राजू सोलंकी आदि ने भी मंच की इस सेवा परंपरा की सराहना करते हुए इसे समाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव बताया। दोनों शाखा अध्यक्षों कैलाश बंसल एवं ऋषभ जोशी द्वारा सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया एवं मानव सेवा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि यह शिविर पूरे भाटापारा नगर के लिए गौरव का विषय है।

कुरूद नगरपालिका को केन्द्र सरकार ने 96 लाख स्वीकृत प्रदान की

पायनियर संवाददाता ➤ कुरुद
www.dailypioneer.com

मोदी की गारंटी में, विष्णु के सुशासन और अजय के विकास रथ को आगे बढ़ाने के लिए कुरूद नगरपालिका को कचरा प्रबंधन के लिए मशीनें लगाने एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार ने 96 लाख स्वीकृत प्रदान किये है, कुरूद नगर में पिछले कई वर्षों से नगर के प्रमुख जगहो मे कालेज रोड के केनाल रोड किनारे और कुरूद से लगे ग्रामीण सीमाओं में कचरा डंपिंग कर देते थे, इन समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चन्द्राकर परिषद में प्रस्ताव करवाकर राइसमिल एरिया नगरपालिका के 4 एकड़ ज़मीन पर कचरा प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार से मशीनें लगाने एवं मनीकंचन केन्द्र तैयार करने राशि माँग किये थे, 5 दिसम्बर को केन्द्र सरकार ने आदेश जारी कर 96 लाख लागत से मशीन लगाने एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान किये है। यह महत्वपूर्ण स्वीकृति मिलने पश्चात नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चन्द्राकर अपने पार्षदों के साथ, कचरा प्रबंधन वाले जगह का निरीक्षण किये और मिडिया को जानकारी देते हुए कहा यह स्वीकृति कुरूद नगर में स्वच्छता हेतु नया अध्याय लिखेगी, वर्षो के कचरा डंपिंग समस्या से निजात मिलेगी, नगर को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार का कुरूद वासी सदैव ऋणी रहेंगे, हमारे नई परिषद के लगातार सक्रियता से कुरूद पिछले 9 महिनो से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, चारों दिशा में युद्ध गति से विकास कार्य चल रहे है, बहुत जल्द सबके सहयोग से कुरूद नगर की तस्वीर सुंदरता में सम्मिलित होने वाली है। कुरूद में विधायक अजय चन्द्राकर के मार्गदर्शन में परिषद के सभी सदस्यों के विकास परक सोंच के चलते नये नये क्षेत्रों मे विकास कार्य हो रहे है, कुरूद नगरवासियों को, परिषद के सदस्यों को हार्दिक बधाइयाँ, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विभागीय मंत्री अरूण साव, विधायक अजय चन्द्राकर, सांसद रूपकुमारी चौधरी का नगरवासियों की ओर धन्यवाद ज्ञापित करते है। इस अवसर पर निरीक्षण टीम मे परिषद के सदस्यों में विधायक प्रतिनिधि भानु चन्द्राकर, सभापति-पार्षदगण मिथिलेश बैस, महेन्द्र गायकवाड़, राजकुमारी ध्रुव, रवि मानिकपुरी, कविता चन्द्राकर, प्रेस क्लब अध्यक्ष मूलचंद सिन्हा उपस्थित थे।

आरएसएस की सेवा के 100 वर्ष पूरे होने पर गृह संपर्क, पत्रक का वितरण

पायनियर संवाददाता ➤ भाटापारा
www.dailypioneer.com

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन एवं सेवा के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ के स्वयंसेवकों द्वारा भाटापारा नगर के बस्ती में हर घर संपर्क अभियान के तहत घर- घर भारत माँ के चित्र एवं पत्रक का वितरण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत महाकाल बस्ती में जिला प्रचारक विवेकानंद, स्वयंसेवक अविनाश शर्मा एवं अन्य स्वयंसेवकों के साथ पत्रक वितरण किया। इस अवसर पर अविनाश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। शताब्दी वर्ष के पूरा होने पर पूरे देश में आरएसएस अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से सभी सनातनियों को यह पत्रक प्रदान कर राष्ट्र के प्रति समर्पित होने, संघ से जुड़ने, स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वयंसेवकों ने लोगों से संवाद कर समाजिक समरसता, राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक संरक्षण एवं स्वावलंबन के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया और जगह-जगह पत्रक ग्रहण करने वालों ने स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाया।

एक राष्ट्र-एक चुनाव : लोकतंत्र की मजबूती की ओर एक निर्णायक कदम : सुनील यदु

पायनियर संवाददाता ➤ भाटापारा
www.dailypioneer.com

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत एक राष्ट्र - एक चुनाव की अवधारणा न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगी, बल्कि यह प्रशासनिक स्थिरता, संसाधनों की बचत और विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करेगी। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को साकार करते हुए वन नेशन, वन इलेक्शन के पक्ष में भाटापारा शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नाकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद कर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' हेतु उनका बहुमूल्य सुझाव एवं हस्ताक्षर सहित उनका समर्थन प्राप्त करते हुए उक्त बाते जिलाध्यक्ष भाजयुमो सुनील यदु ने कही।

एक राष्ट्र-एक चुनाव आवश्यक : भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील यदु ने इस आयोजन पर चर्चा करते हुए आगे कहा कि अब समय आ गया है लोकतंत्र को अनावश्यक खर्च, बार-बार होने वाले चुनाव और राजनीतिक अस्थिरता की जकड़न से मुक्त किया जाए। सुनील यदु ने कहा कि नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ एक राष्ट्र-एक चुनाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस मुहिम से जोड़कर एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए लोकमत तैयार करना है। भाजपा युवा मोर्चा गांव, गली, शहरों, खेत, खलिहानों, दुकानों में चर्चा कर बड़ी संख्या में युवाओं को भी इस अभियान में जोड़ रही हैं। ताकि हर क्षेत्र के युवा जुड़े और एक राष्ट्र-एक चुनाव के विषय को लोकव्यापी बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर अविनाश शर्मा, पीयूष साहू, अभिषेक मिश्रा, सुरेंद्र डागोर, लीलेश्वर साहू सहित युवा साथी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सभी वार्डों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं महापौर ने

पायनियर संवाददाता ➤ धमतरी
www.dailypioneer.com

नगर निगम कार्यालय के बाहर बैठ कर जनदर्शन में नगर के सभी वार्डों से बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए। आमजन ने अपने-अपने वार्ड से जुड़ी सड़क, नाली, पेयजल, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, आवास, पेंशन व अन्य मूलभूत समस्याओं को महापौर रामू रोहरा के समक्ष रखा। महापौर ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और प्रत्येक शिकायत के समाधान की स्पष्ट जानकारी मौके पर ही दी। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन समस्याओं का निराकरण तत्काल संभव है, उन्हें तुरंत हल किया जाए, जबकि दीर्घकालिक एवं तकनीकी मामलों को प्राथमिकता सूची में शामिल कर निश्चित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए। महापौर ने कहा कि नगर के सभी वार्ड मेरे लिए समान हैं। हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनदर्शन के माध्यम से जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे कई वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा तय हुई। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

दो ग्रामों में 8 एकड़ एवं 4 एकड़ कुल 12 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक था

12 एकड़ के स्वामित्व का किसान देखते ही देखते बना 150 एकड़ का मालिक

पायनियर संवाददाता ➤ धमतरी
www.dailypioneer.com

राजनीति भी क्या चीज है, इसमें पदार्पण करने वाले लोगों का भाग्य इतना जल्दी बदल जाता है, जिसकी कल्पना शायद कोई आम आदमी नहीं कर सकता और धीरे धीरे नेतागिरी प्रारंभ करने के बाद उसका जीवन स्तर बदल जाता है और वह जमीन में न चलकर वाहनों में बैठे बैठे सारे कार्य संपादित करना प्रारंभ कर देता है जिसे लेकर लोगों की टीका-टिप्पणी भी शुरू हो जाती है। ऐसे नेताओं में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का भी समावेश हो गया जिन्होंने नेतागिरी के पूर्व अपनी मेहनत मशक्कत से अथवा उनके वरिष्ठजनों की लगभग 12 एकड़ भूमि से जिंदगी की शुरूवात की थी। लेकिन नेतागिरी में आने के बाद इसकी उड़ान इतनी तेज हो चुकी है कि अल्पावधि में ही इसने सैकड़ों एकड़ भूमि अपने कब्जे में रखने का एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है जिसकी जिले में सर्वत्र चर्चा है। सिहावा विस क्षेत्रांतर्गत आने वाले तथाकथित जनप्रतिनिधि जिसके एवं परिजनों के नाम से 2013 तक क्षेत्र के दो ग्रामों में 8 एकड़ एवं 4 एकड़ कुल 12 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक था। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में इन्होंने 150 एकड़ भूमि लगभग खरीद ली है और 200 से 300 एकड़ भूमि लीज में लेकर उस पर अपना जाल कायम कर लिया है। क्षेत्र में चर्चा तो इस बात की भी है कि एक आईएएस अधिकारी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्य में पदस्थापना है, उनकी काली कमाई को सफेद करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्वाचित होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं, मांगों को लेकर आने वाले लोग उक्त नेता की बाट जोहते रहते हैं। लेकिन महोदय मात्र एक दिन ही अपने कक्ष में बैठकर, कार्य निपटाकर अपने गंतव्य को रवाना हो जाते हैं जिससे दूरदराज से आने वाले शिकायतकर्ताओं, समस्याग्रस्त व्यक्तियों से उनकी भेंट नहीं हो पाती और मायूस होकर वे अपने गांव लौट जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नेतागिरी, समाजसेवा का एक बेहतरीन नमूना होता है। चुनाव के पूर्व लोक-लुभावन सपने दिखाकर चुनाव जीतने के बाद इनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है और वे अपने मतदाताओं को भी नहीं पहचानते, न ही उनकी समस्याओं को लेकर वे गंभीर है जिससे न सिर्फ पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, अपितु उस संस्था का भी काम उपेक्षित हो रहा है। खबर के मुताबिक उक्त नेता ने अचानक इतने बड़े भूभाग को अपने कब्जे में लेकर सभी को चौंका दिया है जिसकी चहुंओर गूंज है। उक्त तथाकथित नेता अब तो मुंगेरीलाल के हसीन सपने की तरह सांसद बनने का सपना भी देखने लगा है। इसका कहना है कि मेरे पास अपार धन संपत्ति है और हर चीज को खरीदने का माद्दा रखता हूं। जैसा कि मैने अपने पैसे के दम पर एक पद खरीद लिया हूं, वैसे आने वाले समय में मैं और ज्यादा बोली लगाकर इससे भी बड़ा पद बोली लगाकर खरीद लूंगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इनके दावे में कितनी सच्चाई है, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस बड़बोले नेता के दावे पर क्षेत्र के लोगों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले इस नेता ने अपने 12 एकड़ खेत को सैकड़ों एकड़ में बदलने के लिये एक विशेष जाति के लोगों के नाम पर भारी भरकम भूमि अधिग्रहण कर उसमें वृक्षों की अवैध कटाई कर पर्यावरण विभाग को एक चुनौति दे रखी है। हरे-भरे बेशकीमती वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कोई देखने वाला नहीं है। इसे लेकर चर्चा है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा भी उक्त बड़बोले नेता के दबाव में आकर यह सब कृत्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं जबकि बेशकीमती फलदार वृक्षों को काटने के पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जाती है और वृक्षों की कटाई के बाद उसके परिवहन के लिये भी संबंधित विभाग के साथ साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से भी अनुमति ली जानी चाहिये। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इस मामले में जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए है। यदि यही कृत्य एक गरीब परिवार के व्यक्ति द्वारा की जाती तो शायद उसके खिलाफ पूरा अमला सक्रिय होकर कार्यवाही कर उसे जेल भेज देता। क्षेत्र के लोगों की मानें तो इनका पूरा काला चिट्ठा आने वाले कुछ दिनों में सार्वजनिक करने की तैयारी में ये लोग जुटे हुए हैं। क्षेत्र के कुछ नागरिकों ने सैकड़ों एकड़ के क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को लेकर वनबल प्रमुख श्रीनिवास राव से अपील की है कि वे बेतहाशा वृक्षों की कटाई की घटना को गंभीरता से लेकर उक्त व्यक्ति बनाम नेता पर उचित कार्यवाही किया जाये।

विजय मिश्रा 'अमित' को सामाजिक समरसता सम्मान

पायनियर संवाददाता ➤ रायपुर
www.dailypioneer.com

बहुप्रतिष्ठित समाज गौरव विकास समिति द्वारा प्रदेश के रंगकर्मी-कलमकार विजय मिश्रा 'अमित' को 'सामाजिक समरसता सम्मान' से विभूषित किया गया। सिविल लाइन रायपुर स्थित वृंदावन सभागार में आयोजित सामाजिक प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने उन्हें साल श्रीफल, सम्मान पत्र देकर अलंकृत किया। कुलपति चंदेल ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी में निहित रीति- रिवाज संस्कार-संस्कृति को बनाए रखने का आव्हान किया।इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व अपर कलेक्टर नोहर राम साहू, गुरु गोरखनाथ अलंकृत आचार्य पुनाराम साहू राज तथा समारोह के संयोजक डॉक्टर सुखदेव राम साहू 'सरस' ने छत्तीसगढ़ को प्रतिभाओं का गढ़ कहते हुए इसके भविष्य को उज्जवल बताया। कार्यक्रम का संचालन ठेठ छत्तीसगढ़ी में करते हुए ऋतुराज साहू ने विभूषित विजय मिश्रा की कला साहित्य यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया हिंदी लोक-रंगमंचों पर वे पिछले पांच दशक से सतत सक्रिय हैं। हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच में बलराज साहनी अवार्ड से विजय मिश्रा अलंकृत हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉ सुखदेव ने आभार प्रदर्शन किया।

नवीन लुनिया का गोलमाल उजागर लेकिन एफआईआर नहीं, पटवारी-कोचिया भी नपेंगे

मामला घुमका सोसाइटी का, 79 एकड़ रकबा में फर्जी तरीके से धान पंजीयन कराने का

प्रशासनिक जांच में सबकुछ स्पष्ट, सख्ती में की जा रही देरी

पायनियर संवाददाता < राजनांदगांव
www.dailypioneer.com

धान खरीदी-बिक्री में बड़ा गोलमाल करने की तैयारी करने वाले व्यापारी व किसान नवीन लुनिया पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जबकि प्रशासनिक टीम ने जांच में यह पकड़ लिया है कि नवीन लुनिया 79 एकड़ का रकबा गिरदावरी में शामिल कर चुका था और उसने धान पंजीयन भी करा लिया है। यदि प्रशासन को भनक नहीं लगती और वह जांच नहीं करती और व्यापारी-किसान नवीन लुनिया सरकार को तकरीबन 51 लाख रुपए का चूना लगा चुका होता। ज्ञात हो कि किसान नवीन लुनिया के पास तकरीबन सवा दौ सौ एकड़ खेत है। उसमें 79 एकड़ रकबा को छोड़कर उसने धान की बोनी की। लेकिन वह कोचियों से मिलकर फर्जी तरीके से बिना बोनी वाले खेत से धान बेचने की प्लानिंग में था, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने 79 एकड़ का रकबा सरेंडर करा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का गोलमाल करने के बाद भी उस पर प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। जबकि जांच में तो यह स्पष्ट हो चुका है कि उसने गलत तरीके से गिरदावरी भी कराई और पंजीयन भी। दोनों ही मामलों में उसका दोष स्पष्ट है। इस कारण उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सप्ताहभर का अधिक समय बीत जाने के बाद भी नवीन लुनिया पर एफआईआर नहीं की गई है।

कोचिया भी आएंगे लपेटे में, पटवारी भी घेरे में

इस पूरे प्रकरण में नवीन लुनिया के साथ हर वह व्यक्ति लपेटे में आएगा, जो उसके इस काले कारनामे में सहभागी बना है। अभी तक तो जो सामने आया कि किसान नवीन कुछ कोचियों के साथ मिलकर धान बेचने की तैयारी में था। इसके अलावा पटवारी भी जांच के दायरे में है। क्योंकि बिना बोनी के जो रिपोर्ट बनी, उसके कारण पटवारी भी संदेह के दायरे में है। कहीं न कहीं उसकी संलिप्तता स्पष्ट है। इसलिए मामले में कार्रवाई होनी चाहिए।

बिना बोनी 50 लाख की धान बेचने की तैयारी में था नवीन लुनिया

पायनियर संवाददाता < राजनांदगांव
www.dailypioneer.com

घुमका सोसाइटी में बिना धान बोए बिक्री करने का मामला सामने आया है। इसमें शहर के व्यापारी नवीन लुनिया का नाम सामने आया है, उसकी घुमका इलाके में तकरीबन 225 एकड़ जमीन है, इसमें 79 एकड़ में उसने बोनी ही नहीं की। लेकिन उसकी

धान खरीदी केन्द्रों में किसानो की समस्या पर जमकर हंगामा

रानीतराई धान खरीदी केंद्र में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष घेराव में पहुंचे

पायनियर संवाददाता < रानीतराइ
www.dailypioneer.com

ब्लाक कांग्रेस कमेटी जामगांव आर के तत्वावधान में धान खरीदी केंद्र में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को धान बेचने में भारी दिक्कत हो रही है। जिला कांग्रेस के निर्देश में सोमवार को डिंडाभाटा धान खरीदी केंद्र में किसानों व कांग्रेश के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी व हंगामे हुई। जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने समिति प्रबन्धक वर्मा व नायब तहसीलदार को दो दिन में धान खरीदी व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो पाटन के सभी समितियो मे चक्काजाम व उग्र आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्वक किसानों ने जिला कलेक्टर एवं कृषि मंत्री के नाम पर ज्ञापन पाटन नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिह को सौंपा गया। वर्ष 2025-26 में धान खरीदी व्यवस्था में गभीर अनियमितताएं एवं अव्यवस्थाएँ पाटन ब्लॉक के अधीनस्थ धान खरीदी केन्द्रों में विभिन्न समस्या सामने आई है। जिसमे ऑनलाइन व ऑफलाइन टोकन वितरण में व्यापक समस्या,किसानों को समय पर टोकन प्राप्त न होने से आर्थिक नुकसान और भीडभाड की स्थिति, धान खरीदी लिमिट में सरलीकरण, धान विक्रय हेतु पंजीयन में परेशानी का निराकरण,केन्द्रों में प्रतिदिन की खरीदी लिमिट को बढ़ाने, तत्काल परिवहन व्यवस्था चालू करने की मांग रखी गई। विधायक प्रतिनिधि अशोक साहू ने अन्नदाता किसानो की परेशानी से दूर सरकार चिरनिद्रा में सोई हुई है।आज छत्तीसगढ़ से सभी किसान हताश, निराश हो गए हैं। राकेश ठाकुर जिलाध्यक्ष, राजेश ठाकुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अशोक साहू विधायक प्रतिनिधि, महेंद्र वर्मा, उमाकांत चन्द्रकर, विष्णु चन्द्रकर, लुल्ली चक्रधारी, सोहन जोशी,भूपेंद्र बघेल, कपूर साहू, देव कुमार निषाद, रश्मि भेद प्रकाश वर्मा जनपद सदस्य, भविष्य कुमार जैन, यादव राम सेन, भोज रघुवंशी, सत्यनारायण टिकरिहा सरपंच, आनंद बघेल जनपद सदस्य, जानकी चोपड़िया सरपंच, द्रौपदी साहू, कमलेश ठाकुर, निखिल साहू, दुकालू राम निषाद, पालेश्वर ठाकुर, ललित ग्रहण, हरीश ठाकुर, हेमू सोनकर,नारद साहू, महेश्वर टिकरिया, राजेश तिवारी, अंकलहू नेताम, कुबेर वर्मा, मुकेश वर्मा, उदयकरण बिजौरा पंच राम निषाद भानूराम वर्मा डोमन चंद्राकर डोमन साहू नारद साहू राम सिंह आगरे रामा साहू विष्णु वर्मा सहित किसान उपस्थित थे।

अम्लेश्वर पालिका में आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को पढ़ाया जाता है नियमों का पाठ, अधिकारी नही कर रहे नियम का पालन

- ढाई महीने से स्थांतरित लेटर को रखे जमे हुए है पालिका में इंजीनियर

पायनियर संवाददाता < अम्लेश्वर
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ शासन नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से प्रदेश के नगरी निकाय में पदस्थ 93 उप अभियंताओं का स्थानांतरण सूची 18 सितंबर को जारी किया गया है। जिसमें कई जगहों के उप अभियंता अभी भी पदस्थ निकाय में जमे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को स्थानांतरण आदेश नगरी प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है जिसमें नगर पालिका परिषद अमलेश्वर के प्रवीण साहू का भी नाम शामिल है। नगरी प्रशासन के नियम अनुसार 15 दिवस के अंदर स्थानांतरित निकाय में पदस्थ होना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन नगर पालिका अमलेश्वर के इंजीनियर प्रवीण साहू नवीन पदस्थ स्थान नगर पंचायत पाटन में जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में ही अंगद की तरह पैर जमा कर बैठे हुए हैं।जबकि उसके स्थान पर पुराने इंजीनियर ढालेंद्र ठाकुर का नव पदस्थ हो गए है। इसका भी स्थांतरण हो गया था जिसे वापस लाया गया है। एक पार्षद ने स्थानांतरण लेटर को शेयर करते हुए मीडिया को स्थानांतरित नहीं होने की जानकारी शेयर किया है। कई जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किस वजह से यहां जमे हुए हैं। समझ से परे है स्थानांतरित जगह पर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब नगर में उठने लगी है आवाज, हो रही है चर्चा। लोगो का कहना है कि नगर पालिका परिषद अम्लेश्वर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियमों का हवाला देकर नगर में मूल भूत सुविधा देने से बचती हैं, रोड नाली, पानी बिजली की समस्या लेकर जाओ तो नियमों का हवाला देकर मुंह बंद कर देती है कहती हैं अवैध कालोनी में कोई सुविधा नहीं मिलेगी नगर पालिका के नियम अनुसार। लेकिन वही सीएमओ आखिर किस नियम के तहत ढाई महीने पहले स्थानांतरण हुए इंजिनियर प्रवीन साहू को रोक कर रखे हुए है। आखिर वह कौन सा काम है जिसे स्थांतरण होने के 80 दिन बाद भी पूर्ण नहीं कर पाया। वही इंजिनियर प्रवीन साहू नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों को नियम का हवाला देकर गुमराह किया जाता है। लोग मूल भूत सुविधाओ के लिए पालिका के आस पास भटकते हुए नजर आते हैं। जनप्रतिनिधियों का फोन तक नही उठाते पालिका के। अधिकारी कर्मचारी इन लोगो के ताना शाही रवैया से जनता जनप्रतिनिधि हलाकान हैं। उक्त विषय में सत्ता पक्ष के पार्षदों में भी नाराजगी देखी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष दयानंद सोनकर का दो टूक इंजिनियर प्रवीन साहू तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है।

रेवा तालाब में पाउंड मशीन का मेगा अभियानः जलकुंभी हटते ही निखरा पानी

दुर्ग नगर निगम ने पाउंड मशीन से साफ हुआ दीपक नगर का रेवा तालाब

पायनियर संवाददाता < दुर्ग
www.dailypioneer.com

शहर के प्रमुख जलस्त्रोतों को स्वच्छ बनाने के लिए दुर्ग नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वार्ड 23 दीपक नगर स्थित रेवा तालाब में आज पाउंड मशीन के माध्यम से बड़े पैमाने पर सफाई कार्य शुरू किया गया। महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग और कर्मशाला विभाग की संयुक्त टीम सुबह होते ही तालाब पहुंची और आधुनिक पोनो मशीन को पानी में उतारा गया। पाउंड मशीन के संचालन के कुछ ही देर बाद तालाब की सतह पर फैली मोटी जलकुंभी की परत हटनी शुरू हो गई और पानी पहले की तुलना में काफी साफ दिखाई देने लगा। इस कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों में भी उत्साह का माहौल रहा। नगर निगम ने हाल ही में शहर के सभी तालाबों का सर्वे किया था, जिसमें कई जलस्त्रोतों में जलकुंभी एवं कचरे की अत्यधिक मात्रा पाई गई। इसे देखते हुए निगम ने आधुनिक तकनीक वाली पाउंड मशीन की मदद से पूरे शहर में सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया।इसी कड़ी में आज रेवा तालाब की सफाई को प्राथमिकता देते हुए अभियान की शुरुआत की गई। पाउंड मशीन, जिसे पोंड गार्बेज क्लीनिंग मशीन भी कहा जाता है, जल स्त्रोतों की सफाई के लिए अत्याधुनिक तकनीक है। यह मशीन पानी की सतह पर तैरते हुए। खरपतवार, प्लास्टिक व अन्य कचरा को एकत्रित कर बाहर निकालती है।इससे तालाब का जलस्तर सुधरता है, पानी का प्राकृतिक रूप सुरक्षित रहता है, मच्छरों के पनपने की समस्या कम होती है, और आसपास की पर्यावरणीय स्वच्छता बेहतर होती है। निगम के अनुसार यह मशीन शहर के अन्य तालाबों, गौरव पथ तालाब, शीतला तालाब, सिविक सेंटर तालाब आदि में भी चरणबद्ध तरीके से लगाई जाएगी। महापौर अलका बाघमार ने कहा शहर के सभी जलस्त्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेवा तालाब में पोनो मशीन के माध्यम से सफाई शुरू की गई है, और जल्द ही अन्य तालाबों में भी यह प्रक्रिया तेज गति से जारी रहेगी। स्वच्छ दुर्ग, सुंदर दुर्ग के संकल्प को हम निरंतर क्रियान्वित कर रहे हैं। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा पोनो मशीन के जरिए सफाई तेजी से और प्रभावी ढंग से हो रही है। इससे न केवल जलकुंभी हटाई जा रही है, बल्कि जल की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। नागरिकों से भी अपील है कि जलस्त्रोतों में किसी भी प्रकार का कचरा न डालें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। पार्षद मनोज सोनी ने कहा दीपक नगर का रेवा तालाब लंबे समय से जलकुंभी से प्रभावित था। अब आधुनिक मशीन से सफाई होने से तालाब का रूप निखर रहा है और स्थानीय नागरिकों को स्वच्छ जलस्त्रोत मिल रहा है। जल संरक्षण और स्वच्छता दोनों दृष्टिकोण से यह कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वर्षों से तालाब में जमा जलकुंभी के कारण जल प्रवाह बाधित हो रहा था, जिससे पानी बदरंग दिखने लगा था। लेकिन पोनो मशीन के उतरते ही बड़ी मात्रा में खरपतवार बाहर निकाला गया तथा तालाब का पानी साफ़ दिखाई देने लगा है।

स्व. कमला देवी साहू की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए इंद्रजीत सिंह

पायनियर संवाददाता < दुर्ग
www.dailypioneer.com

प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की धर्मपत्नी स्व. कमला देवी साहू की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में एच.टी.सी. कंपनी के डायरेक्टर एवं सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह 'छोटू' विशेष रूप से सम्मिलित हुए। उन्होंने कथा व्यास निरंजन महाराज के श्रीमुख से प्रवाहित हो रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धा व भक्ति भाव से रसपान किया। कथा स्थल पर इंद्रजीत सिंह 'छोटू' ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं उनके परिवारजनों से सौजन्य भेंट कर सादर अभिवादन किया तथा दिवंगत स्व. कमला देवी साहू के प्रति पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्व. कमला देवी साहू का संपूर्ण जीवन सेवा, संस्कार और सामाजिक मूल्यों का जीवंत उदाहरण रहा है। इस अवसर पर सर्व समाज कल्याण समिति की ओर से मलकित सिंह 'लल्लू', अनिल चौधरी, जोगा राव, निर्मल सिंह, शाहनवाज़ कुरैशी, रमन राव, इंद्रजीत सिंह 'चिंटू', वाजिद अंसारी, हरेंद्र यादव, सोम सिंह सहित समिति के अनेक सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा स्थल पर संपूर्ण वातावरण भक्ति, श्रद्धा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आया।

गृह ग्राम गनियारी पहुंचने पर अग्निवीर राकेश साहू का स्वागत

महापौर निर्मल कोसरे ने कहा- ये गांव का नहीं, पूरे प्रदेश का गौरव है

पायनियर संवाददाता < भिलाई-3
www.dailypioneer.com

देश की सेवा के लिए युवाओं में बढ़ते उत्साह और सैन्य भर्ती के प्रति गहरी लगन का प्रतीक बन चुके अग्निवीर योजना में चयनित ग्राम गनियारी निवासी राकेश साहू आज अपने गांव लौटे तो ग्रामीणों ने उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया। राकेश साहू, ग्राम गनियारी निवासी इत्वारी साहू के पुत्र हैं, जिनका कुछ माह पूर्व सेना के अग्निवीर भर्ती में चयन हुआ था। वर्तमान में वे जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं। छुट्टी के दौरान जब वे अपने गांव पहुंचे, तो ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने लायक था। घर-आंगन से लेकर चौपाल तक, हर किसी के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। ग्रामवासियों ने राकेश को फूलमाला पहनाकर, तिलक लगाकर और गर्वपूर्ण जयघोषों के साथ सम्मानित किया। बड़े-बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वहीं युवाओं ने उन्हें अपना प्रेरणास्त्रोत बताते हुए कहा कि राकेश की सफलता ने गांव के युवा वर्ग में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा किया है। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे भिलाई-चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने राकेश साहू का सम्मान करते हुए कहा– अग्निवीर राकेश साहू ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह केवल उनके परिवार या ग्राम गनियारी का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली है। सीमाओं पर खड़े ऐसे जांबाज़ युवाओं की वजह से ही हम सब सुरक्षित हैं। राकेश ने यह साबित किया है कि छोटे से गांव का युवा भी बड़ी से बड़ी ऊंचाई छू सकता है। हम सभी उनकी वीरता, समर्पण और सेवाभाव को हृदय से नमन करते हैं।

टोकन का टेंशन : कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा एक- दो दिन में समस्या दूर नही हुआ तो किसानों के साथ करेंगे चक्काजाम

जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने मौके से ही कलेक्टर दुर्ग से किया दूरभाष पर चर्चा , फुंडा धान खरीदी केंद्र का दौरा

पायनियर संवाददाता < पाटन
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है, धान खरीदी प्रक्रिया को करीब 25 दिन होने को हैं, लेकिन दुर्ग जिले में किसान अब भी टोकन के टेंशन से परेशान हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के फुंडा सोसायटी पहुँचने के खबर लगते ही किसान सैंकड़ो की संख्या में पहुँचकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर से धान टोकन को लेकर अपनी समस्याएं बताने लगे। किसानों का कहना है कि सबसे बड़ी परेशानी टोकन की है, सुबह से ही केंद्रों में लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, मगर न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन टोकन मिल पा रहा है, कई किसान बताते हैं कि वे पखवाड़े भर से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिस्टम में टोकन स्लॉट खुल ही नहीं रहा है। उपस्थित किसानों ने सोसायटी द्वारा जारी की जाने वाली 30 प्रतिशत धान का टोकन व्यक्ति विशेष को चिन्हांकित कर दिए जाने का भी आरोप लगाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने तत्काल मौके पर ही कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह से फोन पर चर्चा कर टोकन समस्या से अवगत कराया तथा टोकन लिमिट तत्काल बढ़ाने मांग किया। ठाकुर ने अब तक धान उठाव के संबंध में शासन की निष्क्रियता पर भी चर्चा किया। कलेक्टर दुर्ग ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर को आश्वस्त किया कि धान खरीदी में टोकन की लिमिट जल्द बढ़ाने आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा धान उठाव के संबंध में शासन को पत्राचार भी कर रहे है। पूरे मामले की जानकारी काँग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने फ़ोन के माध्यम से एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव को भी दिया और कहा कि टोकन का समस्या एक या दो दिन में ठीक नही हुआ, लिमिट नही बढ़ाया गया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ चक्काजाम करेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रसाशन की होगी। ठाकुर ने राज्य की भाजपा सरकार के नियत में खोंट बताते हुवे धान नही खरीदने का षड्यंत्र बताया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, जनपद सदस्य आनंद बघेल, दिना वर्मा, धनी वर्मा, डुमन वर्मा, विजय चिलक, सुंदर सैन, चेतन बंजारे, राजेश वर्मा, गोपाल, गोकुल देशलहरा, हरीश ठाकुर, लोचन यादव, पालेश्वर ठाकुर, भोलेश्वर वर्मा, गिरधर साहू, हुल्लेश्वर पटेल, कैलाश साहू, ईश्वर चंद्राकर, दीपेश बंजारे, मिथलेश शर्मा, राजू शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, जितेंद्र वर्मा, मनोज वर्मा, नारायण वर्मा, सुरेश चेलक, निखिल दास, नागेंद्र वर्मा, श्यामा मनहर, रेवा वर्मा, रीतकरण वर्मा, बोनू निर्माण, तुला राम निर्मल,भगवती साहू, मनोहर वर्मा सहित सैंकड़ो की संख्या में किसान मौजूद थे।

कार्यालय नगर पंचायत डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
Email :- npdongargaon@gmail.com, Ph-07745-271639

क्रमांक/2258/राजस्व/न.प./2025-26 डोंगरगांव, दिनांक 08/12/2025

// दावा आपत्ति सूचना //

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद के सदस्यों द्वारा दिनांक 13/05/2025 को थोक सब्जी व्यापारियों का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पश्चात सूची तैयार की गई जिस पर दावा / आपत्ति आमंत्रित किये जाने के संबंध में परिषद की बैठक दिनांक 11/08/2025 के संकल्प कमांक 07 द्वारा परिषद के सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दावा/आपत्ति आमंत्रण किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अतः जिस किसी व्यक्ति को थोक सब्जी व्यापारियों की भौतिक सत्यापित सूची के संबंध में दावा/आपत्ति हो वह इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी दावा/आपत्ति लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि उपरांत की गई दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डोंगरगांव

न्यायालय तहसीलदार सरायपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.)

// ईश्तहार //

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक दौलतराम सिदार पिता मैनसिंग सिदार जाति गोड़ निवासी ग्राम बूटीफली तहसीलदार सरायपाली जिला महासमुन्द द्वारा उसके स्वयं के पुत्र ओंकेश्वर सिदार का जन्म/मृत्यु दिनांक 25/07/2023 को ग्राम पुजारीपाली में हुआ है। उक्त जन्म का पंजीयन नहीं हो पाने के कारण उक्त तिथि में आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आक्षेप/दावा हो अथवा आवेदन प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनाँक 12/12/2025 को उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
सरायपाली

कार्यालय कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

// अधिसूचना //

धारा-04, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

क्र./1943/भू-अर्जन/2025 रायपुर, दिनांक 24/11/2025

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2023 की धारा 04 में सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आशयित है, अर्थातः-

		भूमि का विवरण			लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	खरोरा	भरुवाडीह खुर्द प.ह.नं.33	कुल खसरा 06	कुल रकबा 0.3962 हेक्टेयर	मोहरेंगा से कठिया (मोहरा) मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य हेतु
योग				0.3962 हेक्टे.	

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक सामाधान निर्धारण सहमति तथा जन सुनवाई दिनांक 23/12/25 को समय 11:30 बजे स्थान पंचायत भवन में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार हैः-

01 लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण :- सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण
02 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- 06
03 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- निरंक
04 प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक
05 प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक
06 क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है :- हॉ
07 क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है :- हॉ
08 परियोजना की कुल लागत :- निरंक
09 परियोजना से होने वाला लाभ :- सुगम यातायात
10 प्रस्तावित सामाजिक सामाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय :- 5.00 लाख
11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक :- निरंक

उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(डॉ. गौरव कुमार सिंह)
कलेक्टर, रायपुर एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

G-252605298/2

संपादकीय

सशस्त्र बल झंडा दिवस

राष्ट्र का सम्मान और कृतज्ञता

सात दिसम्बर का दिन भारत के लिए केवल एक औपचारिकता भर नहीं बल्कि कृतज्ञता का ज्वार है। यह वह अवसर है जब पूरा राष्ट्र अपने उन वीरों को याद करता है जिनकी बदौलत हम अपनी धरती पर सुरक्षित और स्वतंत्र सांस ले पाते हैं। सशस्त्र बल झंडा दिवस देश के शौर्य, समर्पण और पराक्रम की स्मृति को सहेजने का दिन है। यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र का वह उजला पहलू है जो बताता है कि भारत अपने सिपाहियों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और आभार प्रकट करने में कभी पीछे नहीं हटता। झंडा दिवस का इतिहास भले ही 1949 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से शुरू हुआ हो, पर इसकी भावना अनादिकाल से भारतीय समाज में जीवित रही है। यह भावना हर उस परिवार के साथ खड़ी रहती है जिसका कोई सदस्य सीमा पर राष्ट्र की रक्षा में तैनात है। भारत के जवान जब बर्फीली चोटियों पर, मरुस्थल की तपती रेत में, समुद्र की गहराइयों में या आसमान की ऊंचाइयों पर डटे रहते हैं, तब 7 दिसम्बर का यह दिन उनकी ताकत बनकर सामने आता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सैनिक केवल बॉर्डर पर नहीं लड़ता, बल्कि उसका परिवार भी हर दिन त्याग और धैर्य का दायित्व निभाता है। सरकार इस दिन के आयोजन को केवल औपचारिकता नहीं मानती, बल्कि इसे एक ऐसी राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझती है जो सैनिकों के प्रति उसके संकल्प को मजबूती देती है। झंडा दिवस के माध्यम से जो निधि एकत्र की जाती है, उसका उपयोग घायल सैनिकों के उपचार, पुनर्वास, विकलांग सैनिकों की सहायता, वीर नारियों की आर्थिक सुरक्षा और शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है। यह सहायता केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होती है। इससे जवानों को यह भरोसा मिलता है कि उनकी कुर्बानी देश कभी नहीं भूलता और उनका परिवार राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज के समय में जब सुरक्षा की चुनौतियां बहुआयामी हो चुकी हैं, तब झंडा दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। यह वह क्षण है जब सरकार और जनता दोनों एकजुट होकर सेना के साथ खड़े होते हैं। सरकार जवानों की आवश्यकताओं को समझते हुए आधुनिक हथियारों, उन्नत तकनीकों और बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करती है, वहीं समाज इस दिन के माध्यम से यह दिखाता है कि वह केवल सुरक्षा का लाभ नहीं उठाता बल्कि उसकी कीमत को भी समझता है। झंडा दिवस का संदेश यही है कि देश की सुरक्षा केवल फौजी चौकियों से नहीं बल्कि नागरिकों की भावनाओं, समर्थन और सहभागिता से भी मजबूत होती है। सेना के तीनों अंग इस दिन देशवासियों तक पहुंचते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से लोगों को अपने कार्यों और चुनौतियों से अवगत कराते हैं। यह केवल फौजी ताकत का प्रदर्शन नहीं होता बल्कि यह जनता और सेना के बीच भावनात्मक पुल को और मजबूत बनाता है। स्कूलों में, दफ्तरों में और सार्वजनिक स्थलों पर जो छोटे-छोटे झंडे लगाए जाते हैं, वे केवल प्रतीक भर नहीं, बल्कि अपने जवानों के प्रति सर्वोच्च सम्मान की अभिव्यक्ति हैं। झंडा दिवस समाज में सेवा और सहयोग की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रनिर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिकों की भी समान भूमिका है। जब हम झंडा दिवस को मनाते हैं, तब हम उस मूल भावना को स्वीकार करते हैं कि देश पहले है और उसके रक्षक सर्वोपरि हैं। उनकी हर जरूरत, हर तकलीफ और हर संघर्ष हमसे जुड़ा है। सैनिकों के लिए एकत्र किया गया धन उस विश्वास का संबल है कि जब जवान हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, तो हम उसके परिवार की सुरक्षा के लिए खड़े हैं।

जल स्वशासन को नई मजबूती

डॉ. संजय सिंह
जल वैज्ञानिक
जल जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक

भारत फिलहाल जल-संकट के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (उऋइ) की राष्ट्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 193 जिले ऐसे हैं, जहाँ भूजल की स्थिति संकटपूर्ण बनी हुई है। इनमें से 102 जिले गंभीर और 22 जिले अतिझगंभीर श्रेणी में आते हैं। यह स्थिति लगातार खराब हो रही है—2024 के डेटा के अनुसार भारत की कुल भूजल निकासी 62% तक पहुँच गई है और 87% भूजल कृषि में उपयोग हो रहा है। (उळ्ए रिपोर्ट 2024)

ऐसे समय में भारत सरकार का हालिया निर्णय—कि अत्यधिक जल-संकटग्रस्त जिलों में मनरेगा की 65% राशि केवल जल संरक्षण और पुनर्भरण के कार्यों पर खर्च की जाएगी—ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। सेमी-क्रिटिकल जिलों के लिए यह सीमा 40% तय की गई है।

भारत के ग्रामीण इलाकों में जल संकट किसी एक कारण का परिणाम नहीं है; यह अनेक संरचनात्मक, भौगोलिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सम्मिश्रण है। बदलती वर्षा-पद्धति, बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन इस समस्या को और जटिल बनाते हैं। क्टऊकी 2024 रिपोर्ट बताती है कि पिछले तीन दशकों में भारत में औसत वर्षा में 8झ10% की कमी आई है, जबकि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में यह कमी 12झ14% तक दर्ज की गई है। 1990 की तुलना में भारत में ल्र्ीइ६५ी ८िर 125% बढ़े हैं। पिछले दो दशकों में देश के कई इलाके बुंदेलखंड, बीजापुर, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भूमिगत जल स्तर निरंतर गिरा है। ऐसे में मनरेगा की धनराशि को जल संरक्षण में प्राथमिकता देना न केवल नीति-आधारित निर्णय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा से जुड़ा कदम भी है।

दुनिया के उन देशों ने, जहाँ पानी की उपलब्धता सीमित है—जैसे इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन—ने जल संरक्षण की सफलता का राज तीन प्रमुख सिद्धांतों में पाया है: रनऑफ को अधिकतम रोकना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना, और समुदाय की सक्रिय भागीदारी। भारत में भी जहाँ इन सिद्धांतों पर कार्य हुआ, वहाँ उल्लेखनीय सफलता मिली है। महाराष्ट्र के 'जलयुक्त शिवार' अभियान में 2015 से 2019 के बीच लगभग 27,000 गाँवों में भूजल स्तर में 0.5झ2 मीटर तक की वृद्धि दर्ज हुई। राजस्थान के अलवर में सामुदायिक जोहड़ों और तालाबों ने 12 सूखी नदियों को पुनर्जीवित किया। मध्यप्रदेश के देवासझखंडवा मॉडल में वाटरशेड आधारित कार्यों से सिंचाई क्षमता 30झ40% तक बढ़ी। ये उदाहरण बताते हैं कि जब वैज्ञानिक भू-आकृति विज्ञान, जल-बजट और वाटरशेड सिद्धांतों के साथ काम होता है, तो परिदृश्य बदल सकता है।

मनरेगा के 65 फीसद फंड को जल-संरक्षण में लगाने का महत्त्वपूर्ण निर्णय
सरकार के इस निर्णय से देश में बन सकते हैं जल संपन्न गाँव
जल संचयन जन भागेदारी से जल संरक्षण के सफल होंगे प्रयास

मनरेगा भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, जिसका ढांचा सामुदायिक भागीदारी और श्रम आधारित निर्माण पर आधारित है। 2023झ24 में मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक जल-संरक्षण संरचनाएँ बनाई गईं—जिनमें 4.2 लाख चेकडैम, 6.1 लाख खेत-तालाब, 2.5 लाख कंटूर-बंडिंग, और 1.8 लाख गली-प्लग शामिल हैं। लेकिन इन संरचनाओं की गुणवत्ता और वैज्ञानिकता हमेशा एक जैसी नहीं होती। यदि सरकार के नए निर्णय को सही दिशा और तकनीकी आधार दिया जाए, तो इससे सूखे क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण बढ़ेगा, छोटे-छोटे तालाब और पहाड़ी नालों की पकड़ क्षमता बेहतर होगी, कृषि उत्पादन और पशुधन पर पड़ने वाला दबाव कम होगा, और अनेक स्थानों पर छोटी नदियाँ और झरने पुनर्जीवित हो सकते हैं। विशेष रूप से बुंदेलखंड, जहाँ पिछले दो दशकों में वर्षा में लगातार गिरावट और तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, वहाँ जल-संरक्षण कार्य ही भविष्य की जीवनरेखा बन सकते हैं।

योजनाएँ चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हों, यदि ग्राम पंचायतें सक्रिय न हों तो संरचनाएँ केवल कागज़ पर ही सीमित रह जाती हैं। जीपीडीपी स्तर की योजनाओं में जल संरक्षण को प्राथमिकता तो दी गई है, लेकिन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं, कई पंचायत प्रतिनिधियों में उदासीनता, ग्राम सभा जैसी इकाई की निष्क्रियता, और समितियों—जैसे पेयजल समिति व जल-सुरक्षा समिति—की कमजोर भूमिका सबसे बड़ी रुकावट हैं। अटल भूजल योजना, जो नौ राज्यों की 6,000 से अधिक पंचायतों में लागू की गई थी, इसका उदाहरण है। नीति उत्कृष्ट थी, लेकिन पंचायतों की वास्तविक क्षमता और तकनीकी समझ कमजोर होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।

जहाँ-जहाँ महिलाओं को जल प्रबंधन में नेतृत्व मिला है, वहाँ परिणाम अधिक सकारात्मक देखे गए हैं। बुंदेलखंड की जल-सहेलियाँ इसका सशक्त उदाहरण हैं। इनके नेतृत्व में गाँवों में जल-संरक्षण की नियमित निगरानी, संरचनाओं का रखरखाव, और जल बजट का व्यावहारिक उपयोग संभव हो सका है। यदि ऐसे मॉडलों को पूरे देश में अपनाया जाए तो पंचायत स्तर पर जल-कैडर तैयार हो सकता है, जो योजनाओं को स्थायी बना सके।

आने वाले वर्षों में जल-संकट केवल बढ़ेगा। उहउ और नीति आयोग के 2024झ25 अनुमानों के अनुसार 2030 तक भारत की 40% आबादी पानी की कमी झेल सकती है। 2050 तक पानी की मांग 20% बढ़ जाएगी, जबकि उपलब्धता और भी घटती जाएगी। ह्री३'ह्लरि और तालाबों की हालत भी चिंता का विषय है—2024 के आँकड़ों के अनुसार भारत के 65% से अधिक ध्री३'ह्लरि खतरे में हैं, और देश के लगभग 10 लाख पारंपरिक तालाब/झीलें अस्तित्व खोने की कगार पर हैं। ऐसे में केवल धनराशि खर्च करना समाधान नहीं है। इसके लिए जरूरी है वैज्ञानिक जल-शासन (हंशी१ ऋक्ष्ष्१ह्ळ्ळी), भू-आकृति आधारित योजना, जल-उपयोग दक्षता, वर्षा-पानी का वैज्ञानिक संग्रह, और मजबूत निगरानी तंत्र।

मनरेगा से मिलने वाली 65% राशि तभी प्रभावी होगी जब निर्माण गुणवत्ता, निगरानी और सामुदायिक साझेदारी साथ-साथ हों। सरकार का यह निर्णय भारत के भविष्य की जल-सुरक्षा का खाका भी है। यदि मनरेगा की धनराशि को सही दिशा दी जाए, पंचायतों की क्षमता विकसित हो, महिलाओं का नेतृत्व बढ़े, और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित संरचनाएँ बनें, तो भारत के सूखे क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन संभव है। यह निर्णय गाँवों को जल-संपन्न बनाने, नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित करने, हरियाली और जैव-विविधता को बढ़ाने, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की क्षमता रखता है।भारत का जल-संकट गंभीर है, लेकिन समाधान असंभव नहीं। यदि नीति, समुदाय और विज्ञान—ये तीनों साथ आएँ तो भारत सचमुच पानीदार गाँवों वाला देश बन सकता है ।

आयोग का विशेष क्षेत्राधिकार और चुनाव सुधार

वर्तमान में जारी एसआईआर प्रक्रिया पहला अवसर नहीं है, जब चुनाव आयोग एक व्यापक मतदाता सूची तैयार कर रहा है। हालांकि इस बड़े पैमाने के कार्यक्रम के लिए कोई निश्चित समय सारिणी, जैसे हर 10 साल में एक बार या ऐसी कोई अन्य अवधि, निर्धारित नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि जब तक यह आवधिक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, चुनाव परिणाम जनभावना को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करेंगे।

स्वपन दासगुप्ता

पचास साल से भी अधिक समय पहले, भारतीय राजनीति के एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश विद्वान ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की थी कि चुनाव उन चीज़ों में से एक हैं जिन्हें भारतीय बहुत अच्छे से संपन्न करते हैं।र भारतीय लोकतंत्र के स्थायी रूप से स्थगित हो जाने या 'निर्देशित' हो जाने की आशंका (जो पूरी तरह से गलत नहीं थी) की पृष्ठभूमि में, चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को सार्वजनिक जीवन की एक उद्धारक विशेषता के रूप में देखा जाता था। लोकतंत्र के इस प्राथमिक स्तंभ की अंतिम पुष्टि 1977 में तब हुई, जब आपातकाल की छाया के बावजूद, भारत के मतदाताओं ने एक अधिनायकवादी शासन को वोट के जरिये सत्ता से बाहर कर दिया।

चुनाव आयोग (ईसीआई) की यह सुनिश्चित करने की क्षमता कि जनमानस की इच्छा विधायिकाओं में परिलक्षित हो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पिछले सात दशकों में बार-बार परखी गई है। हालाँकि, मार्ग से विचलित होने के उदाहरण मौजूद हैं—इनमें 1972 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 1987 का जम्मू-कश्मीर चुनाव, दो उल्लेखनीय उदाहरण हैं— लेकिन, भारत का चुनावी अनुभव आमतौर पर राजनीतिक प्रणाली की वैधता बनाए रखने में सहायक रहा है।

जैसा कि सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) में होता है, जो विधायी बहुमत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती है, ऐसे उदाहरण भी हैं, जब हारने वाले लोग हैरानी में रह गए जिनके चुनावी अभियान के अनुभव परिणाम से मेल नहीं खाते थे। 1971 में, एक पराजित पक्ष ने जोर देकर कहा कि सोवियत-निर्मित 'अदृश्य स्याही' के उपयोग ने इंदिरा गांधी को शानदार जीत हासिल करने में मदद की। उपग्रह द्वारा ईवीएम के हेरफेर के ऐसे ही अविश्वसनीय दावे 2009 के आम चुनाव के बाद भी सुने गए थे। जो कभी साजिश सिद्धांतकारों का विशेषाधिकार हुआ करता था, वह पिछले वर्ष अब हाशिए का मुद्दा नहीं रहा है। अपनी पार्टी के संख्या-विश्लेषकों से प्रोत्साहित होकर, जिनकी भविष्यवाणियाँ परिणाम से भिन्न थीं, विपक्ष के नेता ने मतदाता सूचियों की सत्यता को चुनौती दी है। जोरदार दावे किए गए हैं कि चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण का उपयोग कर अल्पसंख्यक मतदाताओं को इस आधार पर बाहर करने पर विचार कर रहा है कि वे भारतीय नहीं भी हो सकते हैं। यह विवाद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दलों के बीच खींचतान का विषय बन चुका है और यह असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी फैल सकता है।

चूंकि संविधान का अनुच्छेद 321 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन के संबंध में 'विशेष क्षेत्राधिकार' देता है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा गया है। दशकों से चुनाव आयोग ने चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई नवाचार पेश किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपायों में आदर्श आचार संहिता शामिल है, जो अप्रिय राजनीतिक व्यवहार पर अंकुश लगाती है और ईवीएम ने वोटों में हेरफेर को और अधिक कठिन बना दिया है, हालांकि यह असंभव नहीं है। अब मतदान केंद्रों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए नियम मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ, चुनाव आयोग मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों पर जोर दे रहा है, ताकि मर्यादा बनी रहे तथा मतदान अधिकारियों और मतदाताओं को डराया-धमकाया न जा सके।

निश्चित रूप से, यह सच है कि इन नवाचारों में से कोई भी पूरी तरह से दोषरहित नहीं है। मतगणना केंद्रों सहित स्थानीय स्तर पर अक्सर बाहुबल का प्रभाव रहता है और इसके संभावित रूप से विकृत परिणाम हो सकते हैं। मतदान अधिकारियों द्वारा हेरफेर के अनुभवजन्य प्रमाणों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। जब संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, तो संभव है कि देश को आदर्श लोकतांत्रिक आचरण के अन्य विचलनों के बारे में सुनने को मिले, जिनका चुनाव आयोग द्वारा समाधान किये जाने की आवश्यकता है।लोकतांत्रिक परियोजना में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में, संसद को आम जनता के लिए अपने व्यापक चुनाव अनुभव को संकलित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अच्छी राजनीति के बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी यदि राजनीतिक कार्यपालिका चुनाव आयोग के खिलाफ आम धमकियों, जिसमें शारीरिक नुकसान भी शामिल है, का इशारा करती है और सरकारी अधिकारियों—जिनके शालीन आचरण पर पूरी प्रणाली निर्भर करती है—को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकती है। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान सत्तारूढ़ दल का आचरण शर्मनाक है। कहने की जरूरत नहीं है कि सटीक मतदाता सूची का अस्तित्व लोकतंत्र की मूल शर्त है। यदि वंचित समुदायों के सदस्य मतदान केंद्रों से दूर रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं, तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है। दुर्भाग्यवश, इस बात का विरोध काफी कम होता है, जब बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाता है या दोहरी और तिहरी प्रविष्टियाँ होती हैं, जो परिणाम को प्रभावित कर सकती है। चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र और तस्वीरों के माध्यम से धोखाधड़ी की समस्या को सुलझाने की कोशिश की है। हालांकि, धोखेबाजों ने मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित लोगों के नाम पर वोट देकर चुनाव प्रणाली को चकमा देने के तरीके भी निकाल लिए हैं। पूर्वी भारत में अतिरिक्त समस्या यह है कि मतदाता सूचियों में उन व्यक्तियों को जोड़ दिया गया है, जो भारतीय चुनावों में वोट देने के लिए अयोग्य हैं। वर्तमान में जारी एसआईआर प्रक्रिया पहला अवसर नहीं है, जब चुनाव आयोग एक व्यापक मतदाता सूची तैयार कर रहा है। हालांकि इस बड़े पैमाने के कार्यक्रम के लिए कोई निश्चित समय सारिणी, जैसे हर 10 साल में एक बार या ऐसी कोई अन्य अवधि, निर्धारित नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि जब तक यह आवधिक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, चुनाव परिणाम जनभावना को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करेंगे।

20वीं सदी के शुरुआती दशकों में आयरलैंड के संदर्भ में कहा जाता था कि लोगों को 'जल्द वोट दें और अक्सर वोट दें' की सलाह दी जाती थी। एक उत्साही शोधकर्ता के लिए यह दस्तावेज बनाने लायक हो सकता है कि भारत के कुछ हिस्सों में किस प्रकार की अभिनव प्रथाएँ प्रचलित हैं, जैसे मृत व्यक्तियों द्वारा मतदान या एक उम्मीदवार के मतों का उसके प्रतिद्वंद्वी के खाते में सहजता से स्थानांतरित हो जाना। एसआईआर रचनात्मक राजनीति के इन सभी उदाहरणों को इतिहास में नहीं बदल देगा, लेकिन यह वैश्विक भरोसे में थोड़ी और दृढ़ता जोड़ेगा कि भारत अपनी चुनाव प्रक्रियाओं को अच्छे से संचालित करता है। आशा यह है कि आने वाले दशकों में किसी भी राज्य या क्षेत्र के बारे में यह नहीं कहा जाएगा कि वहाँ चुनाव नहीं होते, बल्कि उन्हें 'प्रबंधित' किया जाता है।

आप की बात

गोवा अग्निकांड: सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही का नतीजा

महोदय, गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी विनाशकारी आग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश में सुरक्षा इंतजामों पर चल रही लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। किचन में गैस सिलेंडर फटते ही धुएं का घना बादल पलभर में पूरे क्लब में फैल गया और सौ से अधिक लोगों की मौजूदगी वाले इस भीड़भरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सबसे अधिक मौतें दम घुटने से हुईं, जो यह बताती हैं कि न तो आपातकालीन निकास सही थे, न ही धुएं को बाहर निकालने की कोई आधुनिक व्यवस्था मौजूद थी। तीन झारखंडी युवकों सहित 25 लोगों की मौत ने कई परिवारों को तबाह कर दिया, जबकि क्लब मालिक और प्रबंधन पर लापरवाही का मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल यह नहीं कि किस पर मामला दर्ज हुआ,सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों दोहराई जाती हैं। दरअसल देश में सुरक्षा निरीक्षण का पूरा ढांचा ही एक तरह से रस्मी औपचारिकता बनकर रह गया है। जिन अधिकारियों पर अग्निशमन मानकों की जांच का दायित्व है, वे नियमित निरीक्षण की जगह महज़ उपस्थिति दर्ज कराने, अनियमित वसूली करने और कागजी खानापूर्ति करने में लगे रहते हैं। नतीजा यह कि क्लब, होटल, बस, फैक्ट्री या स्कूल,हर जगह सुरक्षा उपकरण या तो खराब मिलते हैं, या मौजूद ही नहीं होते; हाल ही में स्कूलों की जांच में यह बात साफ सामने भी आ चुकी है। कोई भी बड़ा हादसा कुछ दिनों तक हलचल पैदा करता है, मगर कुछ हफ्ते गुजरते ही सब कुछ भूलकर व्यवस्था उसी ढर्रे पर लौट आती है और मौतें फिर किसी अग्निकांड या औद्योगिक दुर्घटना के रूप में सामने आ जाती हैं। अब वक्त आ गया है कि सरकार निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कड़े कानून बनाए, जिनमें लापरवाही साबित होते ही तत्काल निलंबन, सेवा से बर्खास्तगी और दंडात्मक कार्रवाई को अनिवार्य किया जाए। सबसे बड़ा सुधार यह होगा कि जिनकी लापरवाही से लोगों की जान जाती है, उनके वेतन, पेंशन और संपत्ति से ही मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि जिम्मेदारी का वास्तविक दबाव पैदा हो। जब तक नियमों को केवल कागज़ पर पूरा करने की संस्कृति खत्म नहीं होगी और निरीक्षण को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की मौतें रोकी नहीं जा सकेंगी। सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि मूल अधिकार है, और जब व्यवस्था इसे सुनिश्चित करने में विफल होती है तो यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि प्रबंधकीय अपराध बन जाता है,जिसका समाधान कठोर जवाबदेही, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के वास्तविक डर से ही संभव है।

सुभाष बुड़ावन वाला,रतलाम.मप्र

विमान यात्रियों का आर्थिक मुंडन रोकें

यह पत्र रजनीश कपूर के लेख, ''अब हवाई यात्रा भी बन गई आफत'' के संदर्भ में है अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत बनाए गए नियमों का इंडिगो ने उल्लंघन किया है इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से अन्य एयरलाइनों ने हवाई किराये में मौके की नजाकत देखकत बढ़ोतरी कर दीं आनन-फानन में कुछ विमान यात्री तत्काल प्रीमियम बुकिंग देकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें डीजीसीए और इंडिगो की लापरवाही के कारण लोगों के कीमती समय , ऊर्जा एवं और धन की बर्बादी का हर्जाना मिलना एवं जुर्माना लगना समय की कानूनी आवश्यकता है डीजीसीए एक नियामक संस्था के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल दृष्टिगोचर हुई है एवं साख पर बट्टा लगता दिख रहा है नौकरी के नियम शर्तों में वर्णित समय सीमा से ज्यादा समय तक विमान उड़ाने से पायलटों को भौतिक मनोवैज्ञानिक थकान होती है, तो दुर्घटना का अंदेशा भी बढ़ता है विमानों के बढ़ते रखरखाव खर्च एवं प्रतियोगिता के चलते विमान यात्रियों का आर्थिक मुंडन रोकने के लिए डीजीसीए नियमों में कोताही ना बरते लापरवाही के मामलों को माननीय न्यायपालिका स्वत संज्ञान में लेने की कृपा करें

युगल किशोर शर्मा, फ़रीदाबाद

ऑनलाइन उपस्थिति—सबके लिए क्यों नहीं?

प्रदेश के शिक्षक वर्ग का सरकार की किसी भी सुधारात्मक व्यवस्था का विरोधी कभी नहीं रहा है ।शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली हर पहल का शिक्षकों ने स्वागत किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। मगर प्रश्न यह है कि ऑनलाइन उपस्थिति जैसी व्यवस्था केवल शिक्षकों तक ही सीमित क्यों है ? यदि यह व्यवस्था प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनिवार्य है, तो फिर वल्लभ भवन से लेकर तहसील,जनपद, पंचायत तक सभी विभागों के अधिकारीझकर्मचारी इस दायरे में क्यों न आएँ ? कोई भी नियम यदि 'समानता' और 'जवाबदेही' के आधार पर लागू किया जाए, तभी वह प्रभावी सिद्ध होता है । पिछले एक दशक के बोर्ड परीक्षा परिणाम गवाह हैं कि प्रदेश के सरकारी शिक्षकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद निजी विद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है ।यह उपलब्धियाँ शिक्षकों की प्रतिबद्धता और परिश्रम का प्रमाण हैं ।ऐसे में केवल शिक्षकों पर कठोर निगरानी और बाकी विभागों को स्वतः मुक्त रखना सवाल खड़े करता है ।चिंता का दूसरा बिंदु यह है कि शिक्षकों की निगरानी हेतु पहले से ही ब्लॉक, जिला एवं संकुल स्तर पर अनेक अधिकारी तैनात हैं। यदि ऑनलाइन उपस्थिति ही अंतिम समाधान है, तो फिर इतना विशाल निगरानी तंत्र किस उद्देश्य से बना हुआ है? क्या यह स्वीकार किया जाए कि वर्षों से खड़ा यह तंत्र निष्प्रभावी रहा है? यदि ऐसा है, तो उसकी समीक्षा एवं पुनर्विनियोजन होना चाहिए। प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में निगरानी में लगे कार्मिकों को शिक्षण कार्य में लगाया जाए तो विद्यालयों में वास्तविक सुधार अधिक तेज़ी से संभव है ।सच यह है कि शिक्षक समय का पालन करते हैं क्योंकि उनका समय सीधे बच्चे के भविष्य को प्रभावित करता है। पर क्या शेष विभागों का समय जनता के जीवन को प्रभावित नहीं करता? क्या आम नागरिक कार्यालयों के बाहर घंटों प्रतीक्षा नहीं करते? यदि शिक्षकों के लिए समय पालन अनिवार्य है, तो वही कठोरता हर विभाग पर लागू क्यों नहीं ? हमारी विनम्र परंतु ठोस अपेक्षा है कि राज्य सरकार ऑनलाइन उपस्थिति को 'एक विभाग' का नहीं, बल्कि 'पूरे प्रशासन' का नियम बनाए। तभी पारदर्शिता का वास्तविक अर्थ सामने आएगा और जनता का भरोसा बढ़ेगा।

अरविंद रावल 51, गोपाल कॉलोनी, झाबुआ (म.प्र.)

पंडरिया का विकास मॉडल: विधायक भावना बोहरा के 2 वर्ष, छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई पहचान बनी

पायनियर संवाददाता < कवर्धा
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ की राजनीति में पंडरिया विधानसभा विकास, सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व का राष्ट्रीय उदाहरण बनकर उभर रही है। विधायक भावना बोहरा के दो वर्षों का कार्यकाल न केवल उपलब्धियों से भरा रहा, बल्कि उनके मानवीय निर्णयों और त्वरित कार्यशैली ने उन्हें प्रदेश के सबसे सक्रिय व प्रभावी जनप्रतिनिधियों में शामिल कर दिया है।

मानवीयता का अद्वितीय उदाहरण — अनाथ बच्चों को दिया जीवनभर का सहारा

कुकदूर के पास तेंदूपत्ता तोड़कर लौटते समय हुए हादसे में अनाथ हुए सेमरहा के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी–शिक्षा, पालन-पोषण और भविष्य तक–विधायक भावना बोहरा ने स्वयं उठाई। जिला पंचायत सदस्य दीपा धुर्वे कहती हैं, विधायक पहली बार ऐसी देखी जा रही हैं, जो अनाथ बच्चों के लिए मां की तरह खड़ी हो जाती हैं। यह कदम क्षेत्र में संवेदनशीलता और जनसेवा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।

सड़क, बिजली, पेयजल— अधोसंरचना में रिकॉर्ड सुधार

भाजपा नेता उतरा गोकुल साहू के अनुसार, पंडरिया में वर्षों से लंबित सड़कें और जर्जर मार्ग आज पूरी तरह बदल चुके हैं। ग्रामीण संपर्क मार्गों का विस्तार, खेतों तक सुगम पहुंच, पेयजल संकट वाले गांवों में हैंडपंप मरम्मत, नए पंप और टैंकर आपूर्ति इन कदमों ने ग्रामीण जीवन को नई राहत दी है।

बेटियों के लिए निःशुल्क बस सेवा — प्रदेश में पहली पहल

भाजपा मंडल अध्यक्ष दुल्लापुर फलित साहू बताते हैं कि पंडरिया-पांडातराई कॉलेज जाने वाली बेटियों को सुरक्षित, सुगम और मुफ्त परिवहन सुविधा ने क्षेत्र में महिला शिक्षा को नई दिशा दी है। यह पहल पूरे प्रदेश में एक सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक मॉडल बन रही है।

हर मंडल में विधायक कार्यालय — जनता तक सीधी पहुंच का नया सिस्टम

भाजपा मंडल अध्यक्ष पांडातराई प्रदीप गोस्वामी के अनुसार, यह पहला मौका है जब किसी विधायक ने पूरे विधानसभा के प्रत्येक मंडल में स्थायी विधायक कार्यालय खोले हैं। समस्याओं का तत्काल पंजीकरण, त्वरित समाधान, मुफ्त एंबुलेंस और मोबाइल हेल्थ यूनिट, इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक पहुंच बेहद मजबूत हुई है।

युवाओं और बच्चों के लिए 'फ्री कोचिंग सेंटर' -शिक्षा में नई क्रांति

नगर पालिका पंडरिया उपाध्यक्ष सुमित तिवारी बताते हैं कि पंडरिया नगर में प्रारंभ हुआ निःशुल्क कोचिंग सेंटर, जिसे जनता 'भविष्य निर्माण केंद्र' कहती है, बच्चों के लिए बड़ा अवसर बनकर उभरा है। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित हरि नाला पुलिया का निर्माण पंडरिया के बड़े विकास कार्यों में शामिल है।

विधायक भावना बोहरा की 2 वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

ग्रामीण सड़कों में बड़े पैमाने पर सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर प्राथमिक फोकस, निःशुल्क एंबुलेंस और मोबाइल हेल्थ यूनिट, प्रत्येक मंडल में विधायक कार्यालय, बेटियों के लिए निःशुल्क बस सेवा, अनाथ बच्चों की जीवनभर की जिम्मेदारी, युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर, पुलिया, सामुदायिक भवन और अधोसंरचना का विस्तार।

पंडरिया का विकास मॉडल — प्रदेश व देश के लिए प्रेरणा

भाजपा मंडल अध्यक्ष कुंडा बाल मुकुंद चंद्रवंशी ने बताया कि विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में पंडरिया एक ऐसा मॉडल बन चुका है जिसे छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर में सुशासन, संवेदनशीलता और त्वरित जनसेवा के आदर्श रूप में सराहा जा रहा है। उनकी कार्यशैली ने पंडरिया को आने वाले वर्षों के लिए मजबूत, स्थायी और आधुनिक विकास का आधार प्रदान किया है।

मॉडिफाई साइलेंसर वाला बुलेट बेमेतरा की सड़को पर तेजगति से दौड़ाना युवक को पड़ा महंगा

बुलेट चालक पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर की गई चालानी कार्यवाही

पायनियर संवाददाता < बेमेतरा
www.dailypioneer.com

मॉडिफाई साइलेंसर वाला बुलेट बेमेतरा की सड़को पर तेजगति से दौड़ाना युवक को महंगा पड़ गया। बुलेट चालक पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर की गई चालानी कार्यवाही पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस द्वारा भारी वाहन, मॉडिफाई साइलेंसर, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा बाइक चालक (बुलेट) मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग कर पटाखे फोड़ने व तेज रफ्तार से बुलेट चलाने वाले चालकों पर चलानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवकों को मोर्डिफाइड साइलेंसर को निकालकर कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर का ही उपयोग करने समझाईश दी जा रही है। बेमेतरा पुलिस ने इस दौरान मॉडिफाई साइलेंसर वाले बुलेट को तेजगति से चलाने पर एक बुलेट चालक को पकड़कर उसके खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 182, (क) (4), 183 (1) (क) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बुलेट वाहन चालक के विरूद्ध 01 प्रकरण में 6,000/- रूपये समन शुल्क लिया गया। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा, प्रधान आरक्षक हेमंत साहू, आरक्षक इंद्रजीत पांडेय, राहुल यादव, बिरेन्द्र साहू सहित सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम शामिल रहे। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिले के थाना/चौकी एवं बेमेतरा यातायात पुलिस द्वारा लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकार मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग कर साइलेंसर द्वारा पटाखे फोड़ने एवं तेज रफ्तार से बुलेट वाहन चलाने, ध्वनि प्रदुषण करने वाले वाहन चालकों पर चलानी कार्यवाही किया गया और मोर्डिफाइड साइलेंसर को निकलवाकर कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर का ही उपयोग करने समझाईश दिया गया। बेमेतरा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें।

वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और नशे की हालत में वाहन न चलाना न केवल कानून का पालन है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

मनरेगा में 'दबाव पत्र' से फर्जीवाड़े का खतरा बढ़ा: मांग आधारित योजना में अधिकारियों की जल्दबाज़ी पर सवाल

पायनियर संवाददाता < कवर्धा
www.dailypioneer.com

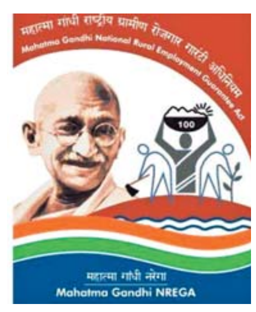

मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी कड़े और दबावपूर्ण निर्देशों ने अब योजना की पारदर्शिता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों और फील्ड-स्टाफ पर जारी सुधारो नहीं तो जवाब दो प्रकार के पत्रों से यह आशंका गहराती जा रही है कि काम का दबाव बढ़ने पर फर्जी प्रगति रिपोर्ट, कागजी मजदूरी और जल्दबाज़ी में स्वीकृत कार्यों की संभावनाएँ तेज़ हो सकती हैं।

जिला प्रशासन ने कार्यक्रम अधिकारी रमेश कुमार भास्कर, प्रभारी प्रोग्राम अधिकारी दिलीप कुमार साहू, सेव कुमार चंद्रवंशी, बाबूलाल मेहरा, अशोक कुमार झरिया और ता. प्रोग्राम अधिकारी लवकेश मरकाम सहित कई अधिकारियों को एक माह में सुधार के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि गलत रिपोर्ट, देर से प्रगति भेजना और निर्देशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन विशेषज्ञों व फील्ड कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे दबाव पत्र मनरेगा की मूल संरचना से मेल नहीं खाते।

'मांग आधारित योजना': दबाव में बढ़ सकता है फर्जीवाड़ा

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) एक मांग आधारित योजना है, जिसमें कार्य तभी शुरू होता है जब मजदूर काम की मांग करते हैं। कबीरधाम जिले में मजदूरों की वास्तविक काम-मांग जनवरी के बाद बढ़ती है। नवंबर-दिसंबर के महीनों में ग्रामीण किसान, मजदूर और परिवारजन धान व गन्ना कटाई जैसे कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में यदि अधिकारी किसी भी कीमत पर काम दिखाने का दबाव कर्मचारियों पर बनाते हैं, तो– कागजों में मजदूरों की फर्जी मांग बनाई जा सकती है। कार्य स्थल पर वास्तविक उपस्थिति के बिना कागजी मजदूरी दर्ज हो सकती है। जल्दबाज़ी में स्वीकृत कार्यों से अनियमितता और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। ग्राम पंचायतों में अधूरे काम, बिना निरीक्षण के भुगतान और नियम उल्लंघन की घटनाएँ बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि कर्मचारियों का दावा हैः दबाव में काम, गड़बड़ी तय।

अधिकारियों की निष्क्रियता अपनी जगह, लेकिन फील्ड स्टाफ पर एकतरफा दबाव खतरनाक

मनरेगा से पलायन रोकने, ग्रामीण सड़क-नाली सुधारने और आजीविका बढ़ाने में बड़ा योगदान मिला है। लेकिन पिछले कुछ समय में रिपोर्टिंग गड़बड़ियों, अधूरे काम, अनुचित ठेकेदारी और ग्राम पंचायत स्तर पर अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई हैं। कलेक्टर का सख्त रुख निश्चित रूप से जवाबदेही बढ़ाने वाला है, परंतु सुधार का दबाव जब फील्ड पर दबाव में बदल जाता है, तब यह योजना की विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचाता है। ग्राउंड कर्मचारियों का तर्क – काम की मांग ही नहीं है, तो काम कैसे दिखाएँ। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है– मजदूर कटाई के मौसम में काम ही नहीं मांगते। पंचायतें कृषि और त्योहारों के समय कार्य शुरू नहीं करना चाहतीं। ऊपर से आए दबाव आदेशों में एक माह में सुधार करना व्यावहारिक नहीं है। यदि जिम्मेदार अधिकारी वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना केवल कागजी प्रगति पर जोर देंगे, तो योजना में कागजी काम और गलत आंकड़े बढ़ेंगे।

कठोर आदेश जरूरी, लेकिन मांग आधारित व्यवस्था में दबाव उल्टा असर डाल सकता है

मनरेगा की सफलता पारदर्शिता, मांग और जनभागीदारी पर निर्भर करती है। यदि अधिकारियों पर दबाव बनेगा, तो वही दबाव फील्ड कर्मचारियों से होकर ग्राम पंचायतों तक पहुँचेगा और अंततः– शुद्ध काम कम, कागजी काम ज्यादा और फर्जीवाड़े की संभावना सबसे अधिक होगी। जिला प्रशासन के आदेश ने जहां जवाबदेही तय करने का संदेश दिया है, वहीं यह भी साफ दिखने लगा है कि दबाव आधारित सुधार, मांग आधारित योजना में जोखिम भी बढ़ाता है।

पटेल समाज में बदलाव की शुरुआत: क्रांतिकारी महाबैठक में भविष्य की नई दिशा तय

पायनियर संवाददाता < कवर्धा/ स.लोहारा
www.dailypioneer.com

पटेल भवन स/लोहारा में जिला पटेल युवा संगठन की ओर से आयोजित क्रांतिकारी महाबैठक में समाज के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कवर्धा, खैरागढ़-छुहीखदान-गंडाई और राजनांदगांव के युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में परदेशी पटेल युवा संगठन के संस्थापक ने कहा कि अब समाज के युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। उन्होंने घोषणा की– अब पटेल भवन सिर्फ बैठक की जगह नहीं रहेगा, बल्कि काम और योजनाओं को आगे बढ़ाने का केंद्र बनेगा।

तीन बड़े काम, जिन पर तुरंत शुरुआत होगी

रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा

संगठन युवाओं को अपने काम-धंधे शुरू करने में मदद करेगा। युवाओं को आज के बाजार की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़े व्यापारियों से स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों में सहयोग की अपील की गई। सरकारी योजनाओं की मदद से गांवों में छोटे व्यवसाय शुरू करवाए जाएंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष कोष

संगठन ने 'पढ़ाई और स्वास्थ्य कोष' बनाने का फैसला लिया। ताकि आर्थिक कमजोरी की वजह से कोई बच्चा पढ़ाई न छोड़े। बच्चों को अच्छे संस्कार और उपयोगी कौशल देने पर भी जोर रहेगा।

समाज की एकता – एक पटेल, एक परिवार

किसी भी परेशानी में समाज का हर सदस्य एक-दूसरे की मदद करेगा। यह नियम समाज को मजबूत और संगठित बनाए रखने के लिए लागू किया जाएगा।

सामाजिक जनों का संबोधन: शिक्षा और मेहनत पर बल

युवा संगठन के अध्यक्ष भुनेश्वर पटेल ने कहा– हमारा समाज मेहनती है, अपने खेत-बाड़ियों में सब्जियां और फसल उगाकर जीवन चलाता है। लेकिन अब हमें मेहनत के साथ आधुनिक तकनीक और अच्छी शिक्षा को भी अपनाना होगा। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अच्छा जीवन जीने की समझ देती है। पटेल समाज के जिलाध्यक्ष शंकर पटेल ने कहा– हम प्रकृति से जुड़े, परिश्रमी और स्वाभिमानी लोग हैं। हमारी मेहनत ही हमारी असली पहचान है। कार्यक्रम को भगवान सिंह पटेल, राजू पटेल, सुखदेव पटेल, रामकुमार पटेल और महेश पटेल ने भी संबोधित किया।

बैठक के प्रमुख उपस्थित सदस्य

अशोक पटेल, धर्मेंद पटेल, सुखदास पटेल, पलटन पटेल, संजय पटेल, सुरेश पटेल, अश्वनी पटेल, रामलाल पटेल, बैसाखू पटेल, गोबिंद पटेल, ईश्वर पटेल, सुखराती पटेल, गोपी पटेल, भूपेंद्र पटेल, मोती पटेल समेत कई सदस्य उपस्थित रहे।

कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य परोपकार और नाम-जाप : स्वामी ज्योर्तिमयानंद

पायनियर संवाददाता < बेमेतरा
www.dailypioneer.com

नगर के कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित गौ प्रतिष्ठा यज्ञ एवं शिवमहापुराण कथा का तीसरे दिन भी प्रातः काल से यज्ञ स्थल की परिक्रमा श्रद्धालुओं द्वारा अनवरत किया जा रहा है सनातन धर्मी प्रातः काल से यज्ञ भगवान की पूजा एवं परिक्रमा में पुरी श्रद्धा से लगे रहे प्रातः काल से यज्ञाचार्यों द्वारा शिवगंगा आश्रम सलवा के बटुकों के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए मण्डी परिसर का माहौल पुरा धार्मिक हो रहा है। स्वामी ज्योर्तिमयानंद ने शिवमहापुराण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा शिवमहापुराण की कथा भगवान शिव के जीवन महिमा और लीलाओं का वर्णन करती है। इसमें शिव के विवाह उनके अवतारों, ज्योतिर्लिंगों और भक्तों की कहानीयों के साथ साथ पूजा पद्धति और ज्ञान प्रद आख्यानों का भी विस्तृत वर्णन है। यह शिव की कल्याणकारी और सर्वोच्च सत्ता के रूप में उनकी शक्ति, करुणा और ज्ञान पर केन्द्रित है। शिवमहापुराण में भगवान शिव की महिमा, अवतारों, शिव-पार्वती की कथा सृष्टि की रचना और शिवभक्ती के मार्गों का विस्तृत वर्णन है। जिसमें शिव को परमेश्वर और कल्याणकारी रुप में दिखाया गया है। यह भक्तों को मोक्ष और सुख प्राप्त करनें का मार्ग बताता है, इसमें शिव भक्ती और कलयुग के धर्म-अधर्म का भी उल्लेख है। कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य परोपकार और नाम-जाप है इस युग में धर्म का पतन और मनुष्य भौतिकता में लिप्त है। ऐसे में दूसरों की मदद करना सेवा करना और भगवान का स्मरण करना सबसे सरल और प्रभावी मार्ग माना गया है। जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जीवन सार्थक बनता है। शिवमहापुराण के आरती के पश्चात स्वामी ज्योर्तिमयानंदः सरस्वती के साथ नगर के नर नारी यज्ञ भगवान की आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए।आज आयोजन में मुख्य रूप से गुड्डा गुप्ता, रोशन दत्ता, लेखमणी पाण्डेय, जितेन्द्र शुक्ला, मनोज मिश्रा, लव मिश्रा, सुमित चौबे, निति अग्रवाल, अनिता मिश्रा, हेमिन साहू, सरस्वती साहु, कुंती साहू, वर्षा गौतम माधवी शर्मा के साथ नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

सीएमएचओ ने जागरुकता रथ को हरी झंड़ी दिखाकर किया रवाना

बेमेतरा जिले के सभी विकासखण्ड में चलेगा 8 से 31 दिसम्बर तक सघन कुष्ठ खोज अभियान

पायनियर संवाददाता < बेमेतरा
www.dailypioneer.com

अभियान तहत स्वास्थ्य अमले घर-घर भ्रमण कर कुष्ठ के संभावित व्यक्तियों की करेंगे पहचान

बेमेतरा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन कुष्ठ खोज अभियान का आरंभ सीएमएचओ कार्यालय में जागरूकता रथ को सीएमएचओ डॉ अमृत लाल रोहलेडर ने हरी झंडी दिखा कर किया, यह अभियान 8 दिसम्बर से शुरुआत किया गया जो कि 31 दिसम्बर तक चलाया चलेगा, संचालक, महामारी नियंत्रण छत्तीसगढ़, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. के निर्देशानुसार कलेक्टर रणबीर शर्मा एवं सीएमएचओ डॉ अमृत लाल रोहलेडर व जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ बी एल राज के मार्गदर्शन पर सधन कुष्ठ खोज अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान बेमेतरा जिला में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के उददेश्य से समुदाय में कुष्ठ रोग के संक्रमण को रोकने हेतू प्रत्येक रोगियों का प्रारंभिक अवस्था में पहचान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि रोग के प्रसार में नियंत्रण हो, एवं कुष्ठ संबंधी विकलांगता से बचा जा सके जिस हेतु बेमेतरा जिले के सभी विकासखंडों में 08 दिसबंर से 31 दिसबंर 2025 तक सघन कुष्ठ खोज अभियान चलेगा, इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य अमले द्वारा घर-घर भ्रमण कर कुष्ठ के संभावित व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जॉच एवं पुष्टि करेगी। इस सघन कुष्ठ खोज अभियान के सफल संचालन एवं सतत् निगरानी हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों का विकासखण्डो में मॉनिटरिंग / सुपरविजन करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। डॉ. बी.एल. राज जिला नोडल कुष्ठ अधिकारी साजा विकासखण्ड, लता बंजारे जिला कार्यक्रम प्रबंधक बेमेतरा विकासखण्ड, हिना सिन्हा, संपत्ति बंजारे जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम नवागढ़ विकासखण्ड, गुलाब चंद साहू प्रभारी जिला कुष्ठ समन्वयक, अर्जुन लाल बेरला विकासखण्ड शामिल हैं। इसके साथ ही समस्त जिला का मॉनिटरिंग / सुपरविजन स्वयं डॉ. अमृत लाल रोहलेडर सीएमएचओ जिला बेमेतरा द्वारा किया जाएगा। इस सघन कुष्ठ खोज अभियान में संभावित कुष्ठ रोग की पहचान, संवेदना जांच, त्वचा परीक्षण, स्किन स्मीयर जांच के साथ एमडीटी दवा की जानकारी दी जाएगी। सीएमएचओ डॉ. अमृत लाल रोहलेडर ने बताया कि कुष्ठ एक संक्रामक रोग है, जिसकी प्रारंभिक पहचान और समय पर उपचार से पूर्ण इलाज संभव है। उन्होंने बताया कि जिले का प्रीवलेंस रेट वर्तमान में 1.08 है, जिसे घटाकर 1 से कम करने का लक्ष्य है। इसके लिए 8 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक सघन कुष्ठ सर्वे अभियान चलाया जा रहा हैं। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. बी एल राज ने बताया कि वर्ष 2030 तक कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित है। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि मितानिन एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग करे और शरीर में दाग-धब्बा या सुन्नपन होने पर जांच अवश्य कराएं।

एसएसपी ने किया रक्षित केन्द्र बेमेतरा का रात्रि में औचक निरीक्षण कर लिया जायजा

पायनियर संवाददाता < बेमेतरा
www.dailypioneer.com

पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू ने रक्षित केन्द्र बेमेतरा (पुलिस लाईन) में रात्रि में पहुच कर औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होनें रक्षित केन्द्र बेमेतरा में आर्म्स शाखा, रोजनामचा कक्ष, क्वाटर गार्ड सहित रक्षित केन्द्र के विभिन्न शाखाओं का जायजा लेकर आर्म्स शाखा में सभी शस्त्रों के उचित रख-रखाव एवं मरम्मत पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान गार्ड एवं उनके हथियार को भी चेक किया गया। शासकीय वाहनों के उचित रख-रखाव हेतु वाहन शाखा प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए गए। उन्होंने पुलिस कस्टडी में सुरक्षा के संबंध में विशेष सावधानी बरतने और हथकड़ी लगाने की विधि में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होनें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुशासन में रहने एवं आकस्मिक डियूटी हेतु सदैव तत्पर रहने। रक्षित केन्द्र और परेड ग्राउंड को साफ-सुथरा एवं अद्यतन रखने हेतु निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि थानों और चौकियों में आने वाले पीड़ितों की शिकायतों पर संवेदनशीलता से त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता में पुलिस की सकारात्मक छवि बनी रहे। उन्होंने दोहराया कि अनुशासन ही पुलिस व्यवस्था की बुनियाद है और किसी भी स्तर की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औचक निरीक्षण के दौरान प्रधान आरक्षक अनुपम शर्मा, राकेश मेरावी, प्रधान आरक्षक आर्म्स शाखा खिलेन्द्र साहू, आरक्षक मुकेश यादव, तारण घितोड़े, संजीव साहू, संजय सप्रे, रामाधीन ध्रुव, कमलेश साहू, ओमप्रकाश बांधे एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

हटरी धर्मशाला में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, 400 लोगों ने करवाया हेल्थ चेकअप

पायनियर संवाददाता ➤ सक्ती
www.dailypioneer.com

सक्ती नगर की हटरी धर्मशाला में मारवाड़ी युवा मंच सक्ती द्वारा बेस्ट आर्थोपेडिक हॉस्पिटल रायपुर के तत्वाधान में स्व.रामावतार डालमिया की स्मृति में नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर के प्रसिद्ध चिकित्सकों डॉ हर्षित गोयनका, नस एवं सायटिका रोग, डॉ कृतिका गोयनका, स्किन रोग, डॉ रोहित कनोई, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं आर्थोपेडिक, डॉ सुनीता कनोई, स्त्रीरोग एवं नि:संतान से संबंधित विशेष चिकित्सा सुविधा का लाभ क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों दिया गया,जिसमें सक्ती नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आए लगभग 400 लोग लाभान्वित हुए, जिसमे नगर के आम नागरिकों के साथ, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न लोगों ने भी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया, उक्त शिविर में मुख्य अभ्यागत के रूप में सक्ती नपा एवं अग्रवाल सभा के अध्यक्ष श्यामसुंदर अग्रवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष संजय रामचंद,सक्ती टीआई लखन पटेल, पूर्व अग्रवाल सभा अध्यक्ष आनंद अग्रवाल, समाजसेवी जगदीश बंसल क्षेत्र के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ राजेश अग्रवाल, मंच के संरक्षक हरिओम अग्रवाल, अग्रवाल युवा सम्मेलन के जिलाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, मायुम सक्ती के अध्यक्ष मनीष कथूरिया, चेंबर अध्यक्ष मुकेश बंसल, महिला जागृति शाखा की अध्यक्षा मिनल अग्रवाल, डालमिया परिवार के वरिष्ठ घासीराम डालमिया, लक्ष्मीनारायण डालमिया सहित आगंतुक चिकित्सकगण मंचस्थ थे, जिनका मंच परिवार एवं डालमिया परिवार के सदस्यों ने माला पुष्पगुच्छ, एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया, स्वागत उद्बोधन एवं मंच संचालन अमन डालमिया ने किया। मुख्य अभ्यागत श्यामसुंदर अग्रवाल ने स्वास्थ्य शिविर को वर्तमान समय की आवश्यकता आवश्यकता बताते हुए चिकित्सकों को सेवा हेतु स्वीकृति देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने का आग्रह किया अन्य मंचस्थ अभ्यागतो ने अपने उद्बोधन में आयोजन की प्रशंसा करते हुए, ऐसे आयोजन को क्षेत्र के चिकित्सा जगत में अनुकरणीय पहल बताते हुए आयोजन हेतु डालमिया परिवार को बधाई दी, कार्यक्रम को सफल रूप से संपन्न करने में मारवाड़ी युवा मंच परिवार सक्ती के अनुराग अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, सुमित शर्मा, पीयूष कथूरिया, राकेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल साई, प्रकाश अग्रवाल ट्राली, मानस अग्रवाल सहित समस्त सदस्यों एवं जनसेवा समिति के अध्यक्ष सीए नीरज अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अशोक खेतान, विजय डालमिया (पूर्व चेंबर अध्यक्ष), गजेन्द्र डालमिया (मायुम), अमन डालमिया सहित पूरे डालमिया परिवार का सराहनीय योगदान रहा।

अंतर जिला चोर गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

चोरी के सोना-चांदी समेत खरीददार सहित समान बरामद

पायनियर संवाददाता ➤ चांपा
www.dailypioneer.com

स्थानीय पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना चांपा एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने सक्रियता दिखाते हुए चोरी के मामले में दो चोरों और एक खरीददार सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए, वहीं खरीददार से सोना गलाने के उपकरण भी जप्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियो में, जैन मंदिर के पीछे बुधवारी चौक थाना कोतवाली कोरबा निवासी सत्य प्रकाश महंत पिता गेंद दास महंत 19 वर्ष, रामसागर पारा थाना कोतवाली कोरबा निवासी अनिल काले पिता अपासो काले 44 वर्ष, नेहरू नगर कुआं भट्ठा बुधवारी बायपास रोड चौकी मानिकपुर थाना सिविल लाइन, जिला कोरबा निवासी मोहन मिंज पिता गोपाल मिंज 24 वर्ष शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आनंद विहार कॉलोनी सिवनी चांपा निवासी प्रार्थी धनीराम देवांगन ने 8 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि भतीजे के दशगात्र कार्यक्रम से लौटने पर देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी हो गए हैं। रिपोर्ट पर थाना चांपा में अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना तुरंत पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं एसडीओपी यदुमणी सिदार को दी गई। निर्देशानुसार थाना चांपा और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई।टीम ने घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही प्रार्थी द्वारा बताए गए चोरी गए मोबाइल की तकनीकी जांच कर लोकेशन एवं डिटेल निकाले गए। साइबर सेल की तकनीकी मदद से पुलिस ने कोरबा क्षेत्र से सत्य प्रकाश महंत और मोहन मिंज को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा। शुरुआत में दोनों आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी की वारदात को अपने अन्य तीन साथियों के साथ मिलकर अंजाम देना स्वीकार किया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि चोरी का सोना-चांदी उन्होंने सोनार अनिल काले को बेच दिया था।दोनों आरोपियों की निशानदेही पर सोनार अनिल काले को पकड़ा गया। उसके पास से सोना गलाने के उपकरण तथा गला हुआ सोना-चांदी बरामद किया गया। तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गिरोह के अन्य तीन आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, निरीक्षक सागर पाठक प्रभारी साइबर सेल, उप निरीक्षक दादुरैया ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक विवेक सिंह, प्रधान आरक्षक विवेक, आरक्षक प्रदीप, माखन, श्रीकांत, रोहित, शंकर राजपूत, वीरेश सिंह, संजय केवट, सचिन एक्का, कैलाश यादव, जय उरांव, भूपेंद्र गोस्वामी, रूप नारायण का विशेष योगदान रहा।

मुकुंद मल्टीप्लेक्स में मारपीट करने वाली दो लड़किया गिरफ्तार, तीन सहयोगी लड़के भी लिए गए हिरासत में

पायनियर संवाददाता ➤ चांपा
www.dailypioneer.com

शहर के मुकुंद मल्टीप्लेक्स परिसर में मारपीट कर उत्पात मचाने वाली दो लड़कियों को चांपा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। पीड़िता ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मुकुंद मल्टीप्लेक्स के टिकट काउंटर के पास खड़ी थी। उसी दौरान दो लड़किया वहां पहुँचीं और पुरानी बात को लेकर गाली-गलौज करने लगीं। विरोध करने पर दोनों ने पीड़िता के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान दोनों लड़कियों ने अपने परिचित लड़कों को भी मौके पर बुला लिया। उनके सामने पीड़िता और उसकी बहन के साथ अश्लील गाली-गलौज और मारपीट की गई। हल्ला होने पर आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया और घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो बाद में वायरल हो गया। इसी के साथ मारपीट में सहयोग करने वाले तीन लड़कों के विरुद्ध भी पुलिस ने पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है।

मुख्यमंत्री साय ने माता कौसल्या जन्मभूमि कोसला का अवलोकन करने जांजगीर-चांपा कलेक्टर को भेजा पत्र

दुर्ग सांसद विजय बघेल से मुलाकात कर पामगढ़ जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ने कोसला आने का दिया न्योता

पायनियर संवाददाता ➤ शिवरीनारायण
www.dailypioneer.com

जांजगीर चांपा व शक्ति जिले में एक दिवासीय प्रवास के दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल क्षत्रिय कुर्मी समाज के जांजगीर कार्यक्रम में शामिल हुए इस दौरान श्री राम के ननिहाल एवं उनकी माता कौसल्या जन्मभूमि कोसला धाम की ओर पामगढ़ जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रूपचंद साहू ने सांसद विजय बघेल से भेंट मुलाकात की उन्होंने सांसद बघेल को गमछा, पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया साथ ही माता कौशल्या जन्म भूमि कोसला धाम का अवलोकन करने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से जांजगीर-चांपा कलेक्टर को जारी किए गए पत्र की प्रति भेंट कर विस्तृत जानकारी भी दिए। जुलाई 2025 में भिलाई में आयोजित एक समारोह में उन्होंने दुर्गा प्रसाद पारकर द्वारा संपादित माता कौसल्या जन्मभूमि कोसला पुस्तक का विमोचन किया था। जिले के एक दिवसीय प्रवास पर आए सांसद बघेल को जनपद उपाध्यक्ष रूपचंद साहू , भाजपा युवा नेता मनोबल सिंह जाहिरे, गौरव तिवारी ने माता कौसल्या जन्म भूमि कोसला धाम का दर्शन करने हेतु न्यौता दिया। जिसे सांसद बघेल ने सहज स्वीकार करते हुए कहा कि - मैं जनवरी माह में विशेष समय निकालकर कोसला धाम आऊंगा और कोसलावासियों के साथ भोजन करूंगा। उन्होंने बताया कि माता कौसल्या जन्मभूमि कौसला धाम के विषय पर जांजगीर-चांपा लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े से हमारी बातचीत हुई है और इस विषय पर प्रधानमंत्री को भी पत्र भेज चुके हैं। इस महती भेंट-मुलाकात के अवसर पर नारायण चंदेल, कृष्णाकांत चंद्रा, जनपद उपाध्यक्ष नवागढ़ प्रतिनिधि घासीराम कश्यप, मनीष सिंगसर्वा, रामेश्वर कश्यप, महेंद्र कश्यप एवं सामाजिक गण उपस्थित थे।

शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय के दर्पण ग्रंथ में भी उद्धत होंगे :माता कौसल्या जन्मभूमि कोसला धाम का महात्म्य

त्रेता युगीन दक्षिण कोसल के नाम से अभिहित पावन छत्तीसगढ़ प्रदेश में रामायण कालीन अनेक महत्वपूर्ण पावन स्थल होने के साथ ही यह पवित्र धरती रामायण कालीन प्रसंगों से ओतप्रोत है। जहां माता कौसल्या की जन्म भूमि कोसला है तो वही उनके पोते वह श्री राम सीता के जुड़वे पुत्र लव-कुश का जन्म स्थल वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया है। श्री राम भक्त शिरोमणि माता शबरी की जन्म भूमि शिवरीनारायण जैसे अनेक रामायण कालीन स्थल इस प्रदेश के कोख में है। माता शबरी जन्मभूमि शिवरीनारायण के पास ही श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी की तपोभूमि खरौद है। जो इस दर्पण ग्रंथ में उद्धत है। धार्मिक नगरी खरौद को खर-दूषण की नगरी कहा जाता है। जहां लक्ष्मण जी के नाम से शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है। क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण महाविद्यालय द्वारा शीघ्र प्रकाशित हो रही है-दर्पण ग्रंथ में महाविद्यालय के प्राध्यापक अश्विनी केशरवानी ने माता कौसल्या जन्मभूमि कोसला को रेखांकित करते हुए बहुत खुबसूरत लेख लिखा है। वही नगर पंचायत शिवरीनारायण के पूर्व अध्यक्ष डॉ. शांति कुमार कैवर्त्य के शोध आलेख माता कौसल्या जन्मभूमि कोसला का ऐतिहासिक सत्यांवेषण को शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरौद ने अपने दर्पण ग्रंथ में विशेष प्राथमिकता दी है।

जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पायनियर संवाददाता ➤ मुंगेली
www.dailypioneer.com

जेण्डर अभियान नई चेतना 4.0 के तहत जिला पंचायत सभाकक्ष, मुंगेली में जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडेय, जिला पंचायत सभापति, अन्य जिला पंचायत सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जेंडर समानता को प्रोत्साहित करना एवं महिलाओं-बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण करना था। इस दौरान इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लेते हुए एक संवेदनशील और समान समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत परिसर में रंगोली, जेंडर आधारित लघु वीडियो क्लिप, जेंडर शपथ तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। मंच से उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और बिहान की दीदियों ने लैंगिक समानता, समान अवसर और महिला सम्मान पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से सीएमएचओ डा. शीला साहा, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी संजूला शर्मा, पशुधन विभाग से उपसंचालक डॉ. आर.एम.त्रिपाठी, साथ ही कृषि, मत्स्य, उद्यानिकी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही जिला पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में बिहान की दीदियाँ और कैडर भी उपस्थित रहीं।

'धरोहर' शैक्षणिक कार्यक्रम डाईट पेंड्रा

पायनियर संवाददाता ➤ जैजैपुर
www.dailypioneer.com

संयुक्त संचालक शिक्षा, संभाग बिलासपुर आर पी आदित्य जी के निर्देशन, जे पी पुष्प डायरेक्टर डाइट पेंड्रा के मार्गदर्शन और आप सबके सकारात्मक सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विजन और मिशन पर आधारित, समग्र शिक्षा को साकार करने एफएलएन और ईसीसीई पद्धति के बेहतर क्रियान्वयन हेतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का आगाज राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थान डाइट पेंड्रा में पंडित हरिहर प्रसाद शर्मा सहयोग उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर तमनार, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल जैजैपुर, संस्कार पब्लिक स्कूल जैजैपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल मान् अजांबर सिंह नेताम, विशिष्ट अतिथि एवं बोर्ड सदस्य चंद्रकांत तिवारी माध्यमिक शिक्षा मंडल, राष्ट्रीय स्तर के कवि, जीपीएम जिला के समाजसेवियों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों एवं अधिकारी गणों की गौरवमयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति, कला, कौशल एवं इनके माध्यम से बच्चों तक पहुंच बनाकर हमारी धरोहरों का संरक्षण संवर्धन करने सबका आह्वान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनका समावेश कर शिक्षा को सुदृढ़, बहु आयामी और समग्र बनाने जबरदस्त प्रदर्शन इस मंच द्वारा किया गया। विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों ने इसे इसे रुचिकर, प्रभावशाली और सार्थक बनाने के उपाय, सुझाव और क्रियान्वयन पर बल दिये। अत्यंत ज्ञानवर्धक, दूरदर्शिता पूर्ण तथ्यों को एक सूत्र में पिरोने का श्रेय जे पी पुष्प प्राचार्य डाइट पेंड्रा को जाता है। उनका यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित हुआ है और होता रहेगा। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई है। बावजूद इसके 5 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी लोगों तक इसकी समझ नहीं पहुंच पाई है। आज ऐसे जागरूक मंचों और संस्थाओं के माध्यम से धरातल पर इसको साकार करने की कवायद अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत की मौलिक पहचान को जीवंत कर एवं हमारी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के साथ भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में एक भारतीय होने के नाते हमें इसका पुरजोर समर्थन कर जन-जन के स्मृति पटल पर इसे रेखांकित करना होगा। आप सभी से हम यही अपेक्षा करते हैं। भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, भावी पीढ़ी को तराशने का प्रयास किया जाना श्रेयस्कर होगा।

गुंजन एजुकेशन सेंटर में स्पोर्ट्स मीट सम्पन्न

पायनियर संवाददाता ➤ सक्ती
www.dailypioneer.com

गुंजन एजुकेशन सेंटर में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2025-26 का सफल समापन हुआ, प्रतियोगिता के दौरान प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर विभिन्न खेलों में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह के अवसर पर शक्ति क्षेत्र के प्रख्यात चित्रकार राजकुमार यादव हरदा, मारवाड़ी युवा मंच महिला जागृति शाखा शक्ति की अध्यक्षा मती मीनल अग्रवाल तथा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला समिति की सचिव मती शिल्पा कथुरिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अतिथियों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों के कला की सरहना कर उनके मनोबल को बढ़ाया। कार्यक्रम के पहले दिन नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए सिंपल रेस, बिस्किट रेस, जलेबी रेस, चॉकलेट रेस, स्पून रेस और जिक-जैक रेस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। दूसरे दिन कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए चेयर रेस, सैक रेस, नीडल-थ्रेड रेस तथा थ्री-लेग रेस जैसी प्रतिद्वंदितापूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिससे मैदान में ऊर्जा और रोमांच का माहौल बना रहा। तीसरे और अंतिम दिन शतरंज, रंगोली, मेहंदी, सलाद सजावट तथा फायरलेस कुकिंग जैसी रचनात्मक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और नवाचारपूर्ण सोच का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के डायरेक्टर नितिन सोनी ने कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने बच्चों को खेल भावना, अनुशासन और टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।तीन दिवसीय इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के तुलेश चंद्र, गोबिंद दाश, भूमेश यादव, देविका पटेल, सारिका सोनी, पुष्पा यादव, पूनम यादव, आँचल यादव, काजल महंत, आँचल पटेल, नीतू यादव, ज्योति देवगाँगन, चारूलता बरेठ, अंचल साहू युक्ता जायसवाल, पियूष यादव, सोनिया सोनवानी, छोटे लाल राठौर आदि सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।

ईश्वर की उपस्थिति या अनुभव से ही सच्चा और वास्तविक आनंद प्राप्त हो सकता हैं

सच्चा और स्थायी आनंद हमारे शरीर के भीतर विद्यमान हैं: स्वामी युगल शरण

पायनियर संवाददाता ➤ चांपा
www.dailypioneer.com

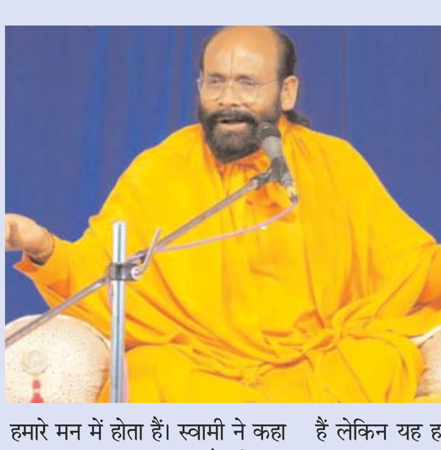

ईश्वर ही आनंद हैं और आनंद ही ईश्वर हैं कुछ दार्शनिक और अध्यात्मिक परंपराओं में ईश्वर को आनंद का स्त्रोत माना जाता हैं। ऐसा माना जाता हैं कि ईश्वर की उपस्थिति या अनुभव से ही सच्चा और वास्तविक आनंद प्राप्त हो सकता हैं। आनंद हमारे ऊपर हैं और हमारे नीचे भी हैं उसी पर्सनालिटी का नाम आनंद गोपिका सेवा मिशन द्वारा आयोजित 21 दिवसीय आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए आठवें दिन डॉ स्वामी युगल शरण महाराज ने सारगर्भित शब्दों में बताया कि मानव जीवन में आनंद की तलाश एक स्वाभाविक प्रक्रिया हैं श्रद्धालु भक्त अक्सर बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं। सच्चा और स्थायी आनंद हमारे शरीर के भीतर विद्यमान हैं। ईश्वर की उपस्थिति या फिर अनुभव से ही हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। संसार का रहस्य एक गहन और जटिल विषय हैं । प्रवचन के आठवें दिन स्वामी युगल शरण जी ने अपने दार्शनिक प्रवचन में संसार के स्वरूप और उसकी वास्तविकता के बारे में विस्तार से दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में कही। उन्होंने कहा कि संसार दो प्रकार का हैं प्रथम स्थूल संसार और दुसरा सूक्ष्म संसार स्थूल संसार वह हैं जो हमें दिखाई देता हैं, जबकि सूक्ष्म संसार हमारे भीतर रहता हैं। यदि हम उसके विषय में सोचते हैं और आंख से देख लेते हैं तो भीतर का संसार बढ़ जाता हैं। हनुमान मंदिर प्रांगण में स्वामी ने कहा संसार में सुख और दुःख दोनों हमारे मन में होता हैं। स्वामी ने कहा कि संसार मिथ्या नहीं हैं लेकिन हमारी धारणा और समझ के कारण यह मिथ्या प्रतीत हो सकता हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में चिंतन करते हैं वह कही और नहीं बल्कि हैं लेकिन यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता हैं। स्वामी ने कहा कि संसार में किसी भी व्यक्ति को सुख नहीं हैं यदि संसार में सुख होता तो एक वस्तु में जितना सुख मिलता उतना हर किसी को मिलता और सदैव मिलते रहता । उन्होंने कहा कि संसार में सुख और दुःख सबको मिलता हैं, यह क्षणिक हैं। स्वामी ने त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव के बारे में अत्यंत विस्तार से बताया कि संसार में कोई भी जीव किसी भी जीव के मुआफिक नही हैं। यह हमें अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव में रहते हैं, तब तक हम संसार में सुख और दुःख दोनों का अनुभव करते हैं। आगे कहा कि माया और उसके 3 गुणों के कारण ही सब अपने स्वार्थ के लिए एक-दुसरे से जुड़े हुए हैं । इसलिए न संसार में राग हैं और न ही दोष। भगवान की भक्ति करने के लिए उदासीनता एक महत्वपूर्ण गुण हैं क्योंकि यह हमें अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखने में मदद करती हैं। उदासीनता हमें भगवान की भक्ति करने में मदद करता हैं। उदासीनता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखने का प्रयास करना चाहिए और प्रतिदिन समय निकालकर भगवान की भक्ति जरुर करनी चाहिए संसार का रहस्य एक गहन और जटिल विषय हैं। स्वामी के प्रवचन से हमें संसार की वास्तविकता और त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव के बारे में जानने और समझने का अवसर आध्यात्मिक प्रवचन से मिला। साथ ही हमें अपने जीवन में इन विलक्षण बातों को समझने और अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए।

जिले में जमीन कारोबारियो के नए संगठन का हुआ गठन

राहुल संभालेंगे प्रॉपर्टी डीलर संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी

सक्ती। जिले में भी जमीन कारोबारियो ने राज्य शासन द्वारा आए दिन बदलते नियमों को लेकर कारोबार हो पर हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए अपने एक अलग संगठन का गठन कर लिया है,तथा इस संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी राहुल अग्रवाल को सौंपी गई है सक्ती के हटरी धर्मशाला में जमीन से जुड़े व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रॉपर्टी संघ सक्ती का गठन किया गया,गठन के दौरान पत्रकार राहुल अग्रवाल को निर्विरोध सक्ती जिला अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर राजेश अग्रवाल (बाबा), सोनू कुरैशी एवं कालू रघुनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई। सचिव के रूप में हरीश अग्रवाल (कालू), सहसचिव पद पर रमेश देवांगन तथा कोषाध्यक्ष के पद पर गोलू (सीडी) को नियुक्त किया गया। वहीं समिति के संरक्षक के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष सक्ती श्याम सुंदर अग्रवाल, जगदीश बंसल, अरुण अग्रवाल एवं चमन अग्रवाल (डीएम) को मनोनीत किया गया।

एसएसपी ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों की ली एक महत्वपूर्ण बैठक

सड़क पर घूमते और बैठे मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में गौ सेवकों के साथ बैठक करने दिए निर्देश

पायनियर संवाददाता ∢ बेमेतरा
www.dailypioneer.com

पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू ने सड़क पर घूमते और बैठे मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में गौ सेवकों के साथ बैठक करने और गौ सेवकों के सहयोग से गौ वंश की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने दिए निर्देश। उन्होनें सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने सुपरविजन में थाना/चौकी में पंजीबद्ध लंबित चालान, अपराध, मर्ग, गुम इंसान, लंबित शिकायतो का शीघ्र निकाल करने तथा लंबित संमंस, लंबित वारंट व ऑपरेशन ईगल अभियान चलाकर स्थायी वारंट की तामिली किये जाने, असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने, अपराध नियंत्रण एवं लघुअधिनियम प्रकरणों में ध्याने देने, गुगल स्प्रीड शीट में लंबित चालान, अपराध, मर्ग, गुम इंसान, लंबित शिकायतो को अलग-अलग गुगल स्प्रीड शीट में एन्ट्री कर अपलोड शीघ्र करने, गुंडा एवं निगरानी बदमाशो की फाईल खोलने एवं तीन से अधिक अपराधो में जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए। एसएसपी ने कहा कि नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगी। साथ ही समयबद्ध मामलों का शीघ्र निपटारा कर 60 से 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही, उन्होंने तलाशी और जब्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी को अनिवार्य बताते हुए, मामलों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होनें नए लागू तीन आपराधिक कानूनों - नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। उन्होनें विजिबल पुलिसिंग को बढ़ावा देने, रात में गश्त, पेट्रोलिंग, कॉम्बिंग ऑपरेशन, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, तथा गोवंश तस्करी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। एसएसपी महोदय ने सायबर प्रहरी अभियान और त्रिनयन एप के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सशक्त एप के माध्यम से वाहनों की चेकिंग कार्यवाही को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही, स्मार्ट और हाईटेक पुलिसिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। उन्होनें अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों सहित थाना/चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शाम को चौक-चौराहों में विजिबल पुलिसिंग के निर्देश दिये गये। विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत पैदल पेट्रोलिंग एवं वाहन पेट्रोलिंग कर भीड-भाड वाले स्थानो, सार्वजनिक स्थानो/सूनसान स्थानों में जमावडा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी/अडडेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की डिक्की, रात्रि में बेफिजुल घुमने वालों सहित आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चौक-चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों की लगातार चेकिंग कार्यवाही करने एवं रात्रि गस्त के दौरान संदिग्ध वाहनो की चेकिंग कार्यवाही करने निर्देश दिए गए। उन्होनें कम्यूनिटी पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण पर ध्यान देने के साथ-साथ मजबूत सूचना तंत्र विकसित करने के दिशा-निर्देश भी दिए गए। एसएसपी ने विजिबल पुलिसिंग और चेकिंग अभियान को सक्रिय करने की बात कही। उन्होंने म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे अपराधों के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होनें संपत्ति संबंधी अपराधों के आदतन आरोपियों पर पैनी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। उन्होंने ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सोशल मीडिया पर सतत निगाह रखने और अधिकारी/कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ कानून और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होनें सीसीटीएनएस योजनांतर्गत एमएलसी/पीएम रिपोर्ट को ऑनलाइन माध्यम से संबंधित अस्पतालों में भेजे जाने तथा एनसीआरबी, नई दिल्ली द्वारा विकसित ई-समंस पोर्टल, समन्वय पोर्टल, साइबर पुलिस पोर्टल के उपयोग और संचालन के संबंध में एवं इस दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए टीम भावना से कार्य करने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे अपराधों के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने के निर्देश दिए। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के निराकरण के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाने का भी निर्देश दिया गया। संपत्ति संबंधी अपराधों के आदतन आरोपियों पर पैनी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। उन्होंने ने सोशल मीडिया पर सतत निगाह रखने और इसके अलावा, चोरी और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त, पेट्रोलिंग और काम्बिंग गशत करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। एसएसपी बेमेतरा ने आम जनता से पुलिस का बेहतर संबंध बनाने, सामुदायिक पुलिसिंग के लिए हमर पुलिस हमर बजार एवं हमर पुलिस हमर गांव अभियान के माध्यम से हॉट/बाजारों एवं ग्रामों, स्कुल कालेजों में नवीन कानून के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने तथा शिकायत/समस्या को लेकर आये महिला आगंतुक /रिपोर्टकर्ता से संयमित व्यवहार करने एवं उनकी रिपोर्ट को गंभीरता पुर्वक लेते हुये तत्काल उचित कार्यवाही करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने, आम जनता में पुलिस विभाग का विश्वास बढ़ाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त बैठक में अति. पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी कौशिल्या साहू उपस्थित रहें।

क्यूआर कोड से मिलेगी मनरेगा कार्य की जानकारी

जिले के 482 ग्राम पंचायत में 3982 कार्य संचालित

पायनियर संवाददाता ∢ बलौदाबाजार
www.dailypioneer.com

जिले में प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित होने वाला रोजगार दिवस इस बार डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया। मनरेगा अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के पंचायतों में क्यूआर कोड लगाए गए जिसके माध्यम से ग्रामीण अब अपनी पंचायतों में चल रहे मनरेगा कार्यो की जानकारी सीधे अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में चस्पा किए गए क्यूआर कोड की कार्यप्रणाली और उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को समझाया गया। ग्रामीण अब क्यूआर कोड स्कैन कर स्वीकृत कार्यो का विवरण देख सकते हैं। इससे उन्हें पारदर्शिता, रोजगार जानकारी, डिजिटल सुविधा और शिकायत निवारण जैसे अनेक लाभ मिलेगा। अब ग्रामीण मनरेगा परियोजनाओं की स्थिति, स्वीकृत बजट और प्रगति की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड के माध्यम से हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल तक सीधी पहुंच सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीण अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज कर सकते हैं। रोजगार दिवस में आजीविका डबरी हेतु अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर सूची तैयार करते हुए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने कहा गया। वर्तमान में जिले के 482 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत 3922 कार्य संचालित है।

कलेक्टर ने की धान खरीदी प्रगति की समीक्षा, रकबा समर्पण, धान उठाव एवं अवैध धान पर कार्यवाही के निर्देश

अब तक 33289 किसानों से 151229 मीट्रिक टन धान खरीदी

पायनियर संवाददाता ∢ बलौदाबाजार
www.dailypioneer.com

कलेक्टर दीपक सोनी ने खाद्य, सहकारिता, कृषि एवं अन्य सम्बंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने किसानों से अतिरिक्त रकबा समर्पण एवं धान उठाव मर तेजी लाने तथा कोचिये व बिचौलिए के अवैध धाम पर लगातार कार्यवाही के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में धान बेचने आने वाले किसानों का वाहन सहित फोटो लेकर एप्प में अपलोड करने का कार्य सभी उपार्जन केन्द्र के ऑपरेटर से प्रतिदिन अनिवार्य रूप से कराने में निर्देश दिये। उन्होंने मिलर्स द्वारा धान उठाव की समीक्षा करते हुए कहा कि उपार्जन केन्द्र से धान उठाने के बाद ट्रक संबंधित मिलर्स के यहां पहुंचना चाहिए। उन्होंने अतिसंवेदशील उपार्जन केंद्रों में अब तक की खरीदी मात्रा का विश्लेषण करने एवं अधिक खरीदी के कारणों का पता लगाने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी समिति का बिचौलिए से मिलीभगत पाए जाने पर कड़ी करुवाही होगी। सभी सतर्क होकर कार्य करें। अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी के लिये उड़ानदस्ता दल एवं चेक पोस्ट से प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी लेने के निर्देश दिये। बताया गया कि जिले के सभी 166 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी जारी है एवं अब तक 33289 किसानों से 151229 मेट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके साथ ही 10482किसानों का लगभग 157 हेक्टेयर रकबा समर्पण कराया गया है।

जिला पंचायत परिसर में आपकी पूंजी, आपका अधिकार शिविर

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ राज्य मे वित्तिय सेवा विभाग,भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत आपकी पूंजी,आपका अधिकार जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष पर जिला स्तरीय जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन 12 दिसंबर 2025 को जिला पंचायत परिसर के सभा कक्ष मे प्रातः 11 बजे से किया जायेगा। इस शिविर का आयोजन सभी बैंक, बीमा, पेंशन प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अवैतनिक निधि का योगदान रहेगा। इन शिविर मे नागरिकों को अनक्लेम्ड जमा, बिमा दावे, राशि प्राप्त करने हेतु हेल्पडेस्क और सहायता काउंटर उपलब्ध कराये जाएंगे। आवश्यकतानुसार लाभार्थी दावेदारी के केवाईसी अपडेट दावा प्रपत्र भरने एवं दस्तावेज सत्यापन मे भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। जिले के नागरिक से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या मे इस शिविर मे शामिल होकर इस जनकल्याणकारी पहल का लाभ उठाएं।

चाइल्ड लाइन 1098 एवं पाण्डुका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

पायनियर संवाददाता ∢ गरियाबंद
www.dailypioneer.com

दूरभाष के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय के निर्देश पर तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी के मार्गदर्शन में चाइल्ड लाइन 1098 गरियाबंद की टीम ने पाण्डुका पुलिस के सहयोग से एक बाल विवाह को रोकने की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड पाण्डुका के अंतर्गत ग्राम पंचायत घटकर्रा में एक नाबालिग बालिका की सगाई करने की तैयारी की सूचना चाइल्ड लाइन 1098 को दूरभाष से प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन गरियाबंद से परियोजना समन्वयक श्याम सुंदर नायक, केस वर्कर राज सिदार तथा पाण्डुका पुलिस की संयुक्त टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुँची। टीम द्वारा बालिका एवं परिजनों से विस्तृत पूछताछ की गई तथा आयु सत्यापन के लिए उपलब्ध दस्तावेजों की जाँच की गई। बालिका द्वारा प्रस्तुत कक्षा 8वीं की मार्कशीट के आधार पर उसकी आयु 15 वर्ष 05 माह 10 दिन पाई गई। निर्धारित उसकी सगाई आयोजित की जानी थी, जो स्पष्ट रूप से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है। इस अधिनियम के प्रावधानानुसार विवाह के लिए बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य है। अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नाबालिग बालक-बालिका का विवाह करने, कराने अथवा सहयोग करने वाले सभी व्यक्ति दंड के भागीदार होते है। जिनके लिए 2 वर्ष तक का कठोर कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बालिका, उसके माता-पिता, परिवारजनों सहित उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों तथा इसके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी देकर समझाइश दी गई। परिजनों एवं ग्रामीणों ने टीम की समझाइश से सहमति प्रकट करते हुए बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह कराने का आश्वासन दिया।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से सौर ऊर्जा को अपनाने लोगों में उत्साह

- अब तक 728 लोगों ने अपने घर की छत पर लगवाए सोलर पैनल

पायनियर संवाददाता ∢ बलौदाबाजार
www.dailypioneer.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सचमुच ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय लिख दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और जिले में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर दीपक सोनी के सतत मार्गदर्शन ने इस योजना को घर-घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जिले के लोगों में इस योजना को लेकर उत्साह इतना प्रबल है कि 7,869 परिवारों ने अब तक पंजीकरण कराकर सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में अपना सशक्त संकल्प व्यक्त किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जिले के बदलते सोच और जागरूकता का प्रतीक है।इसी प्रतिबद्धता और प्रशासनिक सक्रियता का परिणाम है कि 728 घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित हो चुके हैं। ये परिवार आज मुफ्त बिजली का लाभ प्राप्त कर न केवल आर्थिक बचत कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी सार्थक योगदान दे रहे हैं। इस योजना की पारदर्शिता और त्वरित लाभ वितरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि 501 लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। इससे योजना के प्रति आम नागरिकों का भरोसा और मजबूत हुआ है तथा सहभागिता भी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर दीपक सोनी की निगरानी में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का यह अभियान जिले में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बलौदाबाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़ का एक प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभर रहा है—जहाँ सरकारी योजनाएँ कागज़ों से निकलकर वास्तव में लोगों के जीवन में रोशनी बन रही हैं और उज्ज्वल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

आदर्श पब्लिक हॉयर सेकेंडरी स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया गया आनंद मेला उत्सव

पायनियर संवाददाता ∢ बलौदाबाजार
www.dailypioneer.com

छूहिया बलौदाबाजार स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल में आनंद मेला उत्सव का आयोजन किया गया। जिसकी शुरुआत सरस्वती पूजन के साथ आयोजन में आनंद लेने के लिए पहुंचे अभिभावक गण एवं स्कूल के डायरेक्टर आकाश अग्रवाल, तथा प्राचार्य सुनीता बहादुर के करकमलों द्वारा हुई। इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे सैंडविच मैग्गी, मोमोज मंचूरियन, पाव भाजी, गढ़ कलेवा के विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन, गुपचुप चाट, बेल इत्यादि प्रकार के व्यंजनों का लोगों ने बहुत ही चाव से लुफ्त उठाया तथा इसके अतिरिक्त खेल क्षेत्र में भी बहुत से विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के खेल एवं मेहंदी आर्ट का आयोजन किया। इसके साथ ही विद्यालय में सिखाई जाने वाली कला विधि से विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कलात्मक चित्रों को प्रशिक्षण कक्ष में दर्शाया गया। जो अभिभावकों तथा अन्य अतिथियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। इस आयोजन का मुख्य उददेश्य छात्रों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए किया गया। इस आयोजन में अभिभावकों के मनोरंजन हेतु बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगीत भी प्रस्तुत किया गया। कुछ अभिभावक द्वारा भी प्रस्तुति प्रदर्शित की गई। अभिभावकों ने भी इस मेले की सराहना की और कहा कि इस तरह का आयोजन हर वर्ष होना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी विशेष योगदान रहा। इस प्रकार बहुत ही जोरो शोरों से यह आयोजन सम्पन्न हुआ।

शहर में भय और अनिश्चितता का माहौल चरम पर

दल्ली राजहरा के अस्तित्व पर संकट-भय नहीं, समाधान चाहिए

पायनियर संवाददाता ∢ दल्लीराजहरा
www.dailypioneer.com

दल्ली राजहरा को उजड़ने से बचाओः विकास की बात हो, विस्थापन की नहीं दल्ली राजहरा, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और श्रमिक इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय रहा है, अस्तित्व के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। इस नगर के मेहनतकश नागरिकों के सिर पर मकान टूटने का भय मंडरा रहा है। रवि जायसवाल, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में, शहर की इस गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की घोर उदासीनता की कड़ी निंदा करता हूँ।

चहुँ ओर से भय का माहौल-यह सर्वविदित है कि दल्ली राजहरा की लगभग पूरी आबादी या तो बीएसपी की भूमि पर या रेलवे की भूमि पर दशकों से निवास कर रही है। अब स्थिति यह हो गई है कि नागरिकों को नोटिस मिल रहे हैं, जिससे शहर में भय और अनिश्चितता का माहौल चरम पर है- वर्षों से बसे हुए क्षेत्रों को कब्जा हटाने के नोटिस दिए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा विस्तारीकरण परियोजनाओं के लिए आम जनता को नोटिस दिए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को विस्थापित करने की धमकी दी जा रही है। एक ही समय पर इतने सारे नोटिसों का मिलना स्पष्ट करता है कि स्थानीय नागरिकों के स्थायीकरण की इच्छाशक्ति राज्य सरकार में नहीं है।

सरकार से सवाल: विकास या विस्थापन?

यह अत्यंत दुखद है कि जहाँ राज्य सरकार का प्राथमिक कार्य शहरों के सतत विकास की योजनाएँ बनाना होता है, वहीं छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार दल्ली राजहरा के नागरिकों के मन में अनिश्चितता और विस्थापन का डर पैदा कर रही है। क्या नागरिकों को वर्षों से बसे हुए घरों से बेदखल करना ही सुशासन है? जब लाखों लोगों का जीवन इस भूमि से जुड़ा है, तो क्या सरकार के पास पुनर्वास और व्यवस्थापन की कोई ठोस योजना नहीं है? हमारी स्पष्ट मांग है कि भाजपा सरकार भय का माहौल बनाना बंद करे और अविलंब शहर के विकास की योजना बनाए, न कि नागरिकों को उजड़ने का डर दिखाए।

नगर पालिका की सुस्ती अस्वीकार्य

यह बेहद निराशाजनक है कि इस महत्वपूर्ण मुददे पर दल्ली राजहरा नगर पालिका भी पूरी तरह से सुस्त और निष्क्रिय बनी हुई है। स्थानीय निकाय होने के नाते, नगर पालिका का यह नैतिक दायित्व है कि वह नागरिकों के हक के लिए प्रशासन और सरकार के सामने मजबूती से खड़ी हो। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और नागरिकों को आश्वस्त करना चाहिए।

हमारी मांग और प्रस्तावित समाधान

रेलवे, बीएसपी, पीडब्ल्यूडी और शासन द्वारा जारी किए जा रहे सभी बेदखली नोटिसों पर तत्काल रोक लगाई जाए। राज्य सरकार बीएसपी और रेलवे के साथ समन्वय स्थापित कर, वर्षों से बसे हुए नागरिकों के रिहायशी क्षेत्रों की भूमि को नगर पालिका या राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। ऐसे आवासीय क्षेत्रों को नियमित करने के लिए एक विशेष योजना बनाई जाए, जिससे नागरिकों को उनके घर का वैध पटटा मिल सके। नागरिकों को विश्वास में लेने के लिए नगर पालिका स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और समस्या के समाधान हेतु एक साझा रणनीति तैयार की जाए। दल्ली राजहरा के नागरिक डर में नहीं, बल्कि विकास और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी दलों और संगठनों से अपील करते हैं कि वे इस मानवीय मुददे पर एकजुट हों।

प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बार-बार बिल नोटिस एवं डिमांड नोटिस जारी

राजस्व वसूली शत प्रतिशत होनी चाहिए

पायनियर संवाददाता ∢ दल्लीराजहरा
www.dailypioneer.com

मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वारडेकर ने कहा कि राज्य शासन के स्पष्ट निर्देशानुसार राजस्व वसूली शत प्रतिशत होनी चाहिए। राजस्व वसूली कम होगा तो वेतन भुगतान सहित अन्य विकास कार्य लंबित होंगे। दल्ली राजहरा में कुल 27 वार्ड हैं शहर की कुल जनसंख्या 44363 है। जिन से गृहकर, जलकर एवं नगर पालिका द्वारा निर्मित व्यवसायिक परिसर किराया की राशि वसूल की जाती है। नगर के बड़े संपत्ति कर समेकित कर बकायेदारों को चिन्हित किया गया है, जिन पर प्रॉपर्टी टैक्स राशि बकाया है। नगर पालिका ने विगत वर्षों के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बार-बार बिल नोटिस एवं डिमांड नोटिस जारी कर चुका है। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी बकायादारों द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। इन्हें पर्याप्त नोटिस जारी किया जा चुका है। नगर पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक एवं वार्ड प्रभारी के पास बकायादार अपना टैक्स अति शीघ्र जमा करें। इसके बावजूद भी बकायादार राशि जमा नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बकायादारों की सूची तैयार कर नाम सार्वजनिक कर नाम आगामी माह अखबारों में नाम प्रकाशित किए जाने एवं संपत्ति कुर्क करने की योजना प्रस्तावित किया गया है।

25 से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर आमजनों को शीतलहर से सुरक्षा और त्वरित राहत दिलवाने अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर में शीतलहर से आमजनों को सुरक्षा और त्वरित राहत देने नगर पालिक निगम के जोन कार्यालयों के माध्यम से जयस्तम्भ चौक के समीप, रेल्वे स्टेशन के पास, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी, महोबा बाजार हॉट बाजार सहित राजधानी शहर में विभिन्न लगभग 25 से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महादेवघाट रायपुरा और महोबा बाजार हॉट बाजार, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी चंगोराभाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा, शिक्षक कॉलोनी डंगनिया, खमतराई चौक के पास, जयस्तम्भ चौक के पास, रायपुर जिलाधीश परिसर के सामने डॉ भीम राव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल चौक के पास, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर के पास, मोतीबाग, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के समीप, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबाँधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, कुकरीपारा दूधाधारी मठ मार्ग, नगर निगम जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा और अन्य विभिन्न लगभग 25 से अधिक प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में आमजनों को शीतलहर से रायपुर शहर क्षेत्र में सुरक्षा और त्वरित राहत देने सार्वजनिक अलाव जलाने की व्यवस्था दी गयी है। शीतलहर की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है।

जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने मंवली भांठा एवं गोंडगिरी सहकारी समितियों का किया निरीक्षण

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी एक विशेष निरीक्षण दौरे पर सेवा सहकारी समिति मर्यादित मावलीभाठा क्रमांक 384 तथा सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोंडगिरी क्रमांक 385 पहुँचीं। इस दौरान उन्होंने समितियों के कार्यों, धान खरीदी व्यवस्था तथा किसानों को मिल रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान बहन-भाई उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी समस्याएँ खुलकर जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने रखीं। सबसे प्रमुख मुददा धान खरीदी की प्रतिदिन की लिमिट (क्षमता) बढ़ाने का रहा, जिससे किसान लगातार परेशानियाँ झेल रहे थे। किसानों की समस्याएँ सुनकर तुरंत तिवारी ने मौके पर ही संबंधित नोडल अधिकारी से बातचीत की, तत्पश्चात विषय को ऊपरी अधिकारियों तक पहुँचाने हेतु फोन पर चर्चा की। धान खरीदी क्षमता बढ़ाने एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु लेटर एवं ईमेल द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेजा और जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने स्पष्ट कहा कि– किसान हमारी रीढ़ हैं। भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देगी। हर किसान को समय पर धान खरीदी, बिजली, पानी और खाद-बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। गाँव के किसानों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इतने लंबे समय बाद कोई जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को इतनी गंभीरता से सुन रहा है और तत्काल कार्रवाई कर रही है। निरीक्षण के दौरान किसानों के टोकन, तौल व्यवस्था, बोरों की उपलब्धता, कैपेसिटी बिजली-पानी स्थिति का भी परीक्षण किया गया। समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि धान खरीदी कार्य सुचारू और पारदर्शी तरीके से संचालित हो। किसानों के हित में जिला स्तर पर लगातार निगरानी जारी रहेगी। कल्पना योगेश तिवारी ने किसानों को आश्वासन दिया कि हर समस्या का समाधान प्राथमिकता में किया जाएगा और समितियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

आयुर्वेद शिविर में ब्लॉक के 950 मरीजों का उपचार

पायनियर संवाददाता ◄ डोंगरगांव नगर
www.dailypioneer.com

नगर में आयुष स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क रोग निदान आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। शिविर में 950 मरीजों का पंजीयन व उपचार किया गया। शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि बतौर शामिल जिलाध्यक्ष भाजपा कोमल सिंह राजपूत ने आयुर्वेद व आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को हमारे देश की प्राचीन प्राकृतिक महान धरोहर निरूपित किया। शिविर में कोमल सिंह राजपूत ने मुख्यअतिथि बतौर शिरकत की। अध्यक्षता पूर्व जिपंअध्यक्ष दिनेश गांधी ने की। विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मीनारायण गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष तरुण लहरवानी, जिला भाजपा महामंत्री डीकेश साहू, अंजू त्रिपाठी नपँअध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष दीना पटेल, गुलशन हिरवानी, राम कुमार गुप्ता, मंडल महामंत्री हेमंत चोपड़ा सहित नगर के पार्षदगण, समाजसेवी रामकिशन माहेश्वरी व रमेश सोनी, बालकृष्ण सिन्हा शामिल हुए। शिविर को सफल बनाने में शिविर प्रभारी डॉ वर्षा नागवंशी, डॉ. अनिरूद्ध पटेल, डॉ. श्रेयता कुरोठे, डॉ. मधु बंछोर, डॉ. रेखा साहू, डॉ. प्रीति बोरकर, डॉ. खिलेश, फार्मासिस्ट सुनील अग्रवाल, बसंत सिंह राजपूत, अनिल ताम्रकार, सरोजलता देवांगन, सविता कोरेटी, बिसाहू ठाकुर, रूपेन्द्र साहू, त्रिवेणी साहू, सुरेखा बंजारे, विश्वेश्वर सिंह कंवर, भोगराम चंद्रवंशी, सोमकांत चंद्राकर, दीपक कोर्राम, गजेन्द्र ठाकुर, दिलीप भिमटे आदि ने योगदान दिया। इस मौके पर मितानिन सहित जीवनदीप समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

होम्योपैथी व आयुर्वेद से उपचार

शिविर में इस बार लगभग 950 मरीजों का पंजीयन व उपचार किया गया। इनमें लगभग 76 ने नेत्र जांच व 285 ने रक्त परीक्षण भी कराया। होम्योपैथी में कुल 366 मरीजों तथा आयुर्वेदिक में कुल 584 मरीजों का उपचार किया गया। शिविर में अनेक मरीजों को निःशुल्क दवाईयों तथा मालिश तेल आदि का भी वितरण किया गया।

महापौर मीनल ने स्वीकृत विकास कार्यों की अत्यंत धीमी गति को देखकर गहन नाराजगी व्यक्त की

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 7 अंतर्गत स्वामी आत्मानंद वार्ड क्षेत्र अंतर्गत स्वामी आत्मानंद सरोवर (करबला तालाब) में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत 1 करोड़ रूपये की लागत से उद्यान सौंदर्याकरण और 1 करोड 44 लाख रूपये की लागत से रिटेनिंग वाल निर्माण के प्रगतिरत्त नवीन विकास कार्यों का वहाँ पहुंचकर स्थल पर औचक निरीक्षण किया और वहाँ विकास कार्यों की अत्यंत धीमी गति को लेकर अपनी गहन नाराजगी व्यक्त की और मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता पी. राजेश नायडू कार्यपालन अभियंता योजना अंशुल शर्मा सीनियर, जोन 7 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा और कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे को स्वामी आत्मानंद सरोवर में प्रगतिरत विकास कार्यों की नियमित अच्छी तरह सतत रूप में नियमित मॉनिटरिंग करते हुए सभी कार्य जनहित में जनसुविधा की दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण करवाने के निर्देश दिए निरीक्षण के दौरान स्वामी आत्मानंद वार्ड के पार्षद आनंद अग्रवाल, जोन 7 के सम्बंधित अधिकारियों की स्थल पर उपस्थिति रही।

स्वस्थ समाज के संकल्प के साथ रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल्स की 'द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन 2025' में भागीदारी

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ने 'द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन 2025' के 10वें संस्करण में हेल्थकेयर पार्टनर के रूप में गर्वपूर्ण सहभागिता की। यह कार्यक्रम रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल्स के मेडिकल एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. संदीप दवे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. सुशील जैन और डॉ. गिरीश अग्रवाल, जनरल एवं लापरोसकॉपिक सर्जन डॉ. सिद्धार्थ तामस्कर और अनेक डॉक्टरों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और लोगों को फेफड़ों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, फिट जीवनशैली अपनाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस रन में क्षेत्रभर से प्रमुख अतिथियों, डॉक्टरों, खेल जगत से जुड़े लोगों, हजारों धावकों, परिवारों और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वस्थ सांसों और हरित धरती के लिए दौड़ थीम को सशक्त रूप से आगे बढ़ाते हुए रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ने प्रतिभागियों को लगभग 5,000 पौधे वितरित किए, ताकि हर प्रतिभागी अपने साथ स्वच्छ हवा और स्वस्थ भविष्य की जिम्मेदारी का एक छोटा सा बीज घर ले जा सके। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर के मेडिकल एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. संदीप दवे ने कहा, द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन हमारे राज्य की ऊर्जा, एकता और प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। इस वर्ष की थीम 'वाइल्ड छत्तीसगढ़ - रन विथ अ रोअर' ने उस शक्ति, साहस और जोश को खूबसूरती से व्यक्त किया है, जिसके साथ हजारों लोग आज दौड़े। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हमारा मानना है कि स्वास्थ्य सेवा केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदायों को मजबूत बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है।

मां सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय सरोना रायपुर में आनंद मेले का आयोजन किया गया

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

लोक शिशु शिक्षण समिति द्वारा संचालित मां सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय सरोना रायपुर में विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चों द्वारा आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अभिभावक व भैया बहन स्टाफ सम्मिलित हुए। उक्त अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानैश सिंह ठाकुर समाजसेवी सरोना की ओर से की गई, हमारे मार्ग दर्शक गोपी सिंह ठाकुर, वी सी यदु भी उपस्थित रहे, ज्ञानैश सिंह ठाकुर द्वारा निर्मित शेड का उदघाटन समृद्धि सिंह ठाकुर ने किया और स्कूल के बच्चों को समर्पित किया। उक्त अवसर पर विद्यालय की अध्यक्ष इंदु सिंह राजपूत, जया ठाकुर, प्रधानाचार्य भानुमति हरपाल, उमा वर्मा, भुनेश्वरी साहू, मीला यादव, पार्वती साहू, सविता साहू, शोभा तिवारी, कान्ति साहू, पार्वती बंजारे, खिलेश साहू, निर्मल पारख विद्यालय परिवार से रहे। विशेष अतिथि डॉ. अमित पाटकर, राज सिन्हा ने उपस्थित होकर बच्चों द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की व बधाई देकर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के समापन में निदेशक नरेन्द्र सिंह राजपूत ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

रायपुर शहर से निकल रहे दूषित जल को पूर्ण रूप से उपचारित किये जाने के लिए किये जा रहे सतत कार्य

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा कुल 4 स्थानों कमशः ग्राम चन्दनीडीह (क्षमता 75 एमएलडी), ग्राम-कारा (क्षमता- 55 एमएलडी), ग्राम निमोरा (क्षमता- 90 एमएलडी) एवं भांठागांव (क्षमता 06 एमएलडी) इस प्रकार कुल 206 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कर सतत रूप से संचालन किया जा रहा है। इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से रायपुर शहर से निकल रहे कुल 17 नालों, जो कि 6 मुख्य नालों में मिलते हैं, के दूषित जल को एकत्रित कर निरंतर उपचार किया जा रहा है। इसके तहत चिन्गरी नाला, गोवर्धन नाला, सरोना वंडर पार्क नाला एवं अटारी नाला के दूषित जल को चन्दनीडीह में स्थापित 75 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, छोकरा नाला के दूषित जल को निमोरा में स्थापित 90 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में तथा तेंदुआ नाला के दूषित जल को कारा में स्थापित 35 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जाता है। वर्तमान में चन्दनीडीह एसटीपी अपनी कुल क्षमता के 65% क्षमता पर तथा कारा एवं निमोरा अपनी कुल क्षमता के 100% क्षमता पर संचालित हो रहे हैं। निमोरा में औद्योगिक क्षेत्रों से आ रहे अतिरिक्त मात्रा में दूषित जल के उपचार हेतु तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 60 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया गया है। उक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण उपरांत कारा और निमोरा में हो रहे अतिरिक्त दूषित जल के दबाव को कम किया जा सकता है। रायपुर शहर से निकल रहे दूषित जल को पूर्ण रूप से उपचारित किये जाने हेतु सतत कार्य किये जा रहे हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स का इनिशियल पब्लिक ऑफर 12 दिसंबर को खुलेगा

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (कंपनी) अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर में इक्विटी शेयर्स के लिए बिड/ऑफर 12 दिसंबर को खोलेगी और 16 दिसंबर को बंद करेगी। एंकर इन्वेस्टर बिडिंग डेट 11 दिसंबर होगी। यह ऑफर कंपनी के एक प्रमोटर, यानी प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा ऑफर फॉर सेल के जरिए अधिकतम 48,972,994 इक्विटी शेयर्स तक का है। ऑफर में पात्र आईसीआईसीआई बैंक शेयरहोल्डर्स के लिए अधिकतम 2,448,649 इक्विटी शेयर्स का रिजर्वेशन शामिल है (इसे आईसीआईसीआई बैंक शेयरहोल्डर रिजर्वेशन पोर्शन कहा जाएगा)। आईसीआईसीआई बैंक शेयरहोल्डर रिजर्वेशन पोर्शन को घटाने के बाद बचा ऑफर नेट ऑफर कहलाएगा। ऑफर और नेट ऑफर क्रमशः ऑफर के बाद कंपनी के पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 9.91% और 9.41% हिस्सा होंगे। इक्विटी शेयर्स कंपनी के 05 दिसंबर के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के जरिए ऑफर किए जा रहे हैं, जिसे दिल्ली और हरियाणा में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नई दिल्ली (आरओसी) के पास फाइल किया गया है।

आरंभ 2025 : बी.एड. छात्रों के लिए कलिंगा विश्वविद्यालय का भव्य स्वागत समारोह

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर, ने परिसर में नव-नामांकित बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) छात्रों के लिए भव्य स्वागत समारोह आराम्भ-2025 आयोजित किया। यह कार्यक्रम छात्रों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल, परंपराओं और मूल्यों से परिचित कराने के उददेश्य से आयोजित किया गया, जो उनके शैक्षणिक जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक बना। कार्यक्रम की शुरुआत तिलक और आरती जैसे पारंपरिक स्वागत किया गया, जिसमें छात्रों का आत्मीयता से अभिनंदन किया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और दृष्टिकोण को दर्शाने वाली एक प्रेरणादायक वीडियो प्रस्तुति दी गई। उसके उपरांत विशिष्ट अतिथियों के परिचय और स्वागत से हुई, जिसके बाद शिक्षा संकाय की टीम का परिचय कराया गया। स्वागत उदबोधन शिक्षा संकाय की सहायक प्राध्यापक डॉ. सरोज नैयर द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती वंदना की गई, जो ज्ञान की खोज और नई शुरुआत का प्रतीक है। कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति, डॉ. आर. श्रीधर ने प्रेरणादायक स्वागत भाषण के साथ सभा को संबोधित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की दृष्टि, शैक्षणिक संस्कृति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को कलिंगा विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण का पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान, कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संदीप गांधी ने एक रोचक पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं।

स्वास्थ्य विभाग ने पवार सभा भवन संचालक पर तत्काल 2 हजार रुपए का जुर्माना कर प्राप्त जनशिकायत का किया त्वरित निदान

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

रायपुर नगर पालिक निगम में प्राप्त सफाई सम्बंधित जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेकर नगर निगम जोन 5 जोन स्वास्थ्य अधिकारी संदीप वर्मा ने स्वच्छता निरीक्षक प्रेम मानिकपुरी की उपस्थिति में नगर निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन 5 क्षेत्र अंतर्गत न्यू चंगोराभाठा में पवार सभा भवन के बाहर रहवासी क्षेत्र की नाली की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पवार सभा भवन द्वारा भवन के बाहर रहवासी क्षेत्र की नाली में जूठा खाना फेंके जाने से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत सही मिली और इसके कारण वहाँ रहवासी क्षेत्र और मोहल्ले में बदबू फैलने और रहवासियों को इससे असुविधा होने की शिकायत भी सही मिली। इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पवार सभा भवन न्यू चंगोराभाठा के सम्बंधित संचालक को नगर निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग की ओर से जोन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भविष्य में पुनरावृति होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करने की कड़ी चेतावनी देते हुए सम्बंधित स्थल पर तत्काल 2 हजार रूपये का जुर्माना स्थल पर वसूला जाकर नगर निगम को प्राप्त सफाई सम्बंधित जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया।

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन

पायनियर संवाददाता ◄ रायपुर
www.dailypioneer.com

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर के शिक्षा संकाय में एक दिवसीय भव्य खेल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन और औपचारिक उद्घाटन के साथ हुई। मुख्य अतिथियों में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर (डॉ) सौरभ कुमार चतुर्वेदी, शिक्षा संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ अभिषेक श्रीवास्तव, खेल निदेशक डॉ सुमित तिवारी तथा विभागाध्यक्ष डॉ ईश्वर प्रसाद यदु उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें खेल भावना एवं अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा संकाय के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ देते हुए अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ खेल छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन में शिक्षा संकाय के सभी प्राध्यापकों की उपस्थिति और सहयोग सराहनीय रहा। यह आयोजन विश्वविद्यालय में शिक्षा और खेल के संतुलित महत्व को दर्शाता है।

धान बेचने और रकबा समर्पण में रायगढ़ जिला अव्वल, किसानों ने धान खरीदी की पारदर्शिता पर जताया भरोसा

रायगढ़ जिले में रकबा समर्पण बना धान खरीदी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत, अब तक 184.1415 हैक्टेयर रकबा समर्पित

पायनियर संवाददाता ➤ रायगढ़
www.dailypioneer.com

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में रायगढ़ जिले में राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी एक महापर्व के रूप में नजर आने लगी है। जिले के किसानों में इस वर्ष धान विक्रय को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। किसानों को उनके वास्तविक धान उपज की खरीदी में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारू और किसान हितैषी बनाया है। जिले के सभी 105 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी व्यवस्थित रूप से जारी है। धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी स्वयं कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी द्वारा की जा रही है। वे लगातार उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तौल प्रक्रिया पारदर्शी रहे, किसानों को प्रतीक्षा न करनी पड़े, टोकन प्रणाली सुचारू चले, और केंद्रों में बोरे, तौल मशीनें, छाया, पानी आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध रहे। कलेक्टर द्वारा धान के अवैध परिवहन, भंडारण और बिचैलियों द्वारा अमानक धान बेचने जैसी गतिविधियों पर कड़ाई से निगरानी रखी जा रही है। वे प्रतिदिन खरीदी की समीक्षा कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान खरीदी के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इस वर्ष विशेष रूप से उभरकर सामने आई है। जिले के किसान स्वयं प्रेरित होकर अपना शेष रकबा समर्पित कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा केंद्र सरकार के एमएसपी के अतिरिक्त राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाने वाली अंतर राशि को मिलाकर प्रति क्विंटल 3,100 रुपए समर्थन मूल्य तय किया गया है। किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि वास्तविक उपज बेचने के बाद वे अपने शेष रकबे का समर्पण नहीं करेंगे, तो उनके खातों में उपलब्ध शेष स्थान का दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसान आगे आकर स्वयं अपना रकबा समर्पित कर रहे हैं। धान खरीदी शुरू होने से लेकर अब तक जिले में पारदर्शिता की मिसाल पेश करते हुए रायगढ़ जिले में अद्यतन स्थिति के अनुसार कुल 184.1415 हैक्टेयर रकबा समर्पण दर्ज किया जा चुका है। रकबा समर्पण की दृष्टि से रायगढ़ जिला प्रदेश के सर्वाधिक समर्पण करने वाले जिलों में शामिल हो चुका है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक 3,457 सीमांत किसान, 1,987 लघु किसान और 1,737 बड़े किसान धान विक्रय कर चुके हैं। कुल मिलाकर 7,181 किसानों से 3,92,113.60 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। भुगतान की स्थिति भी संतोषजनक है। राज्य शासन द्वारा धान बेच चुके किसानों को 9,204.90 लाख रुपए का भुगतान उनके खातों में अंतरित किया चुका है। इसके साथ ही सहकारी समितियों द्वारा 1,522.19 लाख रुपए की ऋृण वसूली भी की गई है।

धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने किसान कर रहे रकबा समर्पण–रायगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी महापर्व ने नई पहचान बनाई है। किसानों ने अपने वास्तविक उपज की खरीदी के बाद स्वयं आगे आकर 184.1415 हेक्टेयर रकबा का समर्पण किया है, जिससे खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता का स्तर और भी मजबूत हुआ है। जिले के 7,181 किसानों से अब तक 3.92 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है। किसानों को 92.04 करोड़ रुपए का भुगतान तथा 1,522.19 लाख रुपए की ऋृण वसूली की गई है।

रूपडेगा में लैलूंगा पुलिस का जन चौपाल

थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से कियासीधा संवाद, नशाबंदी व घरेलू विवाद पर खुली चर्चा

पायनियर संवाददाता ➤ रायगढ़
www.dailypioneer.com

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रूपडेगा में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में जन चैपाल का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिलाएं-पुरूषों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि शराब के कारण घरों में झगड़े, आर्थिक नुकसान और सामाजिक ताना-बाना बुरी तरह प्रभावित होता है और इसी कारण पुलिस नशाबंदी को लेकर पूरी संवेदनशीलता और सख्ती के साथ कार्य कर रही है। चैपाल में महिलाओं ने घरेलू विवाद, सुरक्षा, महिला उत्पीड़न, यातायात व्यवस्था और युवाओं में बढ़ते नशे जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। थाना प्रभारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आसपास के इलाकों में अवैध शराब बिक्री की शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और गांव में अवैध शराब बेचने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं ने कई स्थानों पर गश्त बढ़ाने की मांग भी रखी, जिसे प्रभारी ने तुरंत नोट कर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी ने छोटी-छोटी बातों पर होने वाली मारपीट को गलत बताते हुए कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों का हश्र हमेशा बुरा होता है, जिससे न केवल आरोपी का भविष्य तबाह होता है बल्कि पूरा परिवार भी टूट जाता है। वहीं गांव के बुजुर्गों ने भी जन चैपाल का समर्थन करते हुए पुलिस की इस पहल की सराहना की और इसे गांव की शांति और सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया।

रायकेरा ग्राम पंचायत में ग्राम संपर्क एवं जागरूकता अभियान का सफल आयोजन

पायनियर संवाददाता ➤ जशपुरनगर
www.dailypioneer.com

यूनिसेफ एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित पाराङ्कसुरक्षित लइकमन 3.0 के अंतर्गत रायकेरा ग्राम पंचायत में ग्राम संपर्क एवं जन-जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व शासकीय संत रामेश्वर गहिरा गुरुजी महाविद्यालय, बगीचा के प्राचार्य शरद कुमार नेताम ने किया तथा समूचे कार्यक्रम की निगरानी एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राजीव रंजन तिग्गा द्वारा की गई। अभियान के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों ने गांव में रैली निकालकर, डोर-टू-डोर संपर्क कर तथा वॉल पेंटिंग के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सामाजिक मुददों पर जागरूक किया। रैली का संचालन प्रवीण मिंज एवं गीतांजलि शर्मा द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए जागरूकता संदेशों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। कायक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा नशामुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जानकारी देना था। इस अवसर पर ग्रामीणों एवं स्वयंसेवकों ने मिलकर शिक्षित समाज, स्वस्थ समाज और नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता के कारण यह अभियान सफ्ल एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ।

ट्रेक्टर की ठोकर से युवक हुआ गंभीर काम करके घर लौटते समय हुई घटना

पायनियर संवाददाता ➤ रायगढ़
www.dailypioneer.com

काम करके घर लौट रहे युवक को ट्रेक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार ठोकर मार दिया। घायल युवक को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कंचनपुर के पास एक और सड़क हादसा सामने आया हुआ। रमन डनसेना पिता स्व महेश डनसेना घरघोड़ी उम्र लगभग 17 वर्ष अपना काम खत्म करके अपनी स्कूटी से घरघोड़ा से अपने घर घरघोड़ी जा रहा था शाम को लगभग सवा 6 बजे के पास टॉवर कंपनी के ट्रेक्टर ने जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दिया। जिससे स्कूटी में सवार रमन डनसेना गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शीयो के बताये अनुसार कंचनपुर में टावर में काम करने वाले ट्रेक्टर ने स्कूटी में सवार नाबालिग युवक को टक्कर मारी जिससे स्कूटी सवार को सिर में गंभीर चोट लगी है। ग्रामीणों ने घटना कि सुचना पुलिस को दी गई पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को घरघोड़ा हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहाँ घायल का इलाज जारी है। घायल रमन को उपचार के लिए रायगढ़ रिफर किया गया है।

भवन निर्माण कार्य हेतु विधायक ओपी की पहल से 37.36 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति

पायनियर संवाददाता ➤ रायगढ़
www.dailypioneer.com

प्रयास आवासीय विद्यालय, रायगढ़ के भवन निर्माण कार्य हेतु विधायक ओपी की पहल से 37.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।आदिवासी अंचलों के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। ये विद्यालय विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली आदिवासी छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन, अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आधुनिक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करते हैं। हर वर्ष इन विद्यालयों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी जेईई, नीट, क्लैट, एनडीए जैसी राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षाओं में चयनित होते हैं। इसी श्रेणी में रायगढ़ जिले के प्रयास आवासीय विद्यालय की सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा भवन निर्माण कार्य हेतु 3736.93 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से विद्यालय में आधुनिक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, डिजिटल शिक्षण संसाधनों, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक अवसंरचना का विकास होगा। साथ ही आवासीय और भोजनालय सुविधाओं के विस्तार से विद्यार्थियों को सुरक्षित, प्रेरक और समग्र शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। प्रयास आवासीय विद्यालय रायगढ़ में नए भवन निर्माण से न सिर्फविद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सुदृढ़ होगी।

रात के सन्नाटे में पकड़ाया अवैध साल लट्ठों से ठसा-ठस भरा ट्रक

ड्राइवर फरार, कार्रवाई से वन माफियों में हड़कंप

पायनियर संवाददाता ➤ रामानुजगंज
www.dailypioneer.com

वन परिक्षेत्राधिकारी निखिल सक्सेना की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संतोष कुमार गुप्ता गाड़ी गैरेज के पास एक संदिग्ध ट्रक लंबे समय से खड़ा है। सूचना की पुष्टि के बाद सर्किल और बीट रामानुजगंज की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची और वाहन क्रमांक सीजी 15 एसी 5057 की जांच की। जांच में पाया गया कि ट्रक में साल लट्ठा अवैध रूप से लोड किया गया था। पूछताछ और खोजबीन के दौरान वाहन चालक मौके से गायब मिला, जिसके चलते टीम ने बिना देर किए ट्रक सहित कुल 21 नग साल लट्ठा मौके पर ही जप्त कर लिया। जप्त सामग्री पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ड), धारा 52, तथा छत्तीसगढ़ वन उपज एवं व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5(1) एवं छत्तीसगढ़ वनोपज अभिवहन नियम 2001 की धारा 41(3) के तहत कार्रवाई की जा रही है। जप्ती की प्रक्रिया के दौरान उप वनक्षेत्रपाल विजय सिंह,वनपाल दयाशंकर सुसन्ना भगत, और वनरक्षक राजनाथ सिंह व पिंटू मालाकार मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई को नियमों के अनुरूप संपन्न कराया। वन विभाग के अनुसार चालक की तलाश की जा रही है और अवैध कटाई व परिवहन के इस प्रकरण में आगे और भी खुलासे हो सकते हैं।

17 दिसंबर पेशनर्स दिवस पर निकलेगा पेंशनर्स सम्मान रैली अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न

पायनियर संवाददाता ➤ रायगढ़
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन प्रांतीय निकाय रायपुर ने सभी जिला शाखाओ को 17 दिसंबर राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी तारतम में जिला शाखा रायगढ़ की आवश्यक बैठक अभियंता भवन रायगढ़ में जिला शाखा अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पेंशनर दिवस आयोजन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में केंद्र सरकार के जारी टी.आर. क्यू. में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है वित्त अधिनियम 2025 में जिस तरह के प्रावधान जोड़े गए हैं, इस पर चर्चा हुई तथा पाया गया कि यह सब सब पेंनशरो के हित विरुद्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा पेंनशरो के जायज हक की अनदेखी की जा रही है, मोदी की गारंटी नहीं लागू की जा रही है इससे पेंनशरो का आर्थिक नुकसान हो रहा है. इन मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई तथा अपनी चिंता से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को अवगत कराने हेतु ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में रेल टिकट में कोरोना अधिभार को समाप्त कर दिया गया है लेकिन नागरिकों को दी जा रियायत को चालू नहीं किया गया है। इस पर आवश्यक कार्यवाही करने तथा रायगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ष्सियान सदनष् बनाए जाने के लिए वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक रायगढ़ ओपी चैधरी एवं महापौर से भेंट करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के अवसर परष् पेंशनर्स सम्मान रैली ष् निकलने का भी निर्णय लिया गया. यह रैली आधुनिक भारत के विकास में योगदान देने वाले पेंशनरों तथा पेंशन भोगियों के अधिकारों एवं सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले डी. एस. नकारा को समर्पित होगा. पेंशनर सम्मान रैली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य सभी संवर्ग के पेंनशरो को आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक पी बाकला अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह सचिव आर. एन. साहू उपाध्यक्ष विष्णु यादव, उपाध्यक्ष साथी के के स्वर्णकार,साथी रवि गुप्ता, साथी यू आर पटेल सहित साथी बी पी घिल्ले,साथी गोकुल प्रसाद पटेल, साथी गणेश मिश्रा, साथी अमृतलाल हिमधर,साथी लक्ष्मी प्रसाद कोंध, साथी रामगोपाल शुक्ला, साथी हिलारियुस लकड़ा, साथी बी आर सोनी, साथी नीलमणि पाणिग्राही, साथी कृष्ण शरण सिंह ठाकुर, साथी समीर कुमार बोस, साथी विद्याधर बरेठ साथी निराकार चैहान आदि पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

एसआईआरः पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों में हुआ बदलाव

अब सत्यापन एवं गणना कार्य 11 दिसम्बर और दावा-आपत्ति 15 जनवरी तक

14 फरवरी 2026 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

पायनियर संवाददाता ➤ मुंगेली
www.dailypioneer.com

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत कार्यक्रम की तिथियों में बदलाव किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार अब 11 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन एवं गणना कार्य किया जाएगा। 16 दिसंबर को मतदाता सूचियों का प्रारूप का प्रकाशन तथा 15 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां ली जायेगी। 07 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य किया जायेगा। इसके उपरांत 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर प्रपत्रों को वापस एकत्र किया जा चुका है और डिजिटाइजेशन कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिले में अब तक 99 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। जिले के मतदाताओं द्वारा अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ, निकटतम निर्वाचन कार्यालय एवं जिला कलेक्टोरेट परिसर में स्थापित हेल्पडेस्क के नम्बर 9406275535 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही एस.आई.आर. से जुड़े कार्यों हेतु जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर 07755-299049 जारी किया गया है। साथ ही आवश्यक समन्वय और शिकायत समाधान के लिए कंट्रोल रूम एवं संबंधी मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर संजय सोनी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर मोहन उपाध्याय एवं जे.एस.ध्रुव सहित जिला स्तरीय तकनीकी दलों की प्रातः 06 से 10 बजे, प्रातः 10 से दोपहर 02 बजे, दोपहर 02 से शाम 06 बजे तक और शाम 06 बजे से रात 10 बजे तक शिफ्टवाइज ड्यूटी लगाई गई है।

ऑपरेशन शंखनाद का पॉजिटिव असर, गौ तस्कर जुड़ा समाज की मुख्य धारा से

एसएसपी मोहन ने पेश की मिसाल: कभी गौ तस्कर रहा बबलू के नए होटल का फीता काट कर नए जीवन की दी बधाई

पायनियर संवाददाता ➤ जशपुरनगर
www.dailypioneer.com

जिले का साईटांगरटोली ग्राम लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों, विशेषकर गौ-तस्करी के मामलों के लिए बदनाम रहा है। इसी ग्राम का निवासी अमजद हजाम उर्फ बबलू (उम्र 40 वर्ष) कई वर्षों से गौ-तस्करी के कारोबार में संलिप्त था। उसके विरुद्ध थाना लोदाम में गौ तस्करी के 03 मामले दर्ज हैं, वह पिछले 08 माह से लगातार पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल, खेल रहा था, अलग-अलग राज्यों में फरारी भी काट रहा था, अंततः जशपुर पुलिस के दबाव में आकर उसे सरेंडर करना पड़ा। अमजद पुलिस की निगरानी में लगातार बना रहा। जशपुर पुलिस की सतत मॉनीटरिंग और सटीक सूचना तंत्र के कारण उसकी गतिविधियों पर लगातार अंकुश लगाया जाता रहा।

एसएसपी सिंह से मुलाकात जिसने बदल दी जिंदगी –अमजद उर्फबबलू के जेल से छूटने के बाद एसएसपी शशि मोहन सिंह ने उसे कार्यालय में बुलाया और समझाया कि अपराध करने के बाद पुलिस से कब तक भागते रहोगे? अपराध का कोई भविष्य नहीं होता। इससे केवल जेल, भय और असुरक्षा मिलती है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी अंधकार में चली जाएँगी। यदि तुम सही रास्ता चुनो तो सम्मानजनक जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इन बातों ने अमजद पर गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव डाला। उसने पहली बार महसूस किया कि अपराध से जुड़े रहने पर न तो स्थायी कमाई संभव है और न ही परिवार का भविष्य सुरक्षित। उसने स्वयं आगे आकर अपराधमुक्त जीवन जीने का वचन लिया और समाज की मुख्यधारा में लौटने का निश्चय किया।

बबलू शंख ढाबा का शुभारंभ–समाज में नई शुरुआत और सम्मानजनक आजीविका के लिए अमजद ने छत्तीसगढ़-झारखंड की सीमा पर अपना नया ढाबा बबलू शंख ढाबा शुरू किया। यह क्षेत्र मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यात्रियों की आवाजाही अधिक रहती है, जिससे उसे स्थायी आय का भरोसा मिला। ढाबा के उद्घाटन के लिए अमजद ने एसएसपी शशि मोहन सिंह को आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। दिनांक 04 दिसंबर 2025 को एसएसपी स्वयं स्थल पर पहुंचे और विधिवत रूप से ढाबा का उद्घाटन किया, इस ढाबा के एसएसपी पहले ग्राहक बने, उन्होंने अमजद के ढाबा से चाय पिया और उसकी कीमत अदा की, साथ ही सफ्ल ढाबा संचालन की बधाई दी। इस दौरान आसपास के ग्रामीण, व्यापारी, पुलिस अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने अमजद के सकारात्मक निर्णय का स्वागत किया और उसे उसके नए जीवन की शुभकामनाएँ दीं। ग्रामीणों को अपराध छोड़ने का संदेश उदघाटन के दौरान एसएसपी ने उपस्थित ग्रामीणों एवं युवाओं को संबोधित करते हुए कहा किः- अपराध कोई विकल्प नहीं है। एक अपराधी अपने परिवार, समाज और स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपराध छोड़कर मुख्यधारा में वापस आना चाहता है तो जशपुर पुलिस उसका हर संभव सहयोग करेगी। यह कम्युनिटी पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

एसएसपी ने युवाओं को सही राह चलने की अपील कियाः- एसएसपी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुये कहा कि पुलिस और समाज मिलकर ऐसे युवाओं को सही दिशा दे सकते हैं, जो किसी कारणवश गलत रास्ते पर चले जाते हैं।

जशपुर पुलिस की सकारात्मक पहल– एसएसपी की इस पहल को जिले में समाज पुनर्वास मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि अपराध की जड़ें काटते हुए लोगों को सुधार के अवसर देना भी है। अम6जद हजाम उर्फबबलू ने कहा कि अब मैं अपराध से हमेशा के लिए दूर रहूंगा। एसएसपी साहब ने मुझे समझाया तब मुझे पहली बार लगा कि जीवन बदल सकता है, अब मैं अपने परिवार का पेट ईमानदारी से पालूंगा। अमजद का अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में बढ़ना न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जशपुर पुलिस का यह कदम जिले में सामाजिक सौहार्द, सकारात्मक परिवर्तन और अपराध मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में

> यह एक तरह से कम्यूनिटी पुलिसिंग का उदाहरण है, जशपुर पुलिस का यह प्रयास जिले में सकारात्मक परिवर्तन, सुधारात्मक दृष्टिकोण और जन-विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, भविष्य में भी इस तरह के पुनर्वास के प्रयास जारी रहेंगे.
> **-शशि मोहन सिंह, एसएसपी जशपुर**

गाइडलाइन दरों में किये गये बड़े जनहितैषी सुधार : ओपी चौधरी

पायनियर संवाददाता ➤ रायपुर
www.dailypioneer.com

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि समग्र छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे है। इसी दिशा में राज्य में लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से सुझाव, ज्ञापन एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिन पर विचार कर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। प्रदेश के वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान, कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया। अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10 प्रतिशत कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपति के लिए भूखंड की दर में 25 प्रतिशत कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है। जिला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनः पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के ये निर्णय दिनांक 8 दिसंबर से प्रभावशील हो गए हैं।

जमीन की गाइडलाइन की दरों में सरकार ने कोई कमी नहीं किया : सुशील शुक्ला

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जमीन की गाइडलाइन की दरों पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी और सरकार जनता से एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं। खुली जमीनों, प्लाटो और किसानों के खेतों के संबंध में जो बेतहाशा बढ़ोत्तरी की गयी है। सरकार ने न उसमें कोई कटौती की है और न ही उसको स्थगित किया है मतबल गाइडलाइन के बढ़े दर यथावत रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने जमीन गाइडलाइन की दरों को बिना जिला मूल्यांकन समिति से प्रस्ताव लिये और बिना दावा आपत्ति कराये अवैधानिक तरीके से लागू किया था, तथा बढ़ी दरों का अनुमोदन केन्द्रीय मूल्यांकन समिति से भी नहीं लिया था। वर्तमान आदेश में सरकार ने सिर्फ अपनी गलती को सुधारने का काम किया है। सरकार बताये 20 नवंबर जब से नई गाइडलाईन लागू की गयी थी, उसके बाद से अभी तक हुई रजिस्ट्री के स्टांप ड्यूटी का क्या होगा सरकार स्पष्ट करे कि 31 दिसंबर तक जब तक दावा आपत्ति मंगाई गई है तब तक बढ़ी दरे लागू होगी या वह गाइडलाइन स्थगित रहेगी? 31 दिसंबर तक होने वाली रजिस्ट्री पर कौन सी दर लागू होगी, सरकार स्पष्ट करें। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सिर्फ बड़े बिल्डरों को राहत देने के लिए बहुमंजिलों, भवनों के फ्लैट, दुकानों की गणना में सुधार किया गया है तथा सम्पूर्ण एफआईआर की गणना को तल के आधार पर 20 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बढ़ी हुई जमीन की दरों में कहीं पर कोई कमी नहीं किया है।

श्री सीमेंट के संडी ब्लॉक जनसुनवाई को तुरंत रद्द करने की मांग

पायनियर संवाददाता ➤ खैरागढ़
www.dailypioneer.com

श्री सीमेंट द्वारा संडी चूना पत्थर ब्लॉक (खनन पटटा क्षेत्र 404 हेक्टेयर) में प्रतिवर्ष 3.64 मिलियन टन चूना पत्थर उत्पादन और कुल 8.991 मिलियन टन उत्खनन क्षमता वाले प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लेकर विधायक यशोदा निलाम्बर वर्मा ने कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता लेकर कहा कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी में कई गंभीर खामियाँ हैं – मशीनरी एवं खनन विधियों के कारण उत्पन्न धूल, शोर तथा भूजल पर पड़ने वाले प्रभावों से बचाव के पर्याप्त उपाय रिपोर्ट में नहीं दिखाए गए हैं। कंपनी का मंशा पत्र मिलने के बावजूद खनन पटटे का निष्पादन-पंजीकरण लंबित है, और सिर्फ 33 हेक्टेयर पंजीकृत होने के बावजूद पूरे 404 हेक्टेयर पर जनसुनवाई कराना अनुचित व अवैधानिक प्रतीत होता है। विधायक ने बताया कि कंपनी की रिपोर्ट में रोजगार लाभ केवल 138 लोगों का दर्शाया गया है, जबकि परियोजना से हजारों एकड़ सिंचित कृषि भूमि प्रभावित होगी और लगभग 20 हजार से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट आ सकता है। विधायक व स्थानीय प्रभावितों ने यह भी बताया कि पर्यावरण-वनस्पति, जल स्तर व सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के लिये आवश्यक सूक्ष्म-मौसम विज्ञान और व्यापक आधारभूत सर्वेक्षण कंपनी द्वारा प्रभावी रूप से नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि मानसून पूर्व और पश्चात भूजल गहराई के मौजूदा आँकड़े (200 फीट तक से नीचे) पहले से ही चिंतनीय हैं और प्रस्तावित खनन के कारण भूतल जल स्तर और गहरा (रिपोर्ट के अनुसार संभावित 800 फीट तक) हो सकता है, जिससे पेयजल व सिंचाई दोनों पर अभूतपूर्व विपत्ति आएगी। विधायक ने शहीद नगरी छुईखदान में हुए हिंसक प्रदर्शन और लगातार जारी किसानों के विरोध को उद्धृत करते हुए 11 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित जनसुनवाई को तत्काल रदद करने और परियोजना के सामाजिक-आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभावों की स्वतंत्र, पारदर्शी एवं विस्तृत समीक्षा कराने की माँग दोहराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जनता न चाहती है तो वे जनता के साथ खड़ी रहेंगी और आवश्यक कानूनी-नागरिक संघर्षों में साथ देंगी। विधायक की अपील में स्थानीय ग्रामों– संडी, पंडरिया, बुंदेली, बिचारपुर, भरदागोंड समेत प्रभावित आसपास के लगभग 30 ग्रामों का उल्लेख है, जिनके निवासियों ने भी भारी असमर्थता व्यक्त की है। प्रेस वक्तव्य में यह तर्क भी रखा गया कि सिंचित कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर खनन उद्योग स्थापित करने की अनुमति सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अनुचित है और कुछ न्यायालयी निर्देशों व नीतियों के परिप्रेक्ष्य में भी विवादास्पद हो सकती है। विधायक ने कलेक्टर और राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय किसानों व ग्रामीणों की चिंताओं को गंभीरता से लें, माहौल शान्त करने तथा संवेदनशील जनहित को सुरक्षित रखने हेतु प्रस्तावित जनसुनवाई रदद कराते हुए परियोजना के सभी पहलुओं की स्वतंत्र समीक्षा कराने का निर्देश दें।

राष्ट्र के लोकतंत्र के मंदिर में बस्तर के विकास पर हुई चर्चा : कश्यप

पायनियर संवाददाता ➤ रायपुर
www.dailypioneer.com

लोकसभा में चर्चा के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बस्तर क्षेत्र के युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाया। उन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे से प्रश्न करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) जैसी राष्ट्र निर्माण से जुड़ी योजनाओं को बस्तर के दूरस्थ, वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि वहां के युवा भटकाव से बचकर मुख्यधारा में लौट सकें और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। बस्तर सांसद कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, किंतु बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे एनएसएस के माध्यम से स्थानीय युवाओं को शिक्षा, कौशल और स्वयंसेवा से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी केंद्र सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में कार्यरत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों की संख्या, उनके प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण तथा निगरानी व्यवस्था से संबंधित विवरण मांगा। साथ ही इस योजना को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों की जानकारी भी सदन में मांगी।

रजिस्ट्री मे 90 प्रतिशत की गिरावट इस नये नियम की विफलता का सबूत है : विकास उपाध्याय

पायनियर संवाददाता ➤ रायपुर
www.dailypioneer.com

बिजली बिल मामले में भी पहले 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ योजना को बंद कर दिया जनता के विरोध को देखते हुए सरकार ने यू टर्न लिया पर सिर्फ 200 यूनिट बिजली बिल हॉफ किया। फिर जमीन पंजीयन की गलत गाईड लाईन को जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपकर जनता को हलाकान करने का काम राज्य की बीजेपी सरकार कर रही है, जब इस गाईड लाईन का जमीन पर विरोध हो रहा है उसको देखते हुए फिर राज्य की साय सरकार ने महज खानापूर्ति संशोधन कर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। भाजपा नेताओं ने भारत माला योजना में जैसे सरकारी खजाने को खाली करने का काम किया, ठीक वैसे ही ये नई गाईड लाईन भाजपाई नेताओं और मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। ज्ञात हो कि जब से ज़मीन गाइड मे वृद्धि हुई है तब से किसान, व्यापारियों से लेकर आमजन काफी परेशानी की स्थिति मे है। इसलिये पंजीयन समस्या निवारण संघ के राजीव गाँधी चौक पर हुये महाधरना कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन प्राप्त हुआ, इस कार्यक्रम मे कांग्रेस के तमाम नेतागण ने अपनी उपस्थिति दर्ज की साथ ही भाजपा सरकार के इस जनविरोधी नियम की कड़ी आलोचना की। इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करते करते हुये बताया कि इस नये नियम के अनुसार आम जनता के घर, मकान, दुकान के प्रॉपर्टी टैक्स में भारी वृद्धि होगी जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ा है और जनता पर आर्थिक संकट आने का संकेत मिल रहा है।

लोकतांत्रिक ढांचे में कैग की सर्वोच्च भूमिका : रमेन डेका

पायनियर संवाददाता ➤ रायपुर
www.dailypioneer.com

महालेखाकार कार्यालय के आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डेका ने अपने उदबोधन में कहा कि लेखा परीक्षा केवल सरकारी व्यय और राजस्व की जांच तक सीमित नहीं है, यह प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, और जनसेवा में उत्तरदायित्व का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की सर्वोच्च भूमिका है। राज्यपाल रमेन डेका प्रधान महालेखाकार कार्यालय में ऑडिट पखवाड़ा 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर 20 नवम्बर से 8 दिसंबर तक यह सप्ताह आयोजित किया गया। राज्यपाल डेका ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसकी नीव ब्रिटिश शासन के दौरान 1858 में प्रारंभ हुई लेखा परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संस्था की महत्ता को समझते हुए इसे संवैधानिक प्राधिकरण का दर्जा प्रदान किया। डेका ने कहा कि तेजी से बढ़ते डिजिटल प्रशासन के दौर में कैग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यह संस्था केवल कमियों को उजागर नहीं करती, बल्कि प्रशासनिक सुधार, नवाचार एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है। यह न केवल सरकारी कार्यों में वित्तीय अनुशासन लाने का कार्य करता है, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने का महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाता है।

अमित बघेल को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बता दें कि अमित बघेल जब सरेंडर के लिए देवेंद्रनगर थाने पहुंच रहे थे तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। फिर कोर्ट में पेश किया था, जहां से तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। रिमांड खत्म होने पर अमित बघेल को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी। इसका विरोध करते हुए समाज के लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ रायपुर समेत कई जिलों और दूसरे राज्यों में एफआरआई दर्ज कराई थी।

सीरप की बोतल में संदिग्ध वस्तु मिलने का मामला, जांच के लिए नमूने को भेजा गया राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला

पायनियर संवाददाता ➤ रायपुर
www.dailypioneer.com

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवपुरी में कैल्सिड सीरप की एक बोतल के भीतर मांस जैसा पदार्थ पाए जाने संबंधी जानकारी विभाग को मिली थी। उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा तत्काल जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई। रायपुर जिले की संयुक्त जांच टीम के द्वारा संबंधित कैल्सिड सस्पेंसन 200 एमएल, बैच नं. एलजीई 4061, एम/डी 05/2024, ई/डी 04/2026 निर्माता एक्टिनोवा प्राइवेट लिमिटेड, बददी, हिमाचल प्रदेश का विधिवत नमूना संग्रहण किया गया। संग्रहित नमूनों को आगे की गुणवत्ता की जांच हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होते ही अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दिशा निर्देश के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के औषधि निरीक्षकों के द्वारा प्रदेश स्तर पर औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश मे सतत् कार्यवाही की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ जन-सामान्य से अपील करता है कि किसी भी संदिग्ध औषधि संबंधी सूचना से हेल्पलाईन नंबर +91-9340597097 पर तत्काल विभाग को अवगत कराएं। ताकि समय पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जा सके।

SHRI BALAJI INSTITUTE OF PHARMACY AND RESEARCH CENTRE, RAIPUR

Affiliated by CSVTU and PCI

Shri Balaji Institute of Pharmacy and Research Centre invites the applications for the following posts.

PRINCIPAL	- 01
ASSISTANT PROFESSOR	- 04

In the discipline of Pharmaceutical Sciences Qualification : Experience and Pay scale as per CSVTU and PCI norms. Interested and eligible candidates can/may send their resume along with the relevant testimonial and passport size photograph within 7 days of this advertisement.

email : sbp.raipurcg@gmail.com, hrsbp.raipur@gmail.com

Shri Balaji Institute of Pharmacy and Research Centre, Mowa Raipur

Contact : 0771-4241057, 98271-18884, 99261-36950

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक भोजराम पटेल द्वारा आसमा पब्लिसर्स इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड पीएनबी के सामने जयस्तंभ चौक रायपुर, छत्तीसगढ़ से मुद्रित तथा श्री बालाजी हॉस्पिटल कैम्पस (मोवा) रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001 से प्रकाशित संपादक-अच्युतानन्द द्विवेदी*
समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार, डाक पंजीयन नं. छ.ग./रायपुर संभाग/97/2024-26, दूरभाष नंबर 0771-2972403